R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 09
01 से 15 फरवरी 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

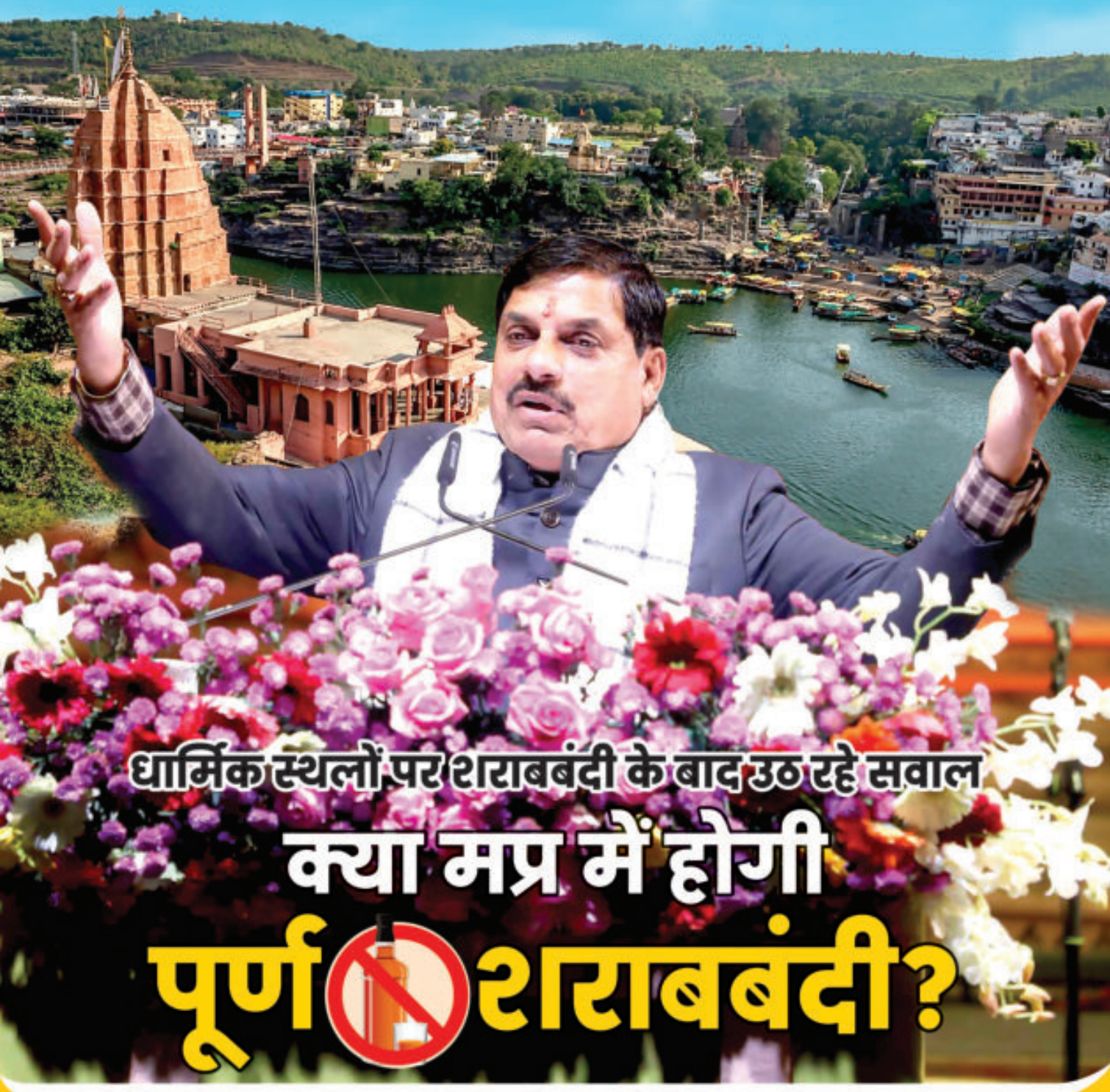

धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के बाद उठ रहे सवाल

क्या मप्र में होगी पूर्ण शराबबंदी?

जो काम उमा, शिवराज और कमलनाथ नहीं कर सके, उसे मोहन यादव ने कर दिखाया

उज्जैन में शराबबंदी के बाद उठा सवाल... काल भैरव को भोग में कैसे चढ़ेगी शराब?

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

विकास

9 | जापान से आएगा बड़ा निवेश

मप्र में जापान की कई बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मुझे खुशी है कि जापान की बड़ी कंपनियां मप्र में आकर अपने व्यवसाय और व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

डायरी

10-11 | बैठक में फरमान...

अपनी कर्त्तव्यपरायणता और ईमानदारी के लिए ख्यात 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन मुख्य सचिव बने तो अफसरों में विश्वास जगा कि उनकी प्रतिभा का अब ठीक से उपयोग होगा। लेकिन मामला...

उपलब्धि

13 | मॉडल जिला बना मंडला

इस समय किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए नए-नए नवाचार किए जा रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इस दिशा में मप्र का मंडला जिला अन्य जिलों के लिए मॉडल बना है।

राजपाट

15 | माननीय बनने बढ़ रही बेकरारी

मप्र में सरकार बने 13 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों की आस लगाए बैठे भाजपा नेताओं की मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद नेताओं को दर्जा मंत्री बनाने का सपना दिखाया गया। इसके लिए नेताओं ने सत्ता, संगठन...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में शराबबंदी की मांग दशकों से हो रही है। इस दौरान प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने केवल वादे किए हैं। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी कर दी है। यानि जो काम पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं कर सके उसे डॉ. मोहन यादव ने कर दिखाया। सरकार के इस कदम की सर्वत्र सराहना हो रही है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या गुजरात और बिहार की तरह मप्र में भी पूर्ण शराबबंदी होगी।

सियासत

32-33 | वजूद की जंग

कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, जैसा उसने 2013 में किया था। कांग्रेस का आक्रामक रुख 2015 के विधानसभा चुनावों में भी रहा, लेकिन आप की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के बुलंद इतिहास...

महाराष्ट्र

35 | अपराध-मुक्त नहीं हो पा...

मायानगरी मुंबई दुनिया के हरेक इंसान को अपनी चमक-दमक और काम-धंधे के लिए अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहां की ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें, सपनों जैसी हॉलीवुड की दौलत-शोहरत वाली दुनिया और सदाबहार मौसम को कौन इंज्वाय नहीं करना चाहता। पर जैसे इस एक दुनिया के...

बिहार

38 | पीके की पॉलिटिक्स

बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर बिहार विधानसभा उपचुनावों में उतरे प्रशांत किशोर (पीके) अपनी जन सुराज पार्टी की करारी हार के बाद युवाओं का कंधा तलाश रहे हैं। बीपीएससी में कथित पेपर लीक-धांधली में उनकी छलांग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-09, पृष्ठ-48
1 से 15 फरवरी, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

महाकुंभ से सबक...सिंहस्थ होगा बेहतर

हमारे पुराणों में लिखा है...

मेषराशिगते सूर्ये सिंहराशयां वृहस्पतौ।
उज्जयिन्यां भवेत कुम्भः सर्वसौख्य विवर्द्धनः।।

यानी जब सूर्य मेष राशि में एवं वृहस्पति सिंह राशि में जाते हैं तब उज्जयिनी में सभी के सुखदायक कुंभ योग आता है। चूकि वृहस्पति सिंह राशि पर रहते हैं इसलिए सिंहस्थ कुंभयोग के नाम से यह प्रसिद्ध है। इस बार 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ अद्भुत सामाजिक समागम है, इससे समाज की दिशा तय होती है। पहले लोग कुंभ के मेले में तय हुई दिशा को लेकर जाते थे और समाज में बदलाव के लिए काम करते थे। समय के साथ परंपराओं में बदलाव आया है, किंतु हमें अपनी जड़ों और मूल्यों के महत्व को समझना होगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित सिंहस्थ की तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं। कुंभ केवल एक मेला ही नहीं, अपितु विश्व को परंपराओं के नवोन्मेष की शिक्षा व संदेश देने वाले शानदार प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है। इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं और आधुनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। प्रयागराज महाकुंभ से सबक लेते हुए मप्र ने सिंहस्थ को बेहतर बनाने के प्रयास अभी से शुरू कर दिए हैं। इस बार सिंहस्थ की तैयारियों में आधुनिक तकनीक और व्यवस्थित प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। सिंहस्थ 2028 में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि व्यवस्थाएं आधुनिक, सुगम और श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। विशाल जनसमूह के लिए बुनियादी ढांचे, परिवहन, सुरक्षा और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर काम हो रहा है। विकास और अधोसंरचना के काम शुरू किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकल्प लिया है कि सिंहस्थ-2028 में श्रद्धालुओं को क्षिप्रा नदी के निर्मल जल में ही स्नान कराया जाए और क्षिप्रा नदी में स्वच्छ एवं शुद्ध जल का प्रवाह सदा के लिए सुनिश्चित कर उसे सही अर्थों में पुण्य-सलिला और सदानीरा बनाया जाए, साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहे। संकल्प की पूर्ति के लिए उज्जैन में सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी, कान्ह क्लोज डक्ट एवं हरियाखेड़ी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं और 18 बैराज एवं स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं। इससे क्षिप्रा नदी में पूरे वर्ष निर्मल जल प्रवहमान रहेगा, साथ ही उज्जैन को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। सिंहस्थ आयोजन के दौरान परिवहन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए दूसरे संसाधनों के साथ ही रेलवे अधिकारियों के साथ सतत् समन्वय के लिए एक विशेष सेल स्थापित किया जाएगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ तक पहुंचने का मार्ग सुगम किया जा सकेगा। विशेष मार्गों का विकास भी किया जाएगा, ताकि यातायात प्रवाह का बेहतर प्रबंधन किया जा सके और पीक-ट्रैफिक के दौरान बॉटल-नैकिंग की समस्या उपस्थित न हो सके। मेला क्षेत्र के लिए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, जल आपूर्ति, सीवेज लाइनें, बिजली, उद्यान आदि के निर्माण की योजना बनाई गई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण लैंड-पूलिंग योजना का उपयोग करते हुए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। यहां अखाड़ों, आश्रमों और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगीं। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सिंहस्थ में भीड़ और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार उज्जैन शहर में 13 नए ब्रिज बनाएगी। इनमें 8 ब्रिज क्षिप्रा नदी पर बनेंगे। 5 रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। सभी का निर्माण पूरा करने की मियाद 31 दिसंबर 2027 रखी गई है। यह फैसला प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं और भीड़ की स्थिति का अध्ययन करने के बाद लिया गया है।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

परीक्षा फीस की मार

कर्मचारी चयन मंडल हर परीक्षा के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों से 500 रुपए तो रिजर्व कैटेगरी के छात्रों से 250 रुपए एग्जाम फीस लेता है। हवा उड़ रही है कि एग्जाम फीस में 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसे में छात्र कैसे अधिक फीस भरेंगे, यह चिंता का विषय है।

● **गीरेंद्र सेन,** रायसेन (म.प्र.)

बिजली बिल का करंट

मप्र में ऐसे करीब 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन पर 50 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डालने की तैयारी हो रही है। मासिक खपत 151 से 300 यूनिट के भीतर रहती है। ऐसे उपभोक्ताओं को भी अब फ्लैट रेट पर बिल भरना होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

● **रिंकी पांडे,** मधुसूदनगढ़ (म.प्र.)

आदिवासियों पर फोकस

मप्र में सत्ता की चाबी आदिवासी मतदाताओं के हाथों में है, यह अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि पिछले कई चुनावों के परिणामों का विश्लेषण बताता है। आदिवासी वर्ग ने भाजपा की चिंता बढ़ाई हुई है। यही एक वजह है कि भाजपा ने पेसा पर अपना फोकस बढ़ाया है। अन्य राज्यों के चुनावों में भी ये बड़ा वोटबैंक है।

● **पायल सोनी,** खुजनेर (म.प्र.)

नक्सलियों से राहत कब?

केंद्र सरकार ने अगले कुछ सालों में देश को नक्सलमुक्त करने का ऐलान किया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार हो रहे प्रहार से उनकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब कार्रवाई से बचने के लिए नक्सली मप्र के जंगलों में अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर मप्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की 2 बटालियन की मांग की है। मप्र के बालाघाट, डिंडौरी, मंडला में नक्सलियों का नया कैडर तैयार किया जा रहा है।

● **जगदीश मीणा,** बिल्रचीपुर (म.प्र.)

आस्था का महाकुंभ

महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से साधु-संतों समेत 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में दुनियाभर के संत-साधु व भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

● **शिवम भदौरिया,** राजगढ़ (म.प्र.)

दिल्ली चुनाव में बंट रहीं रेवड़ियां

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियां अपने-अपने दांव चल रही हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी दलों ने भर-भरकर घोषणाएं की हैं। महिलाओं, युवाओं, गरीबों से लेकर आम आदमी तक के लिए सभी पार्टियों ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान कर दिया है। आप ने बुजुर्गों को लेकर संजीवनी स्कीम का ऐलान किया है। आप का दावा है कि सरकार बनी तो 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने-अपने घोषणा पत्रों में दिल्लीवासियों को भरपूर रेवड़ियां बांटी हैं। अब जनता किसे जिताती है, देखना दिलचस्प होगा।

● **अमीन शेख,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

भाजपा के बगलगीर होंगे शरद

महाराष्ट्र के सत्ता गलियारों में इन दिनों खास किस्म की उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। कहा-सुना जा रहा है कि शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार आपसी मतभेद-मनभेद भुलाकर एक होने जा रहे हैं। चर्चा जोरों पर है कि अजित पवार की मां आशा पवार ने परिवार में एकता के लिए एक बड़ा अनुष्ठान गत दिनों किया। इसके तुरंत बाद ही अजित पवार की पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को भगवान का दर्जा देते हुए कहा है कि यदि दोनों पवार एक होते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। जानकारों का मानना है कि दोनों परिवारों के एकीकरण का प्रयास महाराष्ट्र भाजपा के एक बड़े नेता के इशारे पर किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा को 8 लोकसभा सांसदों और 10 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा। कहा यहां तक जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो शरद पवार की पुत्री सुप्रिया पवार को केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का मानना है कि सीनियर पवार अब अपनी एकमात्र संतान सुप्रिया सुले के भविष्य की बाबत सोच रहे हैं और उनका उद्देश्य सुप्रिया के राजनीतिक भविष्य को मजबूती देना है। इस कारण यदि जरूरत पड़ी तो वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से नाता तोड़ एनडीए का हिस्सा बनने में हिचकिचाएंगे नहीं।

महायुति का हिस्सा बनेगी एमएनएस

देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत भाजपा नेता आशीष शेलार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले इस चुनाव में महायुति का नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। यहां तक कहा सुना जा रहा है कि महायुति गठबंधन में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) शामिल हो सकती है। गौरतलब है कि महायुति में भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। मुंबई में पिछले 25 सालों से बीएमसी में उद्धव ठाकरे की पार्टी का कब्जा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को हराने के लिए उसे एक ठाकरे ब्रांड की जरूरत है, इसलिए उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे को भाजपा गठबंधन में लाने की कोशिश में जुटी है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव ठाकरे अकेले लड़े और उनकी पार्टी खाता खोलने में भी नाकामयाब रही। इस झटके के बाद अब राज ठाकरे गठबंधन का रास्ता ढूंढ रहे हैं। राज ठाकरे मराठी माणूस के मुद्दे से लेकर हिंदुत्व तक का एजेंडा चलाते आए हैं।

घर वापसी करेंगे पवन!

बीते दिनों भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह का जन्मदिन लखनऊ में जोर-शोर से मनाया गया। उप्र के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत कई सांसद और भाजपा विधायक जन्मदिन के इस आयोजन में शामिल हुए और पवन सिंह को बधाई दी। भाजपा से लोकसभा टिकट ठुकराने के बाद पवन सिंह को जन्मदिन पर भाजपा के नेताओं के बधाई देने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह घर वापसी करने जा रहे हैं। असल में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पांच जनवरी को पवन सिंह ने अपने प्रशंसकों के बीच जन्मदिन मनाया। यहां राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा भी देखने को मिला। कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पवन सिंह को पगड़ी पहनाकर जमकर तारीफ की तो मनोज तिवारी ने पवन सिंह को छोटा भाई बताते हुए बधाई गीत गाए। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी पवन को जन्मदिन की बधाई दी। इन शुभकामनाओं के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं पवन सिंह ने भी सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

दिल्ली चुनाव में नुपुर की एंट्री

दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होना है, वहीं नतीजे 8 फरवरी को जारी होंगे। एक ओर जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कुछ ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच खबर है कि बीजेपी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है। यहां तक चर्चा है कि नुपुर को कालकाजी सीट से टिकट मिल सकता है। सोशल मीडिया पर उनके नाम को लेकर कैम्पेन चल रहा है। वहीं कई लोगों ने तो उनको सीएम फेस बनाने की मांग भी कर डाली है। असल में पार्टी ने कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री आतिशी पर विवादित बयान के बाद पार्टी के कालकाजी से उम्मीदवार बदलने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा ने 2022 में एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी।

भाजपा का दामन थामेंगी शर्मिष्ठा!

हाल ही में हुई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनकी याद में कांग्रेस की ओर से समाधि की मांग की गई है। लेकिन इस बीच सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए पहले समाधि बनाने का फैसला लिया है और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। बिना किसी मांग के सरकार द्वारा समाधि बनाने के फैसले पर खुशी जताते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इसके लिए आभार जताया। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि शर्मिष्ठा भाजपा में शामिल हो सकती हैं। वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पिता के सम्मान के बाद बेटी शर्मिष्ठा को भी भाजपा कुछ देगी? यह चर्चा तब से शुरू हो गई थी जब से शर्मिष्ठा ने कांग्रेस के ऊपर हमला शुरू किया। यहां तक चर्चा थी कि दिल्ली में भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारेगी। मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि दिल्ली में भाजपा से चुनाव लड़ना अब भी जोखिम भरा है।

खुदा मेहरबान तो...

प्रदेश में भले ही नौकरशाहों के बीच अंतर नजर नहीं आता है, लेकिन कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जिसमें प्रमोटी और आरआर के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में सामने आया है, जब एक आरआर वाले आईपीएस अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के एक पड़ोसी जिले की कप्तानी के दौरान एक आईपीएस अधिकारी अपनी आशिकी के कारण चर्चा में रहे। साहब आशिकी में इस कदर बदनाम हो गए कि उनकी शिकायत चारों तरफ होने लगी। साहब की आशिकी की खबर जब ऊपर तक पहुंची तो इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। सूत्रों का कहना है कि साहब के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी एक एडीजी स्तर के अधिकारी को दी गई। एडीजी ने अपनी जांच में साहब को दोषी पाया और रिपोर्ट सरकार को भेज दी। सरकार के पास शिकायत पहुंचने के बाद शिकायतकर्ता को उम्मीद थी कि कप्तान साहब के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ने उन पर मेहरबानी दिखाते हुए उन्हें चेतावनी देकर दोषमुक्त कर दिया। इसे कहते हैं जब खुदा मेहरबान तो... बंदा पहलवान हो जाता है। यहां बता दें कि साहब 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। शादीशुदा होने के बाद भी उनका यह प्रेम विभाग की ही एक महिला अधिकारी से चल रहा था।

जाते-जाते माल बटोर ले गए

ग्वालियर-चंबल अंचल में पदस्थ एक युवा आईएएस अधिकारी अपनी पदस्थापना के बाद से ही कमाई में इस कदर जुट गए कि उनकी शिकायत सरकार तक पहुंच गई। साहब ने कमीशनखोरी के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। यही नहीं सूत्रों का कहना है कि जब साहब का तबादला हुआ तो उन्होंने जाते-जाते माल बटोरने के लिए सारी हदें पार कर लीं। गौरतलब है कि 2018 बैच के उक्त आईएएस अधिकारी एक नगर निगम में कमिश्नर की कुर्सी संभाल रहे थे। उन्होंने निगम में होने वाले कामों के लिए बकायदा कमीशन की रकम तय कर रखी थी। जो ठेकेदार भरपूर कमीशन देता था, उसे साहब काम देते थे। सूत्रों का कहना है कि बिल्डरों-ठेकेदारों से साहब ने इतना कमीशन बटोरा कि जाते-जाते उन्होंने कमीशन की दरें कम कर रिकार्डतोड़ वसूली की। सूत्रों का कहना है कि जिससे साहब ने 10 लाख रुपए मांगे थे और पूरी रकम लेने पर अड़े हुए थे, तबादले की सूची जारी होते ही साहब ने उसे फोन लगाकर मोलभाव करना शुरू कर दिया और 10 लाख की जगह 4 लाख रुपए लेने को भी तैयार हो गए। कमीशनखोरी की साहब की इस नीति की प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में खूब चर्चा हो रही है।

मंत्रीजी से कुछ भी करा लो...

प्रदेश सरकार में एक मंत्री ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे जो चाहो वह काम करा लो। मालवा-निमाड़ क्षेत्र से आने वाले इन मंत्रीजी को अधिकारी अपने-अपने तरीके से साध लेते हैं। बताया जाता है कि मंत्रीजी के विभाग में एक मामले की जांच चल रही थी। जिसके खिलाफ जांच चल रही थी, वह एससी कैटेगिरी का था। उक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र देना था। बताया जाता है कि जब मंत्रीजी के पास इससे संदर्भित फाइल पहुंची तो उन्होंने आरोप पत्र वाली नोटशीट पर लिख दिया कि यह व्यक्ति अनुसूचित जाति का है। ऐसे में इसे आरोप पत्र से मुक्त रखा जाए। मंत्रीजी का यह तर्क पढ़कर और सुनकर दूसरे अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी कुछ इसी तरह काम करते हैं। आलम यह है कि विभाग के अधिकारी उनसे इसी तरह के काम करा रहे हैं। जिसको देखकर लोग कहने लगे हैं कि ये ऐसे मंत्रीजी हैं, जिनसे कुछ भी करा लो। यहां यह बता दें कि मंत्रीजी के पास प्रदेश सरकार के हिसाब-किताब वाले विभाग के साथ ही एक कमाऊ विभाग की जिम्मेदारी है। मंत्रीजी के आसपास ऐसे अधिकारियों ने घेरा डाल रखा है, जो मंत्रीजी को तरह-तरह के सपने दिखाकर अपना हित साध रहे हैं। यहां बता दें कि मंत्रीजी एक माफिया के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद पहले से ही विवादों में फंसे हुए हैं। ऊपर से उनके अधिकारी-कर्मचारी उनसे उटपटांग काम करवा रहे हैं।

सोम का उज्जैन से मोहभंग

प्रदेश के सबसे बड़े शराब ग्रुप का महाकाल की नगरी से मोहभंग हो गया है। बताया जा रहा है कि ग्रुप ने उज्जैन में डिस्टलरी लगाने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि सोम डिस्टलरी का देश के कई राज्यों में शराब का कारोबार है। रायसेन जिले में ग्रुप की एक डिस्टलरी है। सूत्र बताते हैं कि ग्रुप ने महाकाल की नगरी उज्जैन में एक नई डिस्टलरी लगाने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसकी शासन-प्रशासन से कई स्तरों पर चर्चा हो चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि यहां डिस्टलरी खुलेगी और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अचानक ही सोम ग्रुप ने अपना मन बदल लिया। सूत्र बताते हैं कि सोम की डिस्टलरी उज्जैन में स्थापित करने के लिए उच्च स्तर पर प्लान बनाया गया था। इस प्लान के तहत इसमें कुछ लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी भी होनी थी। बताया जा रहा है कि हिस्सेदारी के मसौदे से सोम ग्रुप सहमत नहीं था। इसलिए उन्होंने उज्जैन में डिस्टलरी लगाने से मुंह मोड़ लिया। अगर उज्जैन में डिस्टलरी लगती तो सरकार को बड़ा निवेश मिलता।

कानून पर कौन भारी ?

महाकौशल क्षेत्र के खनिज संपदा से भरे एक जिले के विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो में माननीय चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, अब गुंडों को भी टैक्स दे देंगे। सत्तारूढ़ पार्टी का होने के बाद भी अगर किसी माननीय को यह बात कहनी पड़ रही है कि वाकई में मामला गंभीर है। यह वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर जिले में ऐसा कौन गुंडा है, जो कानून-व्यवस्था पर भी भारी पड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि खनिज संपदा के कारण व्यवसायियों में स्पर्धा बनी रहने के कारण यह जिला हमेशा संवेदनशील बना रहता है। बताया जाता है कि जिले में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी भी कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की बजाय दूसरे कामों में लगे रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि विधायक जी की व्यथा यह है कि न तो उनकी और जनता की पुलिस सुन रही है, और न ही सरकार। जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, जो संगठन के नेताओं और एक स्थानीय विधायक की करीबी होने के कारण किसी और को भाव नहीं दे रही हैं।

मप्र में बनेंगे 10 लाख आवास

मप्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत हो गई है। इस योजना में प्रदेश के जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए 10 लाख आवास बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन हितग्राहियों को दिया जाएगा, जिन्हें किसी कारण से अब तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर मैदानी अमले को निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के आवेदन संबंधी जानकारी नजदीकी नगरीय निकायों से प्राप्त की जा सकती है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने यूनीफाइड वेब पोर्टल पर भी जानकारी अपलोड की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 4 प्रकार के घटक शामिल किए गए हैं। हितग्राही आवेदन करते समय अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुसार घटक का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में देश में एक करोड़ आवास और मप्र में 10 लाख आवास बनाए जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में विशेष वर्गों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इनमें पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार शामिल हैं। मप्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब तक 8 लाख 25 हजार जरूरतमंद हितग्राहियों के आवास निर्माण पूरे किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में 9 लाख 45 हजार आवास स्वीकृत किए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रथम चरण के क्रियान्वयन की संपूर्ण अवधि में मप्र देशभर में अग्रणी स्थान पर है। योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मप्र और प्रदेश की कई नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए केंद्र का हिस्सा और राज्य की अनुदान राशि 19 हजार 700 करोड़ रुपए और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम घटक के लिए ब्याज अनुदान के रूप में 3 हजार 900 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल राशि 23 हजार 600 करोड़ रुपए स्वीकृत की जा चुकी है। हितग्राहियों को अब तक 22 हजार 800 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

मप्र सरकार युवा, किसान, गरीब और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन चलाने जा रही है। इसमें महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण मिशन का ड्राफ्ट भी सरकार ने तैयार कर लिया है। इसके तहत महिलाओं के लिए मप्र सरकार पक्का मकान बनाकर देगी। पहले चरण में मप्र में ऐसे 15,650 वन और टू बीएचके मकान बनाकर देगी। वहीं वर्किंग वीमेन के लिए ब्लॉक स्तर पर हॉस्टल बनाएंगे। जिससे महिलाएं जहां नौकरी कर रही हैं, उसके पांच से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने लायक पक्का मकान मिल सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विकासखंड स्तर पर वन और टू बीएचके मकान बनाए जाएंगे। तैयार ड्राफ्ट के अनुसार हर ब्लॉक में ऐसे 10 वन बीएचके और 40 टू बीएचके मकान बनाए जाएंगे। इसमें वन बीएचके बनाने का खर्च 20 लाख रुपए और टू बीएचके मकान बनाने का खर्च 35 लाख रुपए होने की संभावना है। अधिकारियों का अनुमान है कि हर विकासखंड में ऐसे मकान बनाने के लिए करीब 16 करोड़ और प्रदेश के 313 विकासखंडों में करीब 5 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।

सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर 50 कमरों का वीमेन हॉस्टल बनाएगी। इसके तहत पूरे प्रदेश में 313 वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। प्रत्येक हॉस्टल को बनाने में 6 से 7 करोड़ रुपए और 313 हॉस्टल बनाने में 1900 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस हॉस्टल में स्टडी टेबल-कुर्सी वार्डरोब अलमारी, अटैच टॉयलेट और अन्य सुविधाओं सहित कमरे होंगे। कामकाजी महिलाएं लड़कियां अपनी आवश्यकता और बजट अनुसार सिंगल महिला, दो महिला एवं तीन महिलाओं के ठहरने वाले कमरों का चयन कर यहां रह सकती हैं। इनमें बच्चों के लिए डे-केयर रूम होंगे। हॉस्टल में कॉमन किचन और डाइनिंग हॉल की सुविधा होगी। कम से कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाला दोनों टाइम का भोजन, नाश्ता, चाय भी उपलब्ध कराई जाएगी। मप्र सरकार विकासखंड स्तर पर डे केयर सेंटर बनाने की तैयारी में भी है। ये डे-केयर सेंटर उन बच्चों के लिए बनेगा, जिनके माता-पिता दोनों कामकाजी हैं और काम के सिलसिले में पूरे दिन बाहर रहते हैं। ये डे-केयर सेंटर शाम तक खुले रहेंगे। इन डे-केयर सेंटर में बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ब्लॉक स्तर पर एक डे-केयर सेंटर बनाने और उसके संचालन में सरकार को हर साल करीब साढ़े पांच लाख रुपए खर्च करने होंगे। इस तरह पूरी योजना में करीब 17 करोड़ खर्च होने की संभावना है।

● **कुमार राजेंद्र**

अब तक 8 लाख 25 हजार आवास निर्माण पूरे

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब तक 8 लाख 25 हजार आवास निर्माण पूरे किए जा चुके हैं। योजना के पहले चरण में 9 लाख 45 हजार आवास स्वीकृत किए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पहले फेस को पूरा करने के मामले में मप्र देशभर में अग्रणी स्थान पर है। इसके लिए मप्र और प्रदेश की कई नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.50 लाख आवास मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट की 12 नवंबर की बैठक में इस पर सहमति दी जा चुकी है। इसमें बताया गया था कि मप्र के ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास ग्रामीण 2.0 के तहत 3.50 लाख मकान बनाए जाएंगे। एक मकान के लिए डेढ़ लाख रुपए की सरकारी मदद मिलेगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों का कहना है कि गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को आवास की जरूरत है। पहले चरण में जो मंजूरी मिली है, उसके बाद और टारगेट भेजे जाएंगे। गांवों में आवास बनाने डेढ़ लाख रुपए की मदद दी जाएगी।

जापान से आएगा बड़ा निवेश

मप्र में जापान की कई बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मुझे खुशी है कि जापान की बड़ी कंपनियां मप्र में आकर अपने व्यवसाय और व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मप्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से उत्पादों को न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसका लाभ जापानी कंपनियों को तो मिलेगा ही साथ ही प्रदेश में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पैनासोनिक और ब्रिजस्टोन जैसी कंपनियों सहित जापानी निवेशकों ने मप्र में निवेश के लिए सहमति जताई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी 4 दिवसीय जापान यात्रा के दौरान व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के उद्योग, संस्कृति और तकनीक को करीब से समझने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का वातावरण बदल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान में कई बौद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की परंपरा है। जापान की बौद्ध संस्कृति भगवान सूर्य और गौतम बुद्ध से भी जुड़ी हुई है, जिससे हमें अपनी साझा विरासत को समझने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जापानी कंपनियां निवेश के फैसले लेने में बेहद सतर्क रहती हैं और गहन अध्ययन एवं शोध के बाद ही आगे बढ़ती हैं। जापान यात्रा के दौरान हमने जिन प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कि सभी ने सकरात्मक रूख अपनाते हुए मप्र में निवेश करने की बात कही। उन्होंने बताया कि रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़े उद्यमियों से भी चर्चा हुई, जिन्होंने मप्र में निवेश की संभावना को लेकर रुचि दिखाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान की बुलेट ट्रेन में सफर किया और इसकी उन्नत तकनीक की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना की बात कही है। ऐसी ही अन्य परियोजनाओं पर काम हो रहा है। जापान की सहायता से भारत में भी भविष्य में इसी तरह की अत्याधुनिक रेल परियोजनाओं को साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापानी लोगों की मेहमान नवाजी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि जापान के लोग न केवल अपने देश से प्रेम करते हैं, बल्कि भारत के प्रति भी उनके मन में विशेष सम्मान और आत्मीयता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान में भारतीय दूतावास और वहां के अधिकारियों का आभार जताया।

जापान-मप्र के बीच संबंध होंगे और अधिक प्रगाढ़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जापान और मप्र के बीच सांस्कृतिक और औद्योगिक संबंध पहले से ही सुदृढ़ हैं। इन्हें और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम तलाशे जा रहे हैं, जिससे पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जापान की ऐतिहासिक संरचनाओं और उनके संरक्षण के अनुभव से सीखकर मप्र के पर्यटन और धरोहर स्थलों के विकास में नवाचार लाया जा सकता है। उन्होंने इस दौरे को प्रदेश के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा मप्र और जापान के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई देने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान यात्रा के चौथे दिन क्योटो स्थित विश्व प्रसिद्ध किंकाकूजी (स्वर्ण मंदिर) का भ्रमण किया। पारंपरिक जापानी स्थापत्य और बौद्ध संस्कृति का प्रतीक यह मंदिर अपनी सोने की परतों से ढंकी भव्य संरचना और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया और जापानी संस्कृति में इसकी ऐतिहासिक महत्ता को करीब से समझा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदिर के सामने स्थित क्योकाची तालाब के किनारे कुछ समय बिताया, जहां मंदिर का प्रतिबिंब एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें सिर्फ स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं होतीं, बल्कि वे एक सभ्यता की आत्मा को दर्शाती हैं। जापान ने अपनी संस्कृति को सहेजने का जो प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जापान यात्रा सिर्फ सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने जापानी धरोहर संरक्षण, पर्यटन विकास और वास्तुकला के नवाचारों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मप्र भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है और जापान से इस दिशा में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जापान यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश के साथ सांस्कृतिक और औद्योगिक संबंधों को भी और अधिक सशक्त बनाना है। भ्रमण के दौरान उन्होंने जापान की परंपरागत और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की नीति को भी सराहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान दौरे के चौथे दिन क्योटो में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को समझने और मप्र के साथ संभावित सहयोग के नए अवसरों पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से प्रसिद्ध निजो-जो कैसल, शेंजुशेंगेन्डो और टोजी टेम्पल का भ्रमण कर दर्शन किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्योटो स्थित निजो-जो कैसल का अवलोकन किया, जो जापान की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर और स्थापत्य कला का प्रतीक है। उन्होंने इस दौरान जापान की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसके प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को भी जाना। इसके साथ ही, उन्होंने शेंजुशेंगेन्डो मंदिर में दर्शन किए, जो अपनी अनूठी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।

● **रजनीकांत पारे**

बैठक में फरमान... खुद कर रहे सारे काम

अपनी कर्त्तव्यपरायणता और ईमानदारी के लिए ख्यात 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन मुख्य सचिव बने तो अफसरों में विश्वास जगा कि उनकी प्रतिभा का अब ठीक से उपयोग होगा। लेकिन मामला उलटा पड़ गया है। हो यह रहा है कि मुख्य सचिव लगभग रोजाना अफसरों के साथ घंटों मीटिंग कर रहे हैं और तरह-तरह के निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन सारे काम खुद निपटा रहे हैं। दरअसल, मुख्य सचिव मप्र के मूल निवासी हैं और उनकी पूरी कोशिश यह है कि मप्र के लिए बनने वाली कोई भी योजना-परियोजना या नीति पूरी तरह फुलप्रूफ हो। इसलिए वे सारे काम खुद करने में जुट जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव के ऐसा करने से अफसरों में अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है। दरअसल, जब भी कोई नीति बनानी होती है, मुख्य सचिव अफसरों के साथ बैठक कर घंटों उसकी बारीकियां समझाते हैं और बाद में उक्त काम को खुद करने में जुट जाते हैं।

अफसरों का कहना है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। पूर्व में जो भी मुख्य सचिव रहे हैं, वे दिशा-निर्देश देते थे और सारे काम हम लोग करते थे। लेकिन अब मुख्य सचिव खुद काम में जुट जाते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे वे समझ रहे हैं कि हम लोगों को कुछ आता-जाता नहीं है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और उद्यमियों के लिए जीवन और व्यवसाय को आसान बनाना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि न्याय की प्रक्रिया इतनी सरल हो कि आम नागरिक और व्यापारी बिना किसी परेशानी के अपने काम कर सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस विधेयक को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाया है। उनका मानना है कि इससे न केवल शासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मप्र में निवेश और रोजगार के अवसरों में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्य में विकास और सुशासन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। इसमें 13 तरह के एक्ट हैं। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों इस बिल पर चर्चा के लिए मुख्य सचिव ने अफसरों के साथ मीटिंग की, ताकि विधेयक का ठीक से अनुपालन हो सके। यह मीटिंग एक-दो दिन नहीं, बल्कि 5 दिन तक चली। मीटिंग में विभागों ने कहा कि समय पर जानकारी न देने या काम न करने वाले विभागों के अफसरों पर 3 से 5 हजार रुपए का दंड लगाने का प्रावधान किया जाए। अफसरों की यह बात मुख्य सचिव को नहीं जची और उन्होंने कहा कि कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। आलम यह रहा कि 5 दिन की बैठक के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि किसी मुद्दे को लेकर पहली बार ऐसी बैठक हुई है। मुख्य सचिव लगातार घंटों बैठकें ले रहे हैं। विगत दिनों टूरिज्म नीति को लेकर घंटों बैठकें हुईं। उन्होंने अफसरों को इस नीति के संदर्भ में कई बातें बताईं, लेकिन बैठक का परिणाम निल बट्टा सन्नाटा रहा। बताया जा रहा है कि अफसरों को ज्ञान देने के बाद मुख्य सचिव ने अब खुद टूरिज्म नीति को बनाया।

अफसरों का कहना है कि मुख्य सचिव का काम अफसरों से काम करवाना होता है, न कि खुद करना। दरअसल, मुख्य सचिव की जिस तरह की कार्यप्रणाली अभी तक सामने आई है, उससे अफसर यही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है उनको किसी पर विश्वास नहीं है। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव विभाग की गलतियां बताकर अपने सामने अधीनस्थों को कमतर समझते हैं। इसलिए खुद काम करते हैं, किसी से करवाते नहीं हैं। अफसरों को अब भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर होने वाली बैठक का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव इस समिट की तैयारियों को लेकर अफसरों की बड़ी बैठक करने वाले हैं। यह बैठक कितने दिन तक चलेगी, इस पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि अफसरों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन जल्द ही मुख्य सचिव इसको लेकर बड़ी बैठक करेंगे और विभागीय अफसरों को दिशा-निर्देश देंगे।

16 एसएएस अफसर एक साथ बनेंगे आईएएस

मप्र में राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के 16 अफसरों को एक साथ आईएएस अवॉर्ड किया जाएगा। सरकार की मंशा अब एक साथ सभी को पदोन्नति देने की है। इसके लिए केंद्र की अनुमति का इंतजार है। यह अवार्ड वर्ष 2024 और 2025 के लिए किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मार्च में यह डीपीसी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मप्र में राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए पिछले साल होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो पाई थी। अब इस साल दो वर्षों 2024 व 2025 की डीपीसी एक साथ की जाएगी। इस डीपीसी में राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नत किया जाएगा। सीट का निर्धारण करने के बाद पदोन्नति का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। वहां से सहमति मिलते ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक एसएएस के वर्ष 2008 बैच के अफसरों को वर्ष 2024 में आठ पदों पर आईएएस में पदोन्नत किया जाना था। किंतु मप्र संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रस्ताव भेजने में देरी होने के कारण यूपीएससी ने इस डीपीसी के लिए समय पर तारीख तय नहीं की। इस वजह से पूरा वर्ष निकल गया और डीपीसी नहीं हो पाई। इसके साथ ही वर्ष 2024 में आईएएस बनने का सपना संजोए बैठे एसएएस अफसरों को निराशा हाथ लगी।

सुखबीर फिर आएंगे पीडब्ल्यूडी में

प्रदेश में एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। संभावना जताई जा रही है कि 1997 बैच के आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह एक बार फिर लोक निर्माण विभाग में स्थापित होंगे। सिंह वर्तमान में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के पद पर हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए 2-3 अफसरों का नाम दिल्ली भेजा गया है। इनमें शोभित जैन और संजीव झा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग में पूर्व की पदस्थापना के दौरान सिंह ने जिस तरह बेहतर काम किया है, उससे सरकार एक बार फिर उन्हें लोक निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव बना सकती है।

मिश्रा रिटायर, मुखर्जी बने एसीएस

अपर मुख्य सचिव गृह, जेल और परिवहन शिवनारायण मिश्रा 31 जनवरी को रिटायर हो गए। उनके स्थान पर इन विभागों के लिए नए प्रशासनिक चीफ की तलाश मोहन सरकार कर रही है। प्रदेश के सभी प्रमुख विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद गृह, जेल और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बनने के बाद ही इसके आदेश जारी होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रालय स्तर पर सीनियर अफसरों के विभागों में बदलाव और पदस्थापना के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। मिश्रा के रिटायर होने के बाद रिक्त होने वाले अपर मुख्य सचिव पद पर राज्य शासन ने दिल्ली में पदस्थ आवासीय आयुक्त अनिरुद्ध मुखर्जी को एसीएस पद पर प्रमोट कर उनकी पदस्थापना दिल्ली में उसी पद पर रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुखर्जी को प्रमोशन का लाभ एक फरवरी 2025 से मिलेगा। वहीं अक्षय कुमार सिंह भी 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं।

बिना अधिकार कर दी रजिस्ट्री

प्रदेश की राजनीति में करीब 14 माह पहले तक कद्दावर मंत्रियों में शुमार एक पूर्व मंत्री के कहने पर सब रजिस्ट्रार पांडे जी ने बिना सोचे-समझे एक भूखंड की रजिस्ट्री कर दी। जबकि रजिस्ट्री करने का अधिकार डीआर गुप्ता जी को था। जब मामला उजागर हुआ तो सब रजिस्ट्रार ने कहा कि डीआर गुप्ता जी के कहने पर ऐसा किया गया है। फिर भी इस मामले में पांडे जी को सस्पेंड कर दिया गया। अब सब रजिस्ट्रार को बहाल कराने के लिए पूर्व मंत्री हाथ-पांव मार रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नए मंत्री भी इस कोशिश में लगे हैं कि पांडे जी को बहाल कर दिया जाए।

सेलवेंद्रन को करना होगा इंतजार

जिस तरह से अपर मुख्य सचिव का पद रिक्त होने पर सीनियर अधिकारी को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोट कर दिया जाता है, उसी तरह का प्रमोशन सचिव से प्रमुख सचिव पद वाले अधिकारियों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नियम प्रमोशन में रुकावट बनने लगा है। दरअसल डीओपीटी ने नियम जारी किए हैं कि 25 साल की सेवा पूरी किए बगैर कोई भी आईएएस अफसर प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोट नहीं हो सकता। इसी नियम के चलते अनिरुद्ध मुखर्जी के प्रमोट होने के बाद प्रमुख सचिव का पद रिक्त होने के बावजूद सचिव कार्मिक एम. सेलवेंद्रन प्रमुख सचिव नहीं बन पाएंगे। उन्हें इसके लिए 11 माह का इंतजार करना होगा। सेलवेंद्रन 1 जनवरी 2026 को प्रमुख सचिव पद पर प्रमोट होंगे। 2025 में रिक्त होने वाले कुल छह एसीएस के पदों पर प्रमुख सचिव के रूप में काम करने वाले आईएएस तो एसीएस बनते जाएंगे लेकिन प्रमोशन पाने वाले प्रमुख सचिवों के रिक्त पदों को 1 जनवरी 2025 की स्थिति में ही भरा जा सकेगा।

● राजेंद्र आगाल

मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर कमलनाथ बोले-

'27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर मेरी सरकार का निर्णय सही...'

मप्र हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के फैसले पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा- मप्र हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मप्र के ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाईकोर्ट के फैसले ने मेरी तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मप्र सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए। कमलनाथ ने आगे लिखा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है। अगर पिछले 6 साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। मार्च 2019 में मेरी तत्कालीन सरकार ने प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया। 19 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया। यहां उल्लेखनीय है कि स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों के लिए था। ओबीसी के 27 प्रतिशत रिजर्वेशन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जुलाई 2019 में मेरी सरकार ने विधानसभा से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का कानून भी पास कर दिया था।

भरत यादव-लवानिया को नई जिम्मेदारी

म प्र में सरकार आगामी वर्षों के लिए प्रशासनिक जमावट करने लगी है। इसके तहत 27 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में 42 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए। आदेश में मुख्यमंत्री के दो सचिव को भी इधर से उधर किया गया है। 12 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान यात्रा पर जाने से पहले तबादले को हरी झंडी दी। आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अपनी टीम नहीं बना पा रहे। पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री को अपने सचिवालय में ही कई अफसरों के तबादले करने पड़े। मुख्यमंत्री के सचिव भरत यादव को हटाकर मप्र सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इसी तरह अपर सचिव से प्रमोट होकर पिछले माह सीएम सचिवालय में सचिव बनाए गए अविनाश लवानिया को भी वहां से हटाते हुए एमडी पावर मैनेजमेंट कंपनी बनाया गया है। सिबि चक्रवर्ती एम को मुख्यमंत्री का सचिव तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

12 जिलों के कलेक्टर बदले

गुना, खरगोन, डिंडौरी, सीहोर, सतना, बड़वानी, टीकमगढ़, रायसेन, खंडवा, श्योपुर, देवास और बुरहानपुर जिले के कलेक्टर बदले गए हैं। गुना कलेक्टर सतेंद्र सिंह को एमडी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बनाया गया है। उनकी जगह श्योपुर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को गुना कलेक्टर बनाया गया है। खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को आयुक्त सह संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति बनाया गया है। उनकी जगह बुरहानपुर की कलेक्टर भव्या मित्तल को खरगोन का नया कलेक्टर बनाया गया है। नेहा मारव्या सिंह को डिंडौरी जिला का कलेक्टर बनाया गया है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह को संचालक लोक स्वास्थ्य बनाया गया है। उनकी जगह बाला गुरु के को सीहोर का नया कलेक्टर बनाया है। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को एमडी, राज्य भंडार निगम बनाया गया है। उनकी जगह सतीश कुमार एस को सतना का नया कलेक्टर बनाया है। बड़वानी कलेक्टर डॉ. फटिंग राहुल हरिदास को आयुक्त, मप्र गृह निर्माण बनाया गया है। उनकी जगह गुंचा सनोबर को बड़वानी कलेक्टर बनाया गया है। टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा को ओएसडी, सह-आयुक्त तकनीकी शिक्षा बनाया गया है। उनकी जगह विवेक श्रोत्रिय को टीकमगढ़ जिला का कलेक्टर बनाया गया है। रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे को अपर सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनकी जगह अरुण कुमार विश्वकर्मा को रायसेन कलेक्टर बनाया गया है। खंडवा के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बनाया गया है। उनकी जगह देवास के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को खंडवा जिले की कमान दी गई है। डिंडौरी के कलेक्टर हर्ष सिंह को बुरहानपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। ऋतु राज, सीईओ, भोपाल जिला पंचायत को देवास का कलेक्टर बनाया गया है। दमोह के जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा को श्योपुर का कलेक्टर बनाया गया है।

एसीएस और पीएस की होगी नई पदस्थापना

42 आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद जल्द ही प्रदेश में एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है। इस प्रशासनिक फेरबदल में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना की जाएगी। उप सचिव से लेकर सचिव स्तर के आईएएस अफसरों के थोकबंद तबादलों के बाद मप्र सरकार जल्द एक और प्रशासनिक सर्जरी करेगी। इस प्रशासनिक फेरबदल में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना की जाएगी। सीएम सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच प्रारंभिक दौर की चर्चा हो चुकी है। उधर, आईएएस अफसरों के तबादलों के बाद आईपीएस अफसरों के तबादलों की तैयारी तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जापान से वापस आने के बाद आईपीएस अफसरों के तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि आईपीएस अफसरों की पहली तबादला सूची में आधा दर्जन से अधिक जिलों के एसपी बदले जाएंगे। वहीं जिलों में पदस्थ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के भी तबादले किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रशासनिक और पुलिस विभाग के मुखिया की पदस्थापना के बाद सरकार अब नए सिरे से आईएएस और आईपीएस अफसरों की जमावट कर रही है। इस क्रम में अभी तक सबसे अधिक आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अब सरकार आईपीएस अफसरों के तबादले करेगी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के बाद आईपीएस अफसरों की नए सिरे से पदस्थापना की जाएगी।

नेहा मारव्या को मिली कलेक्टरी

देवास कलेक्टर बनाए गए ऋतुराज सिंह लंबे समय से कलेक्टरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उनके बैच के अधिकांश आईएएस कलेक्टर बन चुके हैं। दूसरी ओर उन्हें भोपाल जिला पंचायत सीईओ बने करीब ढाई साल हो गया था। आखिरकार उन्हें कलेक्टरी मिल ही गई। वहीं लंबे समय से कलेक्टरी का इंतजार कर रही 2011 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या सिंह को भी आखिरकार कलेक्टरी मिल गई है। वर्तमान में सरकार 2015 बैच के आईएएस अफसरों को कलेक्टरी दे चुकी है। लेकिन, नेहा मारव्या को इसका मौका नहीं मिल पा रहा था। पिछले माह आईएएस सर्विस मीट के पहले दिन आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन के ग्रुप में नेहा ने अपना दर्द जाहिर किया था और यह बात मीडिया में भी आई थी। अब नेहा मारव्या को डिंडौरी कलेक्टर पदस्थ किया गया है। वहीं शासन ने चार जिला पंचायतों के सीईओ भी बदले हैं। इसमें दतिया जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेम्रवाल, अमन वैष्णव नीमच, डॉ. नेहा जैन सीहोर, कमलेश कुमार भार्गव मुरैना के जिला पंचायत सीईओ बनाए गए हैं। ग्वालियर नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव की जगह संघ प्रिय को ग्वालियर निगमायुक्त बनाया है। इस तबादला आदेश में हाउसिंग बोर्ड में आयुक्त की जिम्मेदारी डॉ. फटिंग राहुल हरिदास और आजीविका मिशन के सीईओ का जिम्मा हर्षिका सिंह को सौंपा है।

● सुनील सिंह

मॉडल जिला बना मंडला

पीएम जनमन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए मंडला की राष्ट्र स्तर पर हुई सराहना

विगत दिनों भारत मंडपम नई दिल्ली में पीएम जनमन डीएम/डीसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश के 18 राज्यों के विशेष पिछड़ी जनजातीय जनसंख्या वाले जिलों को शामिल किया गया। मप्र से मंडला सहित अन्य 12 जिलों ने इसमें हिस्सा लिया। पीएम जनमन अंतर्गत बेहतर कार्ययोजना और क्रियान्वयन के लिए चिन्हित जिलों को प्रस्तुति के लिए चुना गया। मप्र की ओर से इस हेतु मंडला जिले का प्रस्तुति हेतु चयन किया गया। जिले की ओर से कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा पीएम जनमन अंतर्गत शत-प्रतिशत प्रगति के लिए तैयार कार्ययोजना और उसके क्रियान्वयन के लिए सतत् चरणबद्ध अनुश्रवण प्रक्रिया की विस्तृत प्रस्तुति की गई। इसके अंतर्गत जिले में पीएम जनमन आवास को शीघ्र पूरा कराने हेतु किए गए नवाचार जैसे सामग्री प्रबंधन, राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण, जिले में बनी प्रदेश की पहली पीएम जनमन आंगनबाड़ी का निर्माण और लोकार्पण के लिए मंडला की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। कॉन्फ्रेंस के पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों को मंडला जिले की तरह कार्ययोजना बनाकर कार्य करने का सुझाव दिया गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए मंच से मंडला जिले को बधाई दी गई।

इस समय किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए नए-नए नवाचार किए जा रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इस दिशा में मप्र का मंडला जिला अन्य जिलों के लिए मॉडल बना है। क्योंकि यहां के कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले में मिशन नेत्र ज्योति, मिशन सुरक्षा, रेवा पथ और स्मृति सुमन शिविर जैसे नवाचारों का सफल क्रियान्वयन कर जिले को विकास का मॉडल बना दिया है।

गत दिनों मंडला में जिला योजना भवन से पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने मिशन नेत्र ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 6 से 18 साल के स्कूली बच्चों और 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों की आंखों की जांच कर इलाज किया जाएगा। यह अभियान केंद्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है। जिसे देश के दो जिलों मंडला (मप्र) और वाराणसी (उप्र) में शुरू किया गया है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के करीब 2 हजार स्कूलों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों की आंख की जांच कर चश्मे वितरित किए जाएंगे। साथ ही 45 साल से अधिक आयु के 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की भी जांच की जाएगी।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने मिशन नेत्र ज्योति पायलट प्रोजेक्ट योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दृष्टि दोष का शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग हेतु मंडला जिले का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों और नागरिकों की आंखों की जांच के उपरांत चश्मे का वितरण किया जाएगा। शासकीय, अशासकीय स्कूल के बच्चों और नागरिकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों के नेत्रों की जांच स्कूलों में और 45 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्तर पर शिविर लगाकर नेत्र परीक्षण किया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीएचओ और एएनएम के द्वारा सोमवार, बुधवार, गुरूवार और शनिवार को स्क्रीनिंग की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार तथा हाट बाजारों में भी नेत्र विशेषज्ञ सहायकों के द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्तर पर जांच के लिए शैक्षिक संगठन, गैर सरकारी संगठन सहित जिला एवं जनपद स्तर पर वृहद नेत्र स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

वहीं मंडला में मिशन सुरक्षा, जीवन अनमोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। दरअसल, मंडला जिले में बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय बन रहे हैं। बीते वर्षों के आंकड़ों को देखें तो जिले में प्रतिवर्ष 800 हादसों में करीब 250 लोगों की असमय मौत हो गई। इसे देखते हुए अब जिला प्रशासन मिशन सुरक्षा (जीवन अनमोल है) के माध्यम से दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि मिशन सुरक्षा का उद्देश्य जन जागरूकता और सबकी सहभागिता से सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करना है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन में हेलमेट नहीं पहनने और चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाना दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है। इसके अलावा तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भी हादसों की वजह बनता है। उन्होंने कहा कि मिशन सुरक्षा (जीवन अनमोल है) के तहत ट्रैफिक मित्रों के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली जाएगी। स्कूल-कॉलेज में रोड सेफ्टी कमेटी का गठन, यातायात मित्र, ड्राइविंग ट्रेनिंग कार्यक्रम सहित यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएंगे।

वहीं मंडला के माहिष्मती घाट में स्थित रपटा पुल (छोटा पुल) का सांसद निधि से कायाकल्प कर पाथवे निर्माण और रेवा पथ नामकरण किया गया है। नर्मदा नदी के रपटा (छोटे) पुल से पैदल यात्रियों का आवागमन होता है। साथ ही यहां इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिला, युवा और सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा आते हैं। साथ ही इस पुल से स्कूली छात्र, मजदूर, तीर्थ यात्रियों का पैदल आवागमन बना रहता है। लेकिन बारिश के बाद इस पुल में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे इस वजह से आमजन को परेशानी हो रही थी। गत दिनों जिले में स्मृति सुमन शिविर में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। जिले में किए जा रहे इन कार्यों की सर्वत्र सराहना हो रही है।

● अरविंद नारद

हर 150 किमी पर बनेगा एयरपोर्ट

छह और एयरपोर्ट विकसित करने की प्लानिंग

प्रदेश में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। हाल में रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। अब छह और एयरपोर्ट विकसित करने की प्लानिंग है। यह सतना, दतिया, उज्जैन, शिवपुरी, नीमच और सिंगरौली में बनाए जाएंगे। सभी शहर धार्मिक या औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, प्रदेश में अभी 27 एयर स्ट्रिप है। कुछ का लंबे समय से उपयोग नहीं हो रहा था। ऐसे में स्थिति खराब हो गई थी। ऐसे में विमानन विभाग ने इनके विस्तार और बेहतर बनाने की योजना बनाई। इस पर अमल किया जा रहा है। सरकार निजी हवाई पट्टियों का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसमें दमोह में डायमंड सीमेंट, शहडोल में ओरियंट पेपर मिल और नागदा में ग्रेसिम सीमेंट की स्ट्रिप शामिल है।

मप्र सरकार एविएशन के नक्शे पर राज्य को अहम दर्जा दिलाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार इसके लिए नई पॉलिसी बना रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बन सकेंगे। एयरपोर्ट विकसित कर यहां अंतरराज्यीय उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही राज्य की हवाई पट्टियों का भी विकास किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन और उद्योग की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मप्र की नई विमानन पॉलिसी में इन बातों पर विचार किया जा रहा है।

मप्र में अब जिला और ब्लॉक स्तर पर भी हवाई यातायात उपलब्ध होगा। प्रदेश में कई नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जो कि पीपीपी मोड पर तैयार किए जाएंगे। जल्द ही हर 200 किमी पर हवाई अड्डा दिखाई देगा। इसके साथ ही हर 150 किमी पर एक हवाई पट्टी भी बनेगी। प्रदेश में फिलहाल 6 एयरपोर्ट हैं और 31 जिलों में हवाई पट्टी भी है। धार्मिक पर्यटन और बड़े शहरों में यात्रियों की सुविधा के लिए पीएमश्री हवाई सेवा संचालित की जा रही है। अब राज्य सरकार नई विमानन नीति (एविएशन पॉलिसी) बना रही है। इसमें हवाई सेवाओं के विस्तार पर फोकस किया जा रहा है। नई पॉलिसी के तहत प्रदेश का लोक निर्माण विभाग कई एयरपोर्ट बनाएगा। विकासखंड स्तर पर हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। प्रदेशभर की सभी हवाई पट्टियों को जेट विमानों की उड़ान के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। सरकारी हवाई पट्टियों के साथ ही सार्वजनिक संगठनों और प्राइवेट हवाई पट्टियों को भी विकसित किया जा रहा है। यहां से छोटे विमान संचालित किए जाएंगे। इसके लिए विमानन विभाग और पर्यटन विभाग की चर्चा हो चुकी है।

मप्र रेल नेटवर्क के लिहाज से सेंटर में है। रोड कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। अब प्रदेश के हर क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए एयर स्ट्रिप (हवाई पट्टियों) की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह इस तरह विकसित की जाएंगी कि कहीं से भी एक घंटे में एयर स्ट्रिप तक पहुंचा जा सके। इसका फायदा उद्योगों, निवेश को बढ़ावा देने के साथ आपात स्थिति में भी मिल सकेगा। एयर कनेक्टिविटी सुधरने से सफर में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। राज्य की नई विमानन नीति के मसौदे में यह प्रस्तावित किया गया है। इसे अगले महीने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। ध्यान देने लायक बात यह है कि मोहन सरकार हर क्षेत्र और वर्ग की पहुंच विमानों तक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। फिलहाल प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत कम दूरी की उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, छोटे शहरों से भी दो राज्यों के बीच उड़ान शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। देश में कहीं भी नया एयरपोर्ट विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेना होती है। इसके लिए जमीन संबंधित राज्य सरकार मुहैया कराती है। मप्र में छह और एयरपोर्ट खोलने के लिए राज्य सरकार को यह प्रक्रिया करना होगी। हालांकि, बताया जा रहा है विभिन्न चरणों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पहले फेज में दो शहरों को लिया जा सकता है।

प्रदेश में अनेक हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए नई पॉलिसी बना रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में हर 200 किमी पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बन सकेंगे। एयरपोर्ट विकसित कर यहां अंतरराज्यीय उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही राज्य की हवाई पट्टियों का भी विकास किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन और उद्योग की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मप्र की नई विमानन पॉलिसी में इन बातों पर विचार किया जा रहा है। मप्र में अब जिला और ब्लॉक स्तर पर भी हवाई यातायात उपलब्ध होगा। प्रदेश में कई नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जो कि पीपीपी मोड पर तैयार किए जाएंगे। जल्द ही हर 200 किमी पर हवाई अड्डा दिखाई देगा। इसके साथ ही हर 150 किमी पर एक हवाई पट्टी भी बनेगी। प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कम दूरी की उड़ानें संचालित की जा रही हैं। वहीं छोटे शहरों से भी दो राज्यों के बीच उड़ान शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार ने हर 200 किमी पर एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के 55 जिलों में से 31 जिलों में हवाई पट्टी है। इसके अलावा सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्रों की हवाई पट्टियां भी हैं। इनमें दमोह (डायमंड सीमेंट), शहडोल (ओरिएंट पेपर मिल), नागदा (ग्रेसिम) हवाई पट्टी हैं। इन्हें जेट विमान के उड़ान योग्य तैयार किया जा रहा है। इनके अलावा इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, छतरपुर (खजुराहो) एवं जबलपुर में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के हवाई अड्डे हैं। धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए छोटे विमान संचालित किए जाएंगे। धार्मिक एवं अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग वैचुरा, अर्चना एयरवेज जैसी सहायता प्राप्त योजनाएं लाने जा रहा है। विमानन विभाग और पर्यटन विभाग के बीच सहमति बन गई है। पर्यटन विभाग पीपीपी के तहत छोटे रूट पर विमानों का संचालन शुरू करने पर काम कर रहा है।

● **प्रवीण सक्सेना**

माननीय बनने बढ़ रही बेकरारी

मप्र में सरकार बने 13 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों की आस लगाए बैठे भाजपा नेताओं की मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद नेताओं को दर्जा मंत्री बनाने का सपना दिखाया गया। इसके लिए नेताओं ने सत्ता, संगठन और संघ की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। लेकिन मंत्री बनने का सपना अभी भी अधर में है। प्रदेश में निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्तियों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही निगम-मंडलों में नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। प्रदेश भाजपा के कई दिग्गज निगम-मंडलों में पद की आस लगा रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाई। गौरतलब है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई नेताओं के टिकट काटे गए थे। इनमें से कुछ नेताओं को पुनर्वास का पार्टी ने आश्वासन दिया था। संभावना है कि चुनाव बाद सरकार ऐसे नेताओं को मंत्री का दर्जा दे सकती है। भाजपा इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भी निगम-मंडल में समायोजित किया जा सके।

प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक साल बीतने के बाद अब निगम, मंडल और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां पाने के इच्छुक भाजपा नेताओं ने पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एक वर्ष में कुछ ही लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं। बाकी नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही उनका दर्जा मंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा। बता दें, पहले लोकसभा चुनाव के कारण नियुक्तियों का मामला टलता रहा। अब संगठन चुनाव के बाद निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां होने की संभावना बताई जा रही है। इसमें उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देकर मंत्री का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। इसके अलावा कांग्रेस से आए कुछ नेताओं की ताजपोशी भी निगम-मंडलों में हो सकती है। पिछली शिवराज सरकार में भाजपा के उन संभागीय संगठन मंत्रियों को भी निगम-मंडल में तैनात किया गया था, जिन्हें पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद हटा दिया था। इनमें से कुछ भाजपा के पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी हैं। अब तय किया गया है कि उन सभी पूर्व संगठन मंत्रियों को एक बार फिर मंत्री दर्जा नहीं दिया जाएगा। पिछले डेढ़ साल में कांग्रेस के भी कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, उनमें से कुछ को पार्टी ने मंत्री दर्जा देने का आश्वासन दिया था, अब उनकी भी आस टूटने लगी है। कांग्रेस से सुरेश पचौरी सहित तीन पूर्व सांसदों ने भाजपा की शरण ली थी। इसी तरह कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा ने दीपक सक्सेना को तोड़कर झटका दिया था।

डंडा-झंडा उठाने वाले नेताओं को पद का इंतजार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबसे सत्ता की कमान संभाली है तब से ही उन पर संगठन और कार्यकर्ताओं का दबाव है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां की जाएं। ताकि वर्षों से पार्टी का डंडा-झंडा उठाकर घूम रहे कार्यकर्ताओं को अपनी मेहनत का फल मिले, लेकिन अभी तक निगम मंडलों की नियुक्तियों को टाला जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर नेताओं की लिस्ट तैयार हो गई है, लेकिन यह नियुक्तियां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद होंगी। मंत्री दर्जा के पद कम होने से इस बार भाजपा सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं का सरकार में समायोजन करने की तैयारी कर रही है। पंचायत से लेकर जिला और राज्य स्तर तक दीनदयाल समिति का गठन होना है, इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने सुरेश पचौरी को बेहतर पुनर्वास का वादा किया था। प्रदेशभर के नेता निगमों-मंडलों में पद पाने की जोड़-तोड़ में लगे हैं। मंडलों में सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव हारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक आस लगाकर बैठे हैं। सिंधिया समर्थकों में पूर्व मंत्री और सिंधिया की चहेती मानी जाने वाली इमरती देवी, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जैसे नाम शामिल हैं। ये तीनों नेता सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। चुनाव हारने के बाद से तीनों नेता प्रदेश की राजनीति से गायब भी दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सरकार में भाजपा के पूर्व संभागीय संगठन मंत्रियों को निगम-मंडल में पदस्थ कर मंत्री दर्जा दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद इन नेताओं को हटा दिया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वे सभी पूर्व संभागीय संगठन मंत्री एक बार और निगम में तैनात करने के लिए दबाव बना रहे हैं।

प्रदेशभर में ऐसे कई नेता हैं जो निगम मंडलों की जुगाड़ में हैं, एक तो वो जिन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया और दूसरे वे जो कांग्रेस से आकर भाजपा में रचे-बसे हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जिन्हें संगठन का दायित्व दे दिया गया है, वे भी कोशिश में हैं कि कहीं एडजस्ट हो जाएं। अपने समर्थकों को एडजस्ट करवाने के लिए मंत्री और विधायकों ने भी लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में 50 से ज्यादा निगम-मंडल-बोर्ड ऐसे हैं जहां नियुक्तियां होनी हैं। इन पदों पर नियुक्तियों के लिए कई बार कवायदें चलीं, मगर वह अंजाम तक नहीं पहुंच पाईं। इसका एक कारण नेताओं द्वारा समर्थकों की नियुक्तियां कराने का दबाव बनाना भी है। कई बड़े नेता करीबियों को जिम्मेदारियां दिलाना चाहते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संगठन चुनाव पूरा होने के बाद नियुक्तियां करने का फैसला लिया है। इसके बाद ही मंडलों में नियुक्तियां होने की संभावना है। दरअसल, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने इन पदों पर नियुक्तियां की थीं। बाद में फरवरी 2024 के समय मोहन सरकार ने निगम मंडल की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। इसके बाद से ही मप्र के मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली पहुंचते हैं तो कई नेताओं को लगता है कि नेम प्लेट पर माननीय अब चिपका या तब चिपका। लेकिन इसी आस में सालभर बीत गया और अब तक निगम-मंडलों में नियुक्ति नहीं हुई है।

● **लोकेश शर्मा**

देश का हृदय प्रदेश मप्र राजनीति का भी केंद्रीय प्रदेश है। संघ और भाजपा की प्रयोग भूमि इस प्रदेश में राजनीति के नए-नए प्रयोग किए जाते हैं। इसी कड़ी में संविधान को लेकर छिड़ी लड़ाई भी यहीं से लड़ी जा रही है। जिससे संविधान की लड़ाई में मप्र सियासी रणभूमि बन गया है। डॉ. अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस ने 27 जनवरी को बड़ी रैली की। वहीं, भाजपा ने संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस की रैली का जवाब दिया। दरअसल, दोनों पार्टियां अपने आपको संविधान और अंबेडकर प्रेमी बताने की होड़ में लगी हुई हैं।

संविधान के नाम पर रण

संसद से शुरू हुई संविधान की लड़ाई मप्र से लड़ी जा रही है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर मप्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान देखने को मिला। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महू में अंबेडकर की जन्मस्थली पर बने स्मारक पर पहुंचे और संविधान निर्माता को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। उन्होंने अंबेडकर अमर रहे, का नारा भी लगाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि मुझे गणतंत्र दिवस पर अंबेडकर की जन्मस्थली आकर उन्हें प्रणाम करने का अवसर मिला। यह अलग बात है कि कांग्रेस नेता इसे पर्यटन केंद्र समझकर यहां आते हैं। वहीं 27 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने महू में एक बड़ी रैली की।

दरअसल, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संविधान की रक्षा के नाम पर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा संविधान को कमजोर कर रही है। वहीं भाजपा का दावा है कि वो ही संविधान की असली रक्षक है। इसी खींचतान के बीच मप्र चुनावी रणभूमि बन गया है। महू को अंबेडकर की जन्मस्थली होने के कारण विशेष महत्व दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे बाबा साहेब से जुड़े पंचतीर्थों में शामिल किया है। यह जगह दलित समुदाय के लिए पवित्र स्थल मानी जाती है। इसलिए दोनों ही दल इस मौके का फायदा उठाकर दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस ने जोर-शोर से जातिगत जनगणना और संविधान का मुद्दा उठाया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में मप्र सहित कई राज्यों में कांग्रेस को इस जातिगत गणना का कोई लाभ नहीं मिला।

26 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर अंबेडकर का मखौल उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने अंबेडकर की जन्मस्थली को तीर्थ स्थल बताते हुए कहा कि तीर्थ की महत्ता तिथियों से होती है और कांग्रेस नेताओं को अंबेडकर की जन्मस्थली आना ही है, तो उन्हें अंबेडकर से जुड़ी तिथियों पर आना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर संविधान और अंबेडकर का मखौल उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग अपने इवेंट की वजह से अंबेडकर की जन्मस्थली पर आते हैं, न कि अपने कमिटमेंट की वजह से। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और वह सबको पहचानती भी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि अंबेडकर को उनके जीवनकाल में एक पार्टी विशेष और उसके नेताओं के कारण कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। आज इस पार्टी के नेता अपनी सियासी जमीन खोने के बाद अंबेडकर की जन्मस्थली को पर्यटन केंद्र समझकर यहां आ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि अंबेडकर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अंबेडकर की जन्मस्थली आने पर कोई रोक नहीं है, पर वह उम्मीद करते हैं कि ये नेता संविधान निर्माता के साथ किए गए अन्याय को याद करें और इसके लिए उनसे माफी मांगें। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 1950 में देश के संविधान को लागू किए जाने के दौरान अंबेडकर का मत था कि अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का कदम गलत है, क्योंकि इससे भविष्य में कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि हमने यह सब देखा कि अनुच्छेद-370 के कारण 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुईं। नरेंद्र मोदी सरकार

दलितों को साधने का मंच बना डॉ. अंबेडकर नगर

आधिकारिक रूप से डॉ. अंबेडकर नगर और व्यवहारिक रूप से महू के नाम से जाना जाने वाली अंबेडकर की जन्मस्थली नेताओं का तीर्थस्थल बन गया है। हाल के दिनों में यह दलित राजनीति का केंद्र बन गया है। दलितों को साधने के लिए डॉ. अंबेडकर नगर सबसे बड़ा मंच बन गया है। भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी सभी की कोशिश रहती है कि देश के सबसे बड़े वोट बैंक दलितों को साधने के लिए डॉ. अंबेडकर नगर में बड़ा समागम किया जाए। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि आज डॉ. अंबेडकर नगर राजनीति और राजनेताओं का तीर्थस्थल बन गया है। देश में दलित राजनीति की धुरी बन चुके डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू कांग्रेस और भाजपा के लिए सियासी जोर आजमाइश का केंद्र बनी हुई है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में दलित वोट और सीटों के आंकड़ों ने कांग्रेस और भाजपा की सक्रियता बढ़ा दी है।

ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित कर दिया था।

वहीं कांग्रेस ने 27 जनवरी को महू में बड़ा आयोजन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर बात की और जनता को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा ने लोकसभा से पहले भी संविधान को खत्म करने की बात कही थी, इन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें आ गईं तो संविधान बदल देंगे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को संविधान के आगे माथा टेकना पड़ा। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा, हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ आरएसएस-भाजपा है जो संविधान के खिलाफ हैं, इसे कमजोर करते हैं और खत्म करना चाहते हैं।

राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। इसमें अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, भगवान बुद्ध, फुले जी जैसे महापुरुषों की आवाज है। राहुल गांधी ने आगे कहा, कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। मोहन भागवत की बात पर राहुल गांधी ने कहा, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। याद रखिए, जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, दलितों के लिए आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए, दो-तीन अरबपतियों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। संविधान में लिखा है कि हिन्दुस्तान के सारे नागरिक एक समान हैं। संविधान में लिखा है हर

हिन्दुस्तानी को सपना देखने और भविष्य बनाने का हक होना चाहिए। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिन्दुस्तान में है। राहुल गांधी ने आगे कहा, यह नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, वो हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार हैं। जीएसटी हिन्दुस्तान के गरीब लोग देते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। राहुल गांधी ने कहा, पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम कम होता है, लेकिन भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। राहुल गांधी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम होगी लेकिन हिन्दुस्तान में कीमत बढ़ती जाती है। आजादी से पहले गरीबों को कोई अधिकार नहीं थे राजा को थे। भाजपा-आरएसएस आजादी से पहले का हिन्दुस्तान चाहती हैं। बेरोजगारी पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, इस देश में युवा को रोजगार नहीं मिल सकता, बिना रोजगार के सर्टिफिकेट कचरा है। इस देश में आईआईएम और आईआईटी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही आपको कहां से मिलेगी। आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है आप देख रहे हो मैं हैरान हूं, ये लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, आदिवासी राष्ट्रपति है, उन्होंने उनको अंदर मंदिर में जाने नहीं दिया। राम मंदिर कार्यक्रम में किसी दलित पिछड़े को देखा? राष्ट्रपति को संसद उद्घाटन में भी नहीं आने दिया गया। गरीब जनरल कास्ट और दलितों-पिछड़ों के हाथ में क्या आ रहा है? 90 फीसदी आबादी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, देश का बजट 90 अफसर बनाते हैं, उनमें से दलित, पिछड़ा, गरीब जनरल कास्ट, आदिवासी कितने हैं मैंने सोचा पता लगाते हैं। इनमें से 3 पिछड़े हैं, कहते हैं उनको की चुप बैठो वरना तुम्हारी एसीआर बिगाड़ देंगे, क्या ये अन्याय नहीं है।

महू में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर तेलंगाना सरकार ने क्रांतिकारी तरीके से काम शुरू किया है। जहां सबसे पहले जाति जनगणना हो रही है। कुछ ही समय में हम दिखाने जा रहे हैं कि तेलंगाना में दलितों, गरीबों, आदिवासियों और माइनॉरिटी की जनसंख्या कितनी है। इन वर्गों का राज्य के संसाधनों पर कितने प्रतिशत हक है। राहुल गांधी ने कहा- यह एक क्रांतिकारी निर्णय है। जिसके सार्वजनिक होने के बाद 90 प्रतिशत आबादी को पता चल जाएगा कि राज्य में हमारी आबादी कितनी है। उसके अनुरूप हमारे कितने हित और अधिकार हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

भाजपा के लिए चुनौती, कांग्रेस में उत्साह

2009 से लेकर 2024 तक के लोकसभा चुनाव परिणामों में एससी आरक्षित सीटों का आंकड़ा देखें, तो भाजपा की बढ़ती मुश्किलें स्पष्ट हो जाती हैं। 2009 में भाजपा को 12, जबकि 2014 में 40 सीटें मिली थीं, वहीं 2019 के मोदी लहर में 46 तक पहुंचने के बाद 2024 में यह घटकर 30 रह गईं। कांग्रेस का ग्राफ भले ही छोटा रहा, लेकिन 2024 के नतीजे ने उसकी संभावनाओं को बल दिया है। एससी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस को 2009 में 30 तो 2014 में 7 सीटें मिली थीं, जबकि 2019 में छह का आंकड़ा 2024 में छलांग लगाकर 20 पर पहुंच गया है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि वोट शेयर भाजपा के साथ 31 प्रतिशत, तो कांग्रेस के साथ 19 प्रतिशत है। मप्र के 2023 के विधानसभा चुनाव में एससी आरक्षित सीटों को देखें तो भाजपा को 26, तो कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने मप्र में दलित राजनीति को लेकर मुखर होने के लिए जीतू पटवारी को फ्रीहैंड दिया है। इधर, दलित वर्ग को साधने की होड़ में कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है।

जैसा लोग कहेंगे वैसा होगा बजट

मप्र के आगामी बजट को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। बजट को लेकर सभी सेक्टर्स के विषय विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों और आम लोगों से भी बजट को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। आम लोग मप्र सरकार की साइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं। वहीं बजट से समाज के अलग-अलग वर्गों की क्या उम्मीद है और वे क्या चाहते हैं, यह जानने के लिए सरकार खुली चर्चा कराएगी। यह आयोजन 23 जनवरी को प्रशासन अकादमी में होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक आम लोग बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। जो भी सुझाव बेहतर होगा उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा।

गौरतलब है कि मार्च में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियों में सरकार जुटी है। अधिकारियों के स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश सरकार का बजट इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा, नारी, गरीब और किसान कल्याण के विजन पर केंद्रित होगा। सरकार इसे लेकर स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ कर चुकी है। गरीब कल्याण मिशन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है तो नारी सशक्तीकरण और किसान कल्याण मिशन का खाका भी खींचा जा चुका है। इन पर फोकस करते हुए बजट की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। विभिन्न विभागों ने इन वर्गों से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए अपने बजट प्रस्ताव दिए हैं। बजट को लेकर विभिन्न वर्गों की जो उम्मीद है, उन्हें जानने के लिए खुली चर्चा कराने का निर्णय लिया है। बजट से समाज के अलग-अलग वर्गों की क्या उम्मीद है और वे क्या चाहते हैं, यह जानने के लिए सरकार खुली चर्चा कराएगी। यह आयोजन 23 जनवरी को प्रशासन अकादमी में होगा। इसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठेंगे और सुझाव लेंगे। 23 जनवरी को प्रशासन अकादमी में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ युवा, महिला, किसान, उद्योग सहित अन्य वर्गों की बजट से अपेक्षा जानेंगे। इसके लिए सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इनकी मांग और सुझाव पर विभाग विचार करेगा व जो भी बजट में शामिल करने योग्य बिंदु होंगे, उन्हें प्रस्तावित किया जाएगा।

प्रदेश का वर्ष 2024-25 का बजट 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है। 22 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट के माध्यम से भी विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। इसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2025-26 का बजट चार लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चार जातियां गरीब, किसान, युवा और महिला बताई हैं, उसको ही केंद्र में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन वर्गों को लेकर संचालित केंद्रीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ हितग्राहियों को दिलाने के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना बनाएं। इसके अनुसार ही बजट प्रविधान प्रस्तावित करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनवरी के अंतिम सप्ताह में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। बजट का खाका भी युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए चलाए जाने वाले मिशन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से खींचा जा रहा है। सभी विभागों में इन चारों वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रविधान होंगे। बजट में इन्हें अलग से प्रदर्शित भी किया जाएगा और एक विभाग को नोडल बनाया जाएगा। यह ठीक कृषि, चाइल्ड और जेंडर बजट जैसा होगा। इसमें अलग से बताया जाता है कि किस वर्ग के लिए क्या वित्तीय प्रविधान किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जापान दौरे से लौटने के बाद बजट प्रस्तावों पर बैठक करेंगे। इसके पहले वित्त विभाग और मुख्य सचिव अनुराग जैन के स्तर पर विचार-विमर्श कर बजट का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। केंद्र के बजट को देखने के बाद उसके प्रविधान के अनुसार प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगे साढ़े आठ हजार करोड़

घर-घर नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए जल जीवन मिशन के कई काम प्रदेश में फंड के अभाव में अटक गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इसे लेकर नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल, केंद्र सरकार से योजना को संचालित करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिल पा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने में करीब दो माह रह गए हैं और अब तक दूसरी और तीसरी किस्त के 1,422 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के लिए प्रस्तावित 17 हजार करोड़ रुपए के कामों के लिए साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए के केंद्रांश के साथ 4,456 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं। प्रदेश में 26,408 नल-जल योजनाओं के लिए 77,952 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार से पहली किस्त के रूप में 2,622 करोड़ रुपए तो मिल गए हैं लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त अप्राप्त है। इसके कारण ठेकेदारों का भुगतान अटका हुआ है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इसकी पूर्ति के लिए सरकार बजट की व्यवस्था कर रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत हुए अनुपूरक बजट के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 3,515 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए। इसके साथ ही केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व चर्चा बैठक में राज्य की ओर से उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बकाया राशि दिलाने के साथ बजट में अतिरिक्त प्रविधान करने की मांग रखी। बता दें, प्रदेश में वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन अंतर्गत 10,773 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2024-25 में योजना के कामों के लिए 17 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, इसमें केंद्र सरकार की सहभागिता 8,500 करोड़ रुपए की है।

भाजपा में अंदरूनी लड़ाई

मप्र भाजपा में अंदरूनी लड़ाई से हर कोई त्रस्त है। मंत्री, सासंदों और विधायकों में खुलेआम तकरार हो रही है। कोई मंच से तो कोई बैठकों में हमला बोल रहा है। इससे पार्टी का माहौल लगातार गरमा रहा है। प्रदेश में भाजपा के अंदर कलह बढ़ती जा रही है। भाजपा में अपने ही लोगों ने अपने नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि भाजपा नेताओं के बीच बढ़ रही तल्खियों ने कांग्रेस को मौका दे दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि ये भाजपा में मंत्रियों और सांसदों के बीच चल रही गलाकाट प्रतिस्पर्धा है या जलन की भावना है।

मप्र के चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। राज्य से लेकर केंद्र तक में भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद मप्र भाजपा के अंदर गुटबाजी की आग भड़क रही है। अब यह लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। यह लड़ाई सरकार और संगठन को असहज करने वाली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें विभिन्न पदों पर समायोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाने वाले विधायकों को बोर्ड और निगमों में स्थान दिया जाएगा। कुछ नेताओं को सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के गुटों के बीच भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की गुटबाजी का असर बीते चुनावों पर भी पड़ा है। रामनिवास रावत की विधानसभा उपचुनाव में हार को इसी का परिणाम माना जा रहा है।

इस समय भाजपा में संगठन चुनाव चल रहे हैं। इस बीच, पार्टी में अंदरूनी विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। पार्टी के नेता एक-दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। हाल ही में विंध्य में देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल आमने-सामने हैं। इससे पहले भी अलग-अलग रीजनल में नेताओं के विवाद खुलकर सामने आ चुके हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो इसकी शिकायत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई है। ऐसे में प्रदेश में चल रही खींचतान को सुलझाने के लिए प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। देवतालाब विधानसभा से विधायक गिरीश गौतम और मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल हैं। इसका कारण है कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण के मामले में विधायक प्रदीप पटेल के दबाव में एक टीआई और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया। मऊगंज विधायक पटेल की देवतालाब क्षेत्र में दखलंदाजी विधायक गिरीश गौतम को पसंद नहीं आई। उन्होंने पटेल पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि उनके क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। इसलिए, देवतालाब विधानसभा में दखल दे रहे हैं। इस पर पटेल ने कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने किस तारतम्य में ऐसा कहा, यह तो वही बता सकते हैं। सीधी से विधायक रीति पाठक ने कुछ दिन पहले ही उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में मंच से उपमुख्यमंत्री को कहा कि वह रीवा के साथ ही सीधी का भी विकास करें। सीधी में अस्पताल के विकास के लिए आई 7 करोड़ रुपए की राशि गायब हो गई। उन्होंने छह से सात बार पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर उनके क्षेत्र की समस्याओं को नजरंदाज करने का भी आरोप लगाया था।

प्रदेश के कई अन्य क्षेत्र भी हैं जहां भाजपा नेताओं के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद सामने आ चुका है। टीकमगढ़ से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के खिलाफ अपने ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पहले पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने कहा था कि वह कांग्रेसियों का पक्ष ले रहे हैं। साथ ही अपराधियों को प्रतिनिधि बना रहे हैं। अब मीडिया से बात करते हुए विधायक ललिता यादव ने कहा है कि मानवेंद्र सिंह ने सच कहा है। कांग्रेस के रिकॉर्डेड एजेंट को वह प्रतिनिधि बना रहे हैं। सभी विधायक उनसे परेशान हैं। वहीं, विवादों पर केंद्रीय मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि मैं सीधा साधा व्यक्ति हूं। साथ ही सीधी राजनीति करता हूं। मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं। आयातित लोग कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे, जिन्हें खुद पार्टी में आए कितना समय हुआ है। दरअसल, रायसेन जिले के एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन था। इस कार्यक्रम में नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल गेस्ट थे। स्कूल के आमंत्रण पत्र में सांसद का नाम ऊपर था और मंत्री का नीचे। यह बात मंत्रीजी को नागवार गुजरी और कथित तौर पर स्कूल की मान्यता रद्द करने की वार्निंग दिलवा दी। बाद में स्कूल को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि दर्शन सिंह चौधरी ने कहा था कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। इसी तरह से विंध्य क्षेत्र में रीवा सांसद और त्योंथर विधायक के बीच ठन गई है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक कार्यक्रम में भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी के दादा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तिवारी ने लूट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति की है। इस पर श्रीनिवास तिवारी के पोते और भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि दिवंगत नेता पर इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है। जनता की सेवा के लिए जिसने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

● **जितेंद्र तिवारी**

सागर में वर्चस्व की जंग

बुंदेलखंड के सागर में भाजपा नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच टकराव जारी है। 2020 में गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। वहीं, गोविंद राजपूत सिंधिया समर्थक हैं। भूपेंद्र सिंह का आरोप है कि गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया है। वह उनको दिल से कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं, राजपूत भी कई बार कह चुके हैं कि एक विधायक अपने आप को पार्टी से बड़ा मानता है। यह मामला भी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है।

क्या खुलेगा कालेधन का राज?

आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर चेतन गौर और शरद जायसवाल भी लोकायुक्त की रिमांड पर हैं। जानकारों का कहना है कि अब लोकायुक्त तीनों का आमना-सामना कराएगी। जिससे यह साफ हो सके कि कम समय में सौरभ और उसके सहयोगियों ने इतनी बड़ी मात्रा में धन कैसे अर्जित किया। काली कमाई को सोने-चांदी की सिल्लियों में कैसे कन्वर्ट कराया जाता था। अवैध नाकों से खुलेआम वसूली के खेल में और कौन-कौन लोग उनके सहयोगी रहे हैं। इस कमाई का हिस्सा कहां और किस तक जाता था। इन सभी सवालों का जवाब अभी मिला नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या कालेधन का राज खुल पाएगा।

सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी ने प्रदेश के कई बड़े नेता और अफसरों की सांसें फूला दी हैं। सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उसकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। हालांकि, इन आरोपों पर भूपेंद्र सिंह जवाब दे चुके हैं कि कॉन्स्टेबल की नियुक्ति में मंत्री का सीधा कोई दखल नहीं होता। सौरभ शर्मा 2016 से 2023 तक नौकरी में रहा। इस बीच, कांग्रेस से भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत, कमलनाथ और शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे। सौरभ शर्मा ने उनके कार्यकाल में करीब चार साल तक नौकरी की। दरअसल, कांग्रेस के कई बड़े नेता आरोप लगा चुके हैं कि एक कॉन्स्टेबल इतना पैसा बिना किसी सफेदपोश और बड़े अधिकारी के संरक्षण के बगैर नहीं कमा सकता। इसमें गोविंद सिंह राजपूत पर भी आरोप लगे। हालांकि, राजपूत ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया कि इस मामले में मेरा कोई लेना-देना नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच के बाद सब क्लीयर हो जाएगा।

सौरभ के दोस्त चेतन गौर की गाड़ी में एजेंसी को एक डायरी मिली है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के हिसाब-किताब लिखा होने की बात सामने आई है। अब सौरभ और चेतन गौड़ पूछताछ में डायरी में किन अधिकारियों का लेखा-जोखा है, उसका खुलासा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि डायरी में उन अधिकारियों की पूरी डिटेल है, जिनको उगाही का हिस्सा देता था। ऐसे में कई अधिकारियों और नेताओं की अब धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को छापा मारा था। इसके बाद से वह फरार था। इसके बाद एजेंसियों ने उसके दुबई जाने की बात कही। वहीं, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। हालांकि, बाद में उसके 23 दिसंबर को भारत लौट आने की जानकारी भी सामने आई। वह इसके बाद से दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में घूम रहा था। वह अपने परिवार के संपर्क में था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बीच वह भोपाल भी आया, लेकिन एजेंसियां सोती रहीं। जानकारों का कहना है कि इस मामले में निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें लोकायुक्त, ईडी और आयकर की टीम जांच कर रही है। वहीं, आरोपी भारत में घूम रहा है। वह भोपाल आता है और जांच एजेंसियों को उसका पता ही नहीं चलता है। इससे जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली कटघरे में आती है। हाईप्रोफाइल मामले में तो जांच एजेंसियों की तेजी से कार्यवाही की उम्मीद रहती है।

परिवहन विभाग में पदस्थ सीनियर अफसर बताते हैं कि सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ थे। साल 2016 में उनकी अचानक मृत्यु के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए सौरभ की तरफ से आवेदन दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल नोटशीट लिखी कि उनके यहां कोई पद खाली नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक ये इसलिए किया गया ताकि सौरभ शर्मा को मनचाहे विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सके। अफसरों के मुताबिक आमतौर पर परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति इतनी आसानी से नहीं होती। इसके लिए ऊंची पहुंच यानी राजनीतिक कॉन्टैक्ट होना बेहद जरूरी होता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2016 की तत्कालीन सरकार में भी सौरभ के हाई लेवल पर संबंध थे। यही वजह थी कि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हुई।

● **विकास दुबे**

ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने मारे थे छापे

भोपाल में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के यहां 9 दिन में तीन एजेंसियां ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापे मारे थे। कार्रवाई के दौरान उसके पास 93 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली। इनमें कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने 27 दिसंबर को सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल, रोहित तिवारी के ठिकानों पर छापे मारे थे। सौरभ के परिजन और दोस्तों के खातों में 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस पाया। इसके अलावा 23 करोड़ की संपत्ति भी जांच के दायरे में ईडी ने ली थी। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में की गई जांच में 6 करोड़ रुपए की एफडी की जानकारी भी ईडी के हाथ लगी है। फर्मों और कंपनियों के जरिए किए गए निवेश का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित घर और ऑफिस पर छापा मारा था। टीम को इन ठिकानों से 2.95 करोड़ रुपए कैश, करीब 50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात और 234 किलो चांदी सहित अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इसी दिन आधी रात के बाद भोपाल के ही मेंडोरी इलाके में जंगल में लावारिस खड़ी कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। ये कार सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम है।

कुंभ में भगदड़

अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ में होते रहे हादसे

कुंभ मेले में भगदड़ कई बार मची है। अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ के दौरान कई हादसे हुए। 1820 के हरिद्वार कुंभ मेले में भगदड़ से 450 से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1840 के प्रयाग कुंभ मेले में 50 से अधिक मौतें हुईं। 1906 के प्रयाग कुंभ मेले में तो भगदड़ से 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

प्रयागराज के संगम तट पर 28-29 जनवरी की रात करीब डेढ़ बजे मची भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 90 घायल हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए ज्यादातर श्रद्धालु संगम पहुंचना चाहते थे। भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज और मेले में जितने भी रैन बसेरे, धर्मशाला, होटल थे, सब फुल हो गए। लोग सड़कों पर सोने लगे। सड़कों पर भी जगह नहीं मिली, तो लोग संगम के किनारे पहुंच गए। यहां का आधा हिस्सा अखाड़ों के लिए रिजर्व है। आम लोग उधर नहीं जा सकते थे। आम लोगों के लिए तय जगह पर भीड़ जमा होती गई। चुंगी और गऊ घाट से आ रहे लोग भी संगम की तरफ पहुंच रहे थे। संगम पर भीड़ का आगे बढ़ना रुक गया, लेकिन पीछे से लोग आते रहे। इससे 500 मीटर का एरिया चोक हो गया। भगदड़ की दूसरी घटना संगम से करीब एक किमी दूर सेक्टर-21 में हुई। ये संगम के बाद सबसे प्राइम एरिया सेक्टर-20 से सटा है। सेक्टर-20 में सभी प्रमुख अखाड़े हैं। इसलिए यहां ज्यादा भीड़ होती है। यहां जमा भीड़ संगम की तरफ जाना चाहती थी। पुलिस उन्हें जिस रास्ते से भेज रही थी, उस पर करीब 7 किमी चलना था।

कुंभ में पहले भी भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। अंग्रेजों के समय 1820 में कुंभ में भगदड़ मचने से 450 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1954, आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंचे थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीब 8-9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा संन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा, वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए। 27 अगस्त, 2003, महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ लगा था। वहां रामकुंड की ओर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को बैरिकेड्स लगाकर रोका गया था। करीब 30 हजार श्रद्धालु संकरी गली में फंसे थे। इसी बीच एक साधु ने चांदी के सिक्के उछाल दिए। सिक्के लूटने के चक्कर में लोग एक-दूसरे पर चढ़ने लगे। कुछ लोगों के बीच मारपीट भी हो गई। इससे भगदड़ मच गई। 39 लोगों की जान चली गई। 140 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए। 14 अप्रैल 1986, हरिद्वार कुंभ खत्म होने को था। तब हरिद्वार उप्र का हिस्सा था। सुबह का वक्त था। उप्र के मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्नान करने हर की पैड़ी पहुंच गए। उनके स्नान के लिए रास्ता सवा तीन घंटे बंद रखा गया। तब हर की पैड़ी जाने के लिए एक संकरे पुल के ऊपर से जाना होता था। रास्ता रोके जाने की वजह से भीड़ पुल पर जमने लगी। जब मुख्यमंत्री के स्नान के बाद रास्ता खोला गया तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे। भगदड़ मच गई। करीब 50 लोग कुचलकर मारे गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कुछ लोगों की मौत दम घुटने की वजह से भी हुई थी।

10 फरवरी 2013, रविवार का दिन। प्रयाग में कुंभ लगा था। उस दिन मौनी अमावस्या थी। तीन करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। शाम साढ़े सात-आठ बजे की बात है। प्रयागराज जंक्शन पर अचानक लोगों की चीख-पुकार गूंजने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर-6 पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों लोग बदहवास होकर इधर-उधर भाग रहे थे। एक-दूसरे पर गिरते-गिराते। बहुत भयावह मंजर था। जब भगदड़ थमी तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी पड़ी मिलीं। इनमें महिलाएं, पुरुष, जवान और बुजुर्ग सब शामिल थे। कुल 36 लोग मारे गए। देर रात तक इस तरह की चीखों से स्टेशन गूंजता रहा। किसी ने मां को खोया तो किसी ने पिता को, तो किसी ने बेटा-बेटी खोया। अफसोस इस बात का है कि स्टेशन पर इमरजेंसी सुविधा नहीं थी। कई घायलों को बचाया जा सकता था। कुचले जाने के बाद भी कई लोग जिंदा थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर न तो वक्त रहते स्ट्रेचर पहुंच पाया न ही कोई एंबुलेंस। लोगों कपड़े में बांधकर, चादर में लपेटकर घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे। हादसे के वक्त रेलवे कुंभ वार्ड में ताला लगा हुआ था। साढ़े नौ बजे डीआरएम पहुंचे। उसके बाद अस्पताल का ताला खुला। तब वहां रूई और पट्टी छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे। चार लोगों की मौत तो इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गई। कई लोग परिजनों की लाश लेकर भटक रहे थे। 12 घंटे इंतजार करने के बाद भी प्रशासन शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाया था। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हो रहा था। अस्पताल के बाहर मुंहमांगे दामों पर कफन बिक रहे थे। किसी ने हजार रुपए में कफन खरीदे तो किसी को 1200 रुपए देने पड़े।

2013 कुंभ के वक्त उप्र में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। आजम खान को मेले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आजमा खान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन दोष रेलवे और मीडिया पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि जहां तीन करोड़ लोग एक दिन में आए, वहां इस तरह के हादसे के बारे में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मीडिया की सूचना की वजह से भी जो पैनिक क्रिएट हुआ है, उसे कंट्रोल करना है। उप्र सरकार ने मृतकों को पांच-पांच लाख और घायलों को एक-एक लाख रुपए मुआवजा दिया। जबकि रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए दिए गए।

● **बृजेश साहू**

चंबल में घड़ियालों का बढ़ता कुनबा

संकटग्रस्त पक्षियों की जीवनदायिनी बनी चंबल नदी

आगरा के पर्यावरणविद और पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि देश की एकमात्र ऐसी नदी चंबल है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रदूषण नहीं है। सबसे शुद्ध और निर्मल चंबल बहती है। जिसकी वजह से चंबल का जैविक महत्व अधिक हो गया है। यहां पर जल प्रदूषण नहीं है। इसलिए, यहां पर संकटग्रस्त जलीय जीवों के साथ ही संकटग्रस्त पक्षियों का आशियाना भी चंबल बन रही है। जिसकी वजह से ही चंबल नदी का पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ विकसित हो रहा है। पक्षी विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि चंबल नदी का पानी प्रदूषित नहीं है। इसलिए, हर साल चंबल में देश और दुनिया से पक्षी पहुंचते हैं। इसमें इंडियन स्कीमर पक्षी शामिल है। जो संकटग्रस्त पक्षी हैं और बेहद सुंदर हैं। इंडियन स्कीमर इस मौसम में सिर्फ आता ही नहीं बल्कि यहां पर ब्रीड भी करता है। इसके साथ ही प्रवासी पक्षी यहां पर खूब कलरव करते हैं। कहें तो संकटग्रस्त जलीय जीव ही नहीं, संकटग्रस्त पक्षियों की जीवनदायिनी भी चंबल नदी बन रही है।

डकैत और दस्युओं की पनाहगाह चंबल नदी में अब मगरमच्छ, घड़ियाल और डॉल्फिन का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। कहें तो चंबल अब संकटग्रस्त जलीय (सरीसृप) जीवों के लिए जीवनदायिनी बन गई है। बीते 10 सालों में चंबल सेंचुरी में मगरमच्छ की संख्या बढ़कर दोगुनी से अधिक हुई है। चंबल में घड़ियाल और डॉल्फिन की संख्या में भी इजाफा हो रहा है।

मप्र, राजस्थान और उप्र में बहने वाली चंबल नदी उत्तर भारत की प्राचीन नदियों में से एक नदी है। जो प्राचीनकाल की चर्मवती नदी है। वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि चंबल नदी के खादर, बीहड के साथ ही तीन राज्य से जुड़ी सीमा की वजह से ये 60 और 70 के दशक में डकैतों की पनाहगाह बनी। धीरे-धीरे चंबल में डकैत सक्रिय हुए, जो समाज के सताए या रंजिश के चलते चंबल घाटी में पहुंचे। जिन्होंने चंबल में पहुंचते ही अपना बदला पूरा किया और अपराध के रास्ते पर चल निकले। ये खुद को डकैत की जगह बागी कहलाना पसंद करते थे। चंबल की बात करें तो यहां पर कई ऐसे डाकू हुए, जो आज भी लोगों के जेहन में जिंदा हैं।

केंद्र सरकार ने 1979 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना की, जो मप्र, राजस्थान और उप्र में बनाया गया। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की लंबाई करीब 435 किलोमीटर है। ये क्षेत्र मप्र के मुरैना, राजस्थान के धौलपुर और उप्र के आगरा और इटावा से औरैया जिले की सीमा तक है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को लेकर तीनों राज्यों ने विशेष तैयारी की। जिससे इस क्षेत्र में संकटग्रस्त जलीय जीव और संकटग्रस्त पक्षियों का संरक्षण करने पर काम शुरू करने की योजना बनी। सन् 1981 में घड़ियाल संरक्षण परियोजना बनी। इसके बाद चंबल में घड़ियाल संरक्षण पर काम शुरू किया गया। जिससे चंबल में घड़ियाल, मगरमच्छ, बटागुर कछुआ और डॉल्फिन का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है।

चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट की डीएफओ चांदनी सिंह कहती हैं कि चंबल में संकटग्रस्त जलीय जीव के संरक्षण को लेकर सरकार की योजना है। सरकार की इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ हेविटाट योजना में हम बहुत कार्य करते हैं। जिससे चंबल में घड़ियाल, मगरमच्छ, बटागुर कछुआ और डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। मार्च और अप्रैल में घड़ियाल, मगरमच्छ और बटागुर कछुआ के प्रजनन का समय आता है तो इनके अंडे की देखरेख कर्मचारी करते हैं। इसकी लगातार मॉनीटरिंग होती है। एनजीओ के साथ मिलकर रेस्क्यू, रिहेबिलेटशन, हेचिंग और बच्चों को यमुना में रिलीज किया जाता है। इस तरह से संरक्षण किया जा रहा है। चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट की डीएफओ चांदनी सिंह ने बताया कि चंबल नदी में संकटग्रस्त जलीय जीवों की गणना की गई। जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, बटागुर कछुआ की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि 2023 के मुकाबले डाल्फिन की संख्या 216 से घटकर 167 हो गई है। इस पर सेंचुरी के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। चंबल सेंचुरी क्षेत्र में वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष नहीं हो, इसके लिए समय चंबल के तटीय गांव में जनता के साथ गोष्ठी की जाती है। जिसमें लोगों को ये बताते हैं कि वन्यजीव का संरक्षण जरूरी है। जब बाढ़ आती है तो जनता से ये अपील की जाती है कि यदि कोई वन्यजीव गांव में आ जाए तो तत्काल विभाग को सूचना दें। जिससे उसे रेस्क्यू करके उसे प्राकृतिक वास में छोड़ा जाए। बाढ़ में जलीय जीवों के संरक्षण में अधिक चुनौती सामने आती है।

चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट की डीएफओ चांदनी सिंह का कहना है कि आगरा में एक फेमस कोट आगरा वियोंड ताज चल रहा है। उसमें सूर सरोवर पक्षी बिहार आता है। आगरा से महज 80 किमी की दूरी पर चंबल मिल जाती है। ऐसे ही इटावा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर चंबल मिल जाती है। बस और टैक्सी से पर्यटक पहुंच सकते हैं। उप्र सरकार का ईको टूरिज्म पर जोर हैं। जिसमें हमारा पूरा सहयोग है। आगरा की बात करें तो बोटिंग की व्यवस्था है। यहां पर आने वाले पर्यटक चंबल में संकटग्रस्त जलीय जीव में जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, बटागुर कछुआ और डॉल्फिन के साथ ही बेहद ही खूबसूरत रंग-बिरंगे पक्षी देख सकते हैं। जिनमें कई पक्षी प्रवासी हैं। जो इस मौसम में चंबल में आए हैं। हम चंबल के मैनेंजमेंट प्लान में पिनाहट और नंदगवा चयनित हैं। जहां पर हम काम कर रहे हैं। जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। चंबल सेंचुरी के रेंजर उदय प्रताप सिंह बताते हैं कि सेंचुरी तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को किसी प्रकार की समस्या न हो। इसके लिए वन विभाग ने सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हैं। चंबल नदी की बात करें तो आज चंबल में घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन समेत प्रवासी पक्षी भी डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही चंबल सेंचुरी में लकड़बग्घा, तेंदुआ, काला हिरण, सांभर भी मौजूद हैं। उप्र के जालौन, इटावा और औरैया जिले की सीमा पर सिंडौस के पास एक क्षेत्र पचनदा है, जो मप्र राज्य के भिंड जिले की सीमा के पास भी है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की बादशाहत स्वच्छता के मामले में खत्म हो सकती है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उसे कई शहरों से कड़ी टक्कर मिल रही है। इंदौर लगातार 7 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। हालांकि इस बार उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कई ऐसे शहर हैं जो इंदौर को टक्कर दे रहे हैं लेकिन इस बार इंदौर को मप्र की ही राजधानी भोपाल से चुनौती मिल रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यह पहला मौका है जब स्वच्छ सर्वेक्षण में निगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रत्येक शहर मासिक सूचना तंत्र के माध्यम से अपने स्वच्छता संबंधित किए गए कार्यों की जानकारी भेजता है। सर्वे के दौरान मैदानी स्तर पर यदि कार्य में 50 फीसदी तक की कमी पाई जाएगी तो उस शहर के अधिकतम 30 अंक कम कर दिए जाएंगे।

इंदौर को मप्र की राजधानी भोपाल से कड़ी चुनौती मिल रही है। 2023 में भोपाल देश का पांचवां सबसे स्वच्छ शहर था। इस बार भोपाल नगर निगम ने खास तैयारी की है। जिसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। भोपाल नगर निगम के पास कचरा ट्रांसफर करने के लिए 72 बड़े ट्रक कैप्सूल हैं। वहीं, सड़क पर ऑटोमेटिक सफाई करने वाली 10 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल शहरों का अलग-अलग मापदंडों पर आंकलन किया जाता है, इसके बाद फैसला किया जाता है कि कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। सफाई सिस्टम के अलावा शहरवासियों का फीडबैक, शिकायतों का समाधान, स्वच्छता के लिए नवाचार, कचरे का पुर्नउपयोग, कचरे का निदान, जल सरंचना, तालाबों की सफाई, पब्लिक टायलेट समेत कई पैमाने होते हैं। इंदौर को स्वच्छता के मामले में उस बार सूरत से कड़ी टक्कर मिली थी। सूरत नगर निगम भी स्वच्छता के लिए लगातार नवाचार कर रहा है जिस कारण से उसके सफाई की देशभर में चर्चा हो रही है।

भोपाल को सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण लगातार प्रयास कर रहे हैं। गत दिवस स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के तहत सबसे स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता के लिए चुने गए 24 वार्डों के पार्षदों के साथ बैठक की। एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से पार्षदों को मूल्यांकन मानदंडों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कुल 200 अंक हैं, जिसमें से 100 अंक स्वच्छता घटकों के लिए समर्पित हैं। महापौर मालती राय ने विशेष स्वच्छता प्रयासों को प्रेरित करने और निवासियों के बीच गर्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता के लक्ष्य पर जोर दिया। मूल्यांकन के मुख्य मानदंडों में अपशिष्ट पृथक्करण, गीले अपशिष्ट से खाद बनाना, धूल रहित हरियाली, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, वाटर प्लस प्रोटोकॉल के अनुसार सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। स्वच्छ विद्यालय रैंकिंग, विरासत-थीम वाली दीवार पेंटिंग और स्वच्छता चैंपियन के सम्मान जैसी पहलों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार निगेटिव मार्किंग

12500 अंकों के लिए करनी होगी मशक्कत

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों का भी कहना है कि सुपर स्वच्छ लीग में शामिल शहरों की किसी तरह की रैंकिंग होगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है। इस संबंध में आगामी दिनों में निर्णय लिया जाएगा। इस बार सर्वेक्षण में शामिल शहरों को अव्वल आने के लिए 12500 अंक हासिल करने की मशक्कत करनी होगी। इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में स्वच्छ सुपर लीग के तहत पिछले वर्ष के सर्वेक्षण में अलग-अलग कैटेगरी में अव्वल रहे शहरों को एक साथ कर दिया गया है। स्वच्छ सुपर लीग में शामिल 12 शहरों का भी स्वच्छ सर्वेक्षण के 12500 अंकों पर आंकलन किया जाएगा। जो शहर 85 फीसदी से कम अंक लाएगा उसे लीग से बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह इस सर्वेक्षण में जिन शहरों को टॉप रैंकिंग मिलेगी वे अगली बार लीग में शामिल हो जाएंगे। अब इस स्वच्छ सर्वेक्षण में हर वर्ष नए टॉपर ही मिलेंगे।

पार्षदों, निवासी संघ के सदस्यों, स्वैच्छिक संगठनों और अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञों से मिलकर बनी एक जूरी वार्डों में स्वच्छता का आंकलन करेगी। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, जूरी के सदस्य अपने वार्ड के अलावा अन्य वार्डों का भी मूल्यांकन करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में कड़ा मुकाबला होने के कारण इंदौर व सूरत को संयुक्त रूप से नंबर-1 का स्थान मिला था। इंदौर के मुकाबले सूरत के सिर्फ 0.48 अंक ही कम थे। ऐसे में सर्वेक्षण में इस बार लागू की गई निगेटिव मार्किंग बड़े बदलाव करेगी। 15 फरवरी से स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए अलग-अलग शहरों में टीमें जाएंगी। इस बार इंदौर सहित 12 शहरों को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है। ऐसे में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में इस बार नए शहर अपनी-अपनी कैटेगरी में टॉप रैंकर होंगे। इंदौर शहर को लीग में मुकाबला करना होगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि लीग में शामिल अलग-अलग शहरों के बीच किसी तरह की प्रतियोगिता होगी या नहीं।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूल में शौचालय की सफाई, सभी कक्षा में गीले-सूखे कचरे के कूड़ेदान, छात्रों के लिए सेनेटरी नैपकिन और उसे डिस्पोजल के लिए नंबर दिए जाएंगे। यह श्रेणी 150 नंबर की तय की गई है। साथ ही केंद्रीय टीम सर्वेक्षण में यह भी देखेगी कि जो सुविधा स्कूलों में उपलब्ध कराई जा रही है उनका छात्र-छात्राएं प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। वहीं पर्यटन स्थलों पर सफाई के लिए भी इस बार नंबर मिलेंगे। साथ ही कार्यालय की दीवारों पर रेड स्पॉट का निरीक्षण करेगी और रेड स्पॉट दिखा तो निर्धारित 60 अंक काटे जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 ट्रिपल आर (रिफ्यूज, रिड्यूस, और रीसाइकिल) पर आधारित है और इस बार 12500 अंक आधारित हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

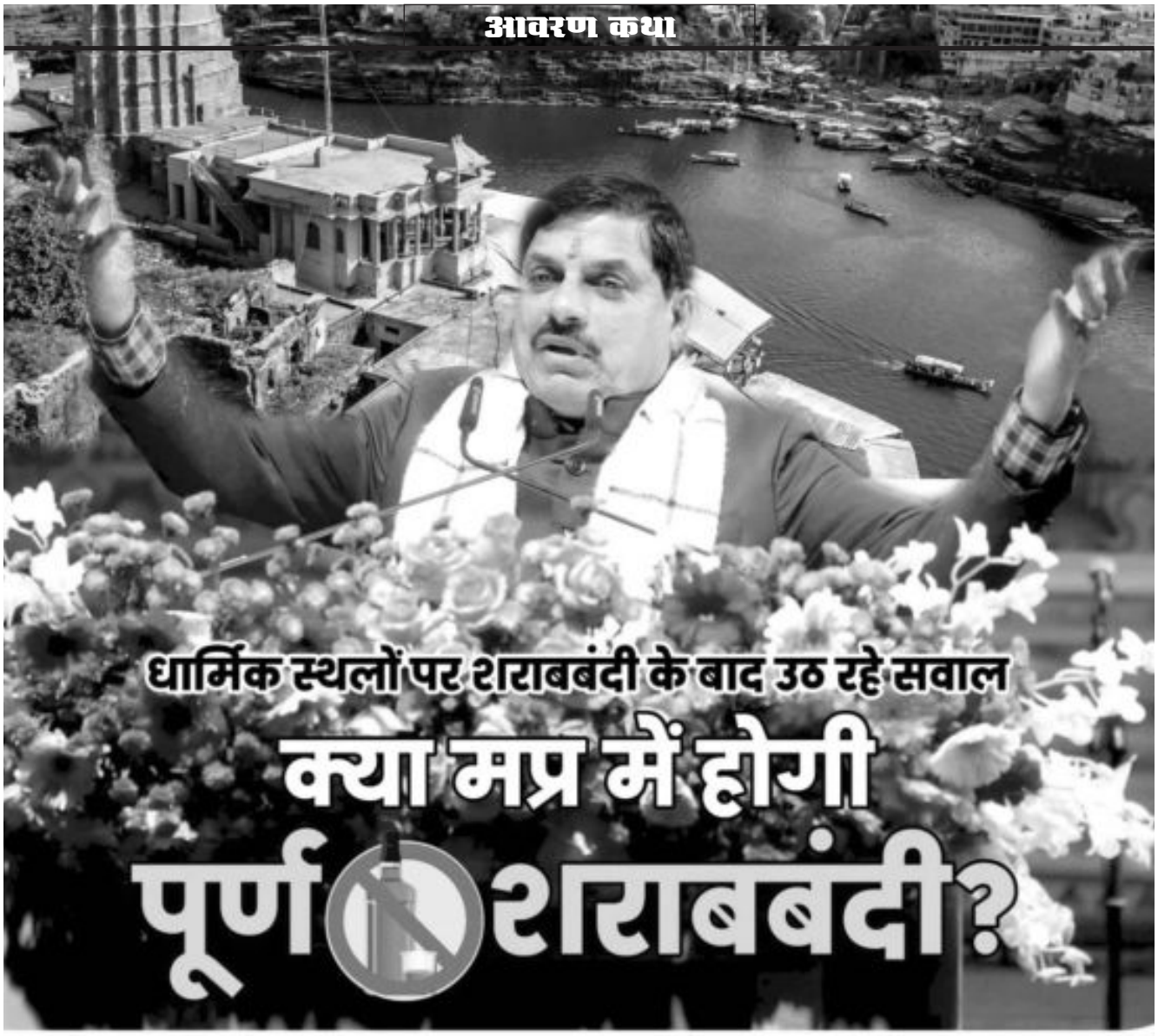

धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के बाद उठ रहे सवाल

क्या मप्र में होगी पूर्ण शराबबंदी?

जो काम उमा, शिवराज और कमलनाथ नहीं कर सके, उसे मोहन यादव ने कर दिखाया

उज्जैन में शराबबंदी के बाद उठा सवाल... काल भैरव को भोग में कैसे चढ़ेगी शराब?

मप्र में शराबबंदी की मांग दशकों से हो रही है। इस दौरान प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने केवल वादे किए हैं। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी कर दी है। यानि जो काम पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं कर सके उसे डॉ. मोहन यादव ने कर दिखाया। सरकार के इस कदम की सर्वत्र सराहना हो रही है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या गुजरात और बिहार की तरह मप्र में भी पूर्ण शराबबंदी होगी।

● राजेंद्र आगाल

मप्र भारत का हृदय प्रदेश है। जैसे मनुष्य के हृदय (हार्ट) का असर उसके पूरे शरीर के संचालन पर पड़ता है, उसी तरह मप्र का भी असर देश के अन्य राज्यों पर पड़ता है। मप्र की इसी विशेषता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। इसके तहत प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की जा रही है। खरगोन जिले के पर्यटन व धार्मिक स्थल महेश्वर में हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। शराबबंदी के तहत इन शहरों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। रेस्टोरेंट और होटलों में शराब परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। मोहन यादव सरकार ने धार्मिक शहरों की मर्यादा बनाए रखने और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न होने पाए, इसके मद्देनजर ये फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से सवाल उठ रहे हैं कि क्या भविष्य में मप्र में पूरी तरह शराबबंदी की जाएगी।

अगर आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो किसी भी राज्य में राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन शराब की बिक्री है। मप्र में हर साल तकरीबन 15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व शराब से होता है। इसको देखते हुए पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने शराबबंदी की बातें तो खूब कीं, लेकिन इस दिशा में कोई आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 धार्मिक शहरों सहित 19 स्थानों पर शराबबंदी की मुहर लगा दी। सरकार के इस कदम से प्रदेश को 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। बंद हुई शराब दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। यह हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी।

आधी-अधूरी शराबबंदी

खास बात ये है कि शराबबंदी केवल धार्मिक शहरों के दायरे में रहेगी। इसके बाहर शराब दुकानों के खोलने में कोई रोकटोक नहीं होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की शराबबंदी की घोषणा के बाद मप्र के आगामी बजट सत्र में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। जिन 17 धार्मिक शहरों में सरकार शराबबंदी करेगी, उनके लिए आबकारी नीति में संशोधन होगा। इसके बाद नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू होगी। गौरतलब है कि मप्र में संपूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लंबे समय तक आंदोलन करती रही हैं। उमा भारती की मुहिम के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बड़े भाजपा नेताओं को कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। लेकिन शराब से मिलने वाला रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि शिवराज सरकार ने उमा भारती की मांग को मानने से इंकार कर दिया था। इसके बाद उमा भारती को संतुष्ट करने के लिए शिवराज सिंह ने कई बार इस प्रकार का बयान दिया कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू की जाएगी। इसके लिए शिवराज ने कई बार कोशिश की लेकिन पार्टी के अंदर इस पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इस पर अमल नहीं हो सका। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार्मिक शहरों में शराब पर बैन लगाने की घोषणा की और इस पर सख्ती से अमल करने का भी संकल्प लिया है।

जानकारों का कहना है कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है। खजुराहो में भी शराबंदी लागू होनी चाहिए। क्योंकि खजुराहो भले ही विश्व पर्यटन स्थल हो लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खजुराहो में श्री मतंगेश्वर का मंदिर है, जहां पूरे प्रदेश के साथ ही उप्र के श्रद्धालु भी आते हैं। वहीं ओंकारेश्वर में शराबबंदी प्रस्तावित है। ओंकारेश्वर खंडवा जिले में आता है। खंडवा में भी दादाजी का मंदिर व आश्रम है। खंडवा के दादाजी के प्रति निमाड़ के साथ ही महाराष्ट्र के लोगों की बड़ी आस्था है। इसलिए इस सूची में खंडवा को भी शामिल किया जाए। वहीं, उज्जैन जिले के तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार का कहना है कि भाजपा सरकार की ये कोरी ढकोसलाबाजी है। दरअसल, इस सरकार के पास एक साल में उपलब्धि दिखाने के नाम पर कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने वरिष्ठ मंत्रियों की खींचतान से परेशान हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की घोषणाबाजी की जा रही है। क्योंकि भाजपा ने जो वादे अपने संकल्प पत्र में किए, उनमें से किसी एक पर भी सालभर के अंदर कोई काम नहीं हुआ। किसानों के मुद्दों पर, महिला सुरक्षा पर ये सरकार बात करने को तैयार नहीं है। वहीं, भाजपा के उज्जैन संभाग के प्रवक्ता सचिन सक्सेना कहते हैं मुख्यमंत्री के इस फैसले की चर्चा राष्ट्रीय पटल पर है। हर कोई इस फैसले की सराहना कर रहा है।

शराब पीने पर रोक नहीं

मप्र के जिन 17 शहरों में शराबबंदी लागू की जा रही है, इस बारे में कहा जा रहा है कि यहां संपूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं होगी। यानि मदिराप्रेमी इन शहरों के बाहर से एक निश्चित मात्रा में अपना शौक पूरा करने के लिए शराब ला सकते हैं। साथ ही घर में बैठकर आराम से शराब पी सकते हैं। मप्र की आबकारी नीति में भी इस प्रकार का प्रावधान है कि परमिशन लेकर तय मात्रा में अपने घर पर शराब का शौक पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार के प्रावधान को लेकर मदिरा प्रेमियों ने शराबबंदी की काट तलाश ली है। शराब के शौकीन इसलिए और निश्चिंत हैं कि शहर की सीमा के बाहर से शराब आसानी से लाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए थोड़ी दौड़-भाग करनी पड़ेगी। जेब भी कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। मप्र के धार्मिक शहरों में शराबबंदी की घोषणा को लेकर लोगों का कहना है कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है। भले ही लोग अपने घर में बैठकर शौक पूरा करें लेकिन शहर में मदिरा की दुकानें नहीं होने से सकारात्मक असर और माहौल देखने को मिलेगा। वैसे भी जिसे पीना है, वह कहीं भी अपनी व्यवस्था कर लेगा। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस फैसले की तारीफ तो बनती है। आपको बता दें कि मदिरा की बिक्री से प्रदेश को बड़ा राजस्व हासिल होता है। राज्य को सीधे मिलने वाले राजस्व में मदिरा से होने वाली कमाई का हिस्सा करीब 15 प्रतिशत है। शराब से होने वाली कमाई को देखें तो सरकार को औसत रूप में प्रतिवर्ष 15200 करोड़ रुपए का राजस्व हर साल प्राप्त होता है। जिसे 2025-26 में बढ़कर 17500 करोड़ रुपए रखने का टारगेट रखा गया है।

2016 से टेंडर नहीं

हर साल सरकार नई आबकारी नीति जारी करती है। नीति में पारदर्शिता को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब की दुकानों के आवंटन के लिए 2016 से टेंडर नहीं किए जा रहे हैं। इससे सरकार को काफी नुकसान पहुंच रहा है। सरकार ठेका पद्धति से शराब दुकानों का आवंटन करती है और हर साल 10-20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के बाद उन्हीं ठेकेदारों को फिर से दुकानें आवंटित कर दी जाती हैं। जानकारों का कहना है कि अगर दुकानों का टेंडर होता तो अच्छी कमाई वाली दुकानों को पाने के लिए ठेकेदारों में प्रतिस्पर्धा होती और सरकार को बड़ा राजस्व मिलता। जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा की कि मप्र के धार्मिक शहरों में शराब पर बैन लगाया जाएगा तो इस घोषणा को लेकर इन शहरों के मदिराप्रेमियों के माथे पर चिंता की

शराब की बिक्री राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य जरिया

किसी भी राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। यही कारण है कि कोई भी सरकार शराबबंदी जैसा निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचती है। दरअसल, राज्य के रेवेन्यू का 15 से 30 फीसदी हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। देश के चंद राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर राज्य शराब की बिक्री पर भारी भरकम टैक्स वसूलते हैं और अपना खजाना भरते हैं। शराब की बिक्री किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य जरिया होती है। आंकड़ों को देखें तो अल्कोहल पर एक्साइज कलेक्शन के मामले में गोवा, उप्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्य आगे हैं। यहां एक्साइज कलेक्शन काफी ज्यादा होता है। रिपोर्ट्स की बात करें तो 2020-21 में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से लभगग 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस मामले में उप्र राज्य सबसे आगे है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उप्र ने एक्साइज ड्यूटी से 41,250 करोड़ का राजस्व वसूला था। एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी शराब पर स्पेशल सेस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबल, रजिस्ट्रेशन जैसे चार्ज लगते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1000 रुपए की शराब की बोतल खरीदता है तो उसे 35 से 50 फीसदी या इससे भी ज्यादा कर देना होता है। यानी जब आप एक हजार रुपए की शराब की बोतल खरीदते हैं तो 350 से 500 रुपए तक सरकार के खजाने में जाते हैं।

लकीरें खिंचनी शुरू हो गईं। शराब के शौकीन आपस में चर्चा करने लगे कि ऐसे कैसे चलेगा? और इसके बाद पड़ताल की गई कि इन शहरों में शराब पर बैन तो होगा लेकिन इसके नियम व शर्तें क्या होंगी। हालांकि अभी नए वित्तीय वर्ष की आबकारी नीति नहीं बनी है। इसलिए ये स्पष्ट नहीं कि इन धार्मिक शहरों में शराबबंदी कैसी होगी? प्रदेश सरकार ने राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए आबकारी नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब सरकार ने कच्ची शराब के शौकीनों के लिए हल्के नशे वाली शराब लॉन्च करने का फैसला किया है। यह शराब आम शराब के मुकाबले सस्ती होगी। वहीं प्रदेश के 38 जिले ऐसे होंगे, जहां पूरे शहर में शराब बिकेगी। इन जिलों में पहले की तरह शराब की बिक्री होगी। वहीं 17 जिलों यानि धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। इसके चलते इन नगरों से 47 शराब की दुकानों को 1 अप्रैल से बंद किया जाएगा। इससे सरकार को 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा।

नई शराब नीति के तहत भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में रेस्टोरेंट रिसॉर्ट और सिविल क्लब के लिए नई कैटेगरी का लाइसेंस ले सकेंगे। इसके लिए सामान्य बार के मुकाबले 50 प्रतिशत फीस देनी होगी। यहां बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक बेचने की अनुमति होगी। किसी भी तरह की हार्ड ड्रिंक नहीं बेची जा सकेगी। नर्मदा नदी के दोनों तटों से 5 किमी की दूरी तक लागू शराबबंदी की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शराब दुकानों का नवीनीकरण मौजूदा वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जाएगा। इसके बाद लॉटरी और फिर ई-टेंडर की प्रक्रिया होगी। जिले की 80 प्रतिशत दुकानों का नवीनीकरण तभी मंजूर किया जाएगा, जब 20 प्रतिशत की वृद्धि पर सहमति होगी। अगर सहमति नहीं बनी, तो ई-टेंडर किए जाएंगे। देसी शराब में अल्कोहल की मात्रा घटाने के लिए 60 डिग्री (अंडर प्रूफ) की नई कैटेगरी शुरू की गई है। यह 180 एमएल के साथ 90 एमएल की नई पैकिंग में भी उपलब्ध होगी। शराब दुकानों पर बिलिंग केवल पीओएस मशीनों के माध्यम से की जाएगी।

20 प्रतिशत अधिक दर पर आवंटन

धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी से जहां लोग खुश हैं, वहीं शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर भी है। प्रदेश में शराब लगभग 20 फीसदी महंगी होगी। शराब पीने के लिए लोगों को अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल सरकार के फैसले के बाद आबकारी विभाग ने

इन शहरों में शराबबंदी

जिन शहरों में शराबबंदी की गई है उनमें चित्रकूट (धार्मिक नगरी, भगवान राम ने वनवास का समय यहां बिताया), मैहर (मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर), दतिया (पीतांबरा माता मंदिर), सलकनपुर (प्रसिद्ध देवी मंदिर), ओरछा (रामराजा सरकार का मंदिर), ओंकारेश्वर (ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग), उज्जैन (महाकालेश्वर मंदिर), अमरकंटक (नर्मदा उद्गम स्थल), मंडला (नर्मदा के प्रसिद्ध घाट), महेश्वर (कई प्राचीन मंदिर), मुलताई (ताप्ती उद्गम स्थल), जबलपुर (प्राचीन नगरी, नर्मदा घाट के लिए प्रसिद्ध), नलखेड़ा (मां बगुलामुखी मंदिर), मंदसौर (भगवान पशुपतिनाथ मंदिर), बरमान घाट और मंडलेश्वर (नर्मदा के प्रसिद्ध घाट), पन्ना (जुगलकिशोर भगवान का प्राचीन मंदिर) और भोजपुर (महादेव का प्राचीन मंदिर) शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके बाद प्रदेश के 38 जिले ही होंगे, जहां पहले की तरह पूरे शहर में शराब की बिक्री होगी। इसके बाद प्रदेश के भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, नर्मदापुरम, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, पांढुर्णा, हरदा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, आगर मालवा, नीमच, रतलाम और शाजापुर जिले ही ऐसे होंगे, जहां पूरे शहर में पहले की तरह शराब दुकानें होंगी। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में करीब 17 शराब की दुकानें हैं। इसके अलावा भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में अब तक 11 दुकान बंद होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई और मैहर क्षेत्र में भी 2 से 3 तक दुकानें हैं। वहीं, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर मंडलेश्वर ओरछा में एक-एक शराब की दुकानें हैं। जबकि अन्य ग्राम पंचायतों में भी शराब की दुकान है। वहीं, प्रदेश में पिछले 20 सालों में दुकानों की संख्या 3605 हो गई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 2151 है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में कुल 1454 दुकानें खुली हैं। मदिरा की बिक्री से प्रदेश को बड़ा राजस्व हासिल होता है। राज्य को सीधे मिलने वाले राजस्व में मदिरा से होने वाली कमाई का हिस्सा करीब 15 प्रतिशत है। शराब से होने वाली कमाई को देखें तो सरकार को औसत रूप में प्रतिवर्ष 15200 करोड़ रुपए का राजस्व हर साल प्राप्त होता है।

20 प्रतिशत अधिक दर पर दुकानों के आवंटन का प्रस्ताव बनाया है। साल 2025-26 में 20 प्रतिशत से अधिक दाम पर शराब की दुकानें नीलाम होंगी। 80 प्रतिशत रकम जमा करने के बाद दुकान फिर से रिन्यू होगी, बाकी की दुकानों के लिए आबकारी विभाग लॉटरी और ई-टेंडरिंग का सहारा लेगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार शराब की खपत बढ़ रही है। इससे सरकार का हर साल 3000 करोड़ से अधिक का खजाना बढ़ रहा है। साल 2024-25 में अब तक 16 हजार करोड़ का रेवेन्यू मिला है। अभी वित्तीय वर्ष को खत्म होने में कुछ महीने और शेष हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार शराब दुकानों के निष्पादन के लिए सबसे पहले ठेकेदारों को नवीनीकरण का अवसर देगी। शराब दुकान/समूह का संचालन करने वाले ठेकेदार 20 प्रतिशत बढ़ी दर पर शराब दुकानों के ठेके ले सकेंगे। हालांकि नवीनीकरण की अनुमति तभी मिलेगी, जब इस प्रक्रिया से आवंटन के लिए 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आवेदन विभाग को मिलेंगे। नवीनीकरण से नहीं उठने वाली शराब दुकानों/समूहों के लिए पहले लॉटरी सिस्टम से और इसके बाद ई-टेंडर से आवंटन किया जाएगा। शराब दुकानों के ठेके में ठेकेदार सुरक्षानिधि के रूप में ली जाने वाली प्रतिभूति राशि अब तक साधारण बैंक गारंटी एवं एफडीआर से जमा कराते थे। चूंकि विगत वर्षों में फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी एफडीआर के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। इसलिए जालसाजी की संभावना को समाप्त करने के लिए आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल के निर्देश पर इस बार प्रतिभूति राशि के रूप में सिर्फ ई-चालान अथवा ई-बैंक गारंटी ही ली जाएगी।

नई आबकारी नीति में कई बदलाव

नई आबकारी नीति में सरकार इस बार बारों की एक नवीन श्रेणी प्रारंभ करने जा रही है, जहां शराब नहीं बल्कि सिर्फ बीयर, वाईन और आरटीडी (रेडी टू ड्रिंक) का विक्रय ही किया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय युवाओं में तेजी से बढ़ रही शराब की लत को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया है। वहीं मदिरा वेयर हाउसों पर सामान्य तालों के स्थान पर बायोमेट्रिक ताले लगाए जाएंगे। बार अब दुकानों को खरीदी गई शराब का भुगतान ऑनलाइन करेंगे। बार को मदिरा प्रदाय हेतु पूर्व में सिर्फ एक दुकान के स्थान पर एक प्राथमिक एवं एक अन्य सेकेंडरी दुकान से मैपिंग की जाएगी। बीयर लेबल का एक मुश्त राशि के भुगतान पर कितनी भी संख्या की लेबल पंजीयन की अनुमति होगी। बारों, बॉटलिंग इकाइयों के सभी प्रकार के निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किए जा सकेंगे। प्रतिबंधित वन क्षेत्र में बार इकाइयों के मापदंडों का सरलीकरण किया जाएगा।

शराबबंदी से 450 करोड़ का नुकसान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मप्र के प्रमुख 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा और उस पर मंत्रिपरिषद की मुहर के बाद इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में शामिल किया जा रहा है। धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी से सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान होगा। हालांकि नए वित्तीय वर्ष में सरकार 20 प्रतिशत उत्पाद शुल्क (ड्यूटी) बढ़ाने जा रही है, जिससे सरकार को विगत वर्ष से लगभग 2 हजार करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य लगभग 16500 हजार करोड़ रखा गया है। शराबबंदी से होने वाले घाटे के बावजूद इस राजस्व लक्ष्य की पूर्ति शराब पर 20 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ाकर की जाएगी। शराब रख सकते हैं या नहीं प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है। हालांकि भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इसके लिए अभियान चला रही हैं। एक अधिकारी ने कहा कि विशुद्ध कानूनी दृष्टि से यह प्रतिबंध शराब की बिक्री बार में बैठकर शराब पीने आदि पर रोक लगाता है। हालांकि, व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोग व्यक्तिगत रूप से शराब रख सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन समूह में नहीं। पूरे मप्र में 3,600 शराब दुकानें हैं, जिनसे हर साल लगभग 15,200 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त होता है। मप्र के आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने पुष्टि की कि 47 दुकानें बंद करने से राज्य को 450 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

प्रदेश में कुल 3601 शराब दुकानें हैं। इनमें से 17 धार्मिक शहरों में करीब 67 दुकानें नए वित्त वर्ष में बंद होंगी। इनका सरकार की कमाई पर कोई असर नहीं होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शराबबंदी की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। समय के साथ मप्र में भी पूर्ण शराबबंदी होगी, पर इसमें वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य धीरे-धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े, इस क्रम में नीतिगत निर्णय हुआ है।

शराब दुकानें बंद होने के बावजूद बढ़ेगा राजस्व

सरकार ने 2024-25 में शराब दुकानों से करीब 14 हजार करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। अगले वित्त वर्ष में लाइसेंस शुल्क में 20 फीसदी बढ़ोतरी से यह आय बढ़कर 16800 करोड़ होने का अनुमान है। इस तरह नए वित्त वर्ष में सरकार की शराब से कमाई 2800 करोड़ रुपए बढ़ सकती है। इसमें से यदि बंद होने वाली दुकानों की कमाई 450 करोड़ रुपए कम कर दी जाए तो भी सरकार को 2350 करोड़ की कमाई ज्यादा होने का अनुमान है। नई आबकारी नीति में शराब दुकानों का निष्पादन रिन्यूअल, ई-लॉटरी और फिर टेंडर प्रक्रिया से किया जाएगा। वर्तमान वर्ष के दुकानों के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिए दुकानों का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। जिलों में 80 प्रतिशत दुकानों के रिन्यूअल के आवेदन मिलने पर ही रिन्यूअल की अनुमति दी जाएगी। 80 प्रतिशत से कम रिन्यूअल के आवेदन मिलने पर दुकानों का टेंडर से निष्पादन किया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने रिन्यूअल के लिए दुकानों

के मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि की थी। सरकार ने प्रतिभूति राशि में पारदर्शिता रखने और जालसाजी रोकने के लिए केवल ई-चालान और ई-बैंक गारंटी को मान्य किया है। साधारण बैंक गारंटी और एफडीआर मान्य नहीं होगी। दरअसल इंदौर में सरकारी गोदाम से शराब लेने के लिए फर्जी चालान का मामला सामने आया था। इसमें 42 करोड़ का घोटाला ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ था। अब इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए ई-चालान को ही मान्य किया गया है। सरकार युवाओं में बढ़ रही मदिरा सेवन की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए बारों की एक नई श्रेणी प्रारंभ करेगी। जहां केवल बीयर, वाइन और आरटीडी (तुरंत पीने योग्य पेय) का विक्रय किया जाएगा। इन बारों में कम अल्कोहल वाली शराब उपलब्ध होगी। अभी बारों में सभी प्रकार की शराब उपलब्ध रहती है। जन सुरक्षा की दृष्टि से अवैध मदिरा को नियंत्रित करने के लिए देशी मदिरा में कम तेजी की (60 डिग्री यूपी) की नई श्रेणी शुरू होगी। देशी शराब 80 एमएल और 90 एमएल की धारिता में उपलब्ध होगी। 80 एमएल के लिए टेट्रा पैक भी शुरू किया जाएगा।

डिजिटल होगा रिकॉर्ड

विदेशी शराब के वेयरहाउस की व्यवस्था को ऑटोमेशन के तहत स्मार्ट वेयरहाउस में बदला जाएगा। शराब के गोदाम में आने और दुकानों तक जाने का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड में रहेगा। इसके अलावा विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें ईडीपी आधारित एड वेलोरम के अनुसार निर्धारित होंगी। सरकार का मानना है कि सस्ती और हल्के नशे वाली शराब उपलब्ध होने से कच्ची शराब की खपत घटेगी। क्योंकि कच्ची शराब न केवल सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे अवैध कारोबार बढ़ता है और शासन का राजस्व चपत लगती है। राजस्थान और उप्र सहित कुछ राज्यों में अंडर प्रूफ शराब पहले से उपलब्ध है। यह बात अलग है कि बाजार में आपेक्षित डिमांड नहीं है। कम नशे के

चलते लोग इस शराब को ज्यादा पसंद नहीं करते। मप्र सरकार इसे और अधिक लोकप्रिय बनाने पर जोर दे रही है। सरकार ने शराब की नई वैरायटी के साथ नए बार खोलने का भी निर्णय लिया है। जहां रेडी टू ड्रिंक यानी कम अल्कोहल वाली शराब उपलब्ध कराई जाएगी। इस शराब में पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुकान से खरीदने के बाद सीधा उपयोग किया जा सकेगा। बार में रेडी टू ड्रिंक के साथ बियर भी मिलेगी।

काल भैरव मंदिर पर स्थिति अस्पष्ट

प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी की घोषणा की है, जिनमें उज्जैन भी शामिल है। इसके बाद उज्जैन जैसे धार्मिक शहर में शराबबंदी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल, उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में शराब का भोग चढ़ाने की परंपरा है, और मंदिर के पास स्थित दो दुकानों से श्रद्धालु शराब खरीदकर इसे भगवान काल भैरव को अर्पित करते हैं। मंदिर के सामने इन दुकानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शराब खरीदते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में उसका सेवन भी करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि धार्मिक शहर में शराबबंदी तो लागू की जाएगी, लेकिन काल भैरव मंदिर में इस नियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक शहर उज्जैन में शराबबंदी के आदेश के बाद भाजपा ने खुशी व्यक्त की है, और कई गृहिणियां तथा अन्य लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाद श्रद्धालु सीधे काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, जहां दोनों सरकारी शराब दुकानों से रोजाना लाखों रुपए की शराब बिकती है। मंदिर के पास दो शराब की दुकानें हैं, जहां से रोजाना करीब 5 लाख रुपए से अधिक की शराब बिकती है। अब देखना यह होगा कि इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी के आदेश को कैसे लागू किया जाएगा।

उज्जैन में शराबबंदी के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि काल भैरव मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों को शराब चढ़ाने के लिए शराब कहां से मिलेगी। भक्तों के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि मंदिर में शराब चढ़ाने की परंपरा रही है। हालांकि, उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह ने इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है और इसे आबकारी नीति के तहत छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला अभी बाकी है और जब आदेश जारी होगा, तब आबकारी नीति के अनुसार ही काल भैरव मंदिर के आसपास शराबबंदी के आदेश पर विचार किया जाएगा। अब यह देखना होगा कि शराबबंदी के आदेश के बाद मंदिर में शराब चढ़ाने की परंपरा कैसे बरकरार रखी जाएगी, या फिर इस पर कोई नया निर्णय लिया जाएगा।

मप्र में अब 90 एमएल बॉटल में मिलेगी देसी शराब

मप्र में मोहन कैबिनेट ने एक अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें शराब दुकानों के आवंटन मूल्य में 20 फीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वहीं देसी शराब को 90 और 180 एमएल की बॉटल में बेचा जाएगा। कैबिनेट में 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने का फैसला भी लिया गया है। कुल 17 स्थानों की 47 शराब दुकानों को एक अप्रैल 2025 से बंद किया जाएगा। इन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इससे सरकार को 450 करोड़ की राजस्व क्षति होगी। महेश्वर में देवी अहिल्या बाई की 300वें जयंती वर्ष के मौके पर कैबिनेट बैठक की गई। नई आबकारी नीति में कहा है कि शराब दुकानों के चालू वित्त वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2025-26 में करके ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। सबसे पहले नवीनीकरण के जरिए दुकानें आवंटित होंगी। इसके लिए 80 प्रतिशत या अधिक राशि जमा करने पर ही नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी। फिर लॉटरी के जरिए और इसके बाद ई-टेंडर के माध्यम से शराब दुकानों का ठेका दिया जाएगा। विदेशी शराब वेयर हाउस की सप्लाई व्यवस्था का ऑटोमेशन किया जाएगा और वेयरहाउस के स्मार्ट वेयर हाउस में परिवर्तित किया जाएगा। विदेशी शराब की ड्यूटी दरों को ईडीपी आधारित एड वेलोरेम किया जाएगा। वहीं शराब के कारोबार में धोखाधड़ी रोकने अब सिर्फ ई-चालान और ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी और एफडी मंजूर नहीं होगी। सरकार ने तय किया है कि युवाओं में शराब की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और शराब को हतोत्साहित करने के लिए नई श्रेणी बार के रूप में शुरू की जाएगी। इसमें सिर्फ बीयर, वाइन और आरटीडी बेची जा सकेगी। इसके लिए हर जिले में आबकारी विभाग के अधिकारी व्यवस्था तय कराएंगे।

अब असली मुद्दा एमएसपी नहीं रहा

पंजाब में जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में जो गतिरोध पैदा हुआ है वह वैसी सुर्खियां नहीं बटोर पाया है जैसी तीन साल पहले हुए किसान आंदोलन ने बटोरी थी। पिछले आंदोलन में किसानों की भागीदारी विशाल पैमाने पर हुई थी, उसे लगभग सभी गैर-भाजपाई दलों का समर्थन मिला था। वह आंदोलन पंजाब-हरियाणा से भी आगे बढ़कर उप्र और मप्र तक पहुंच गया था और उसकी धमक विदर्भ तक महसूस की जा रही थी। 60 साल पहले 1965 में व्यवहार-कुशल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, स्पष्ट वक्ता कृषि व खाद्य मंत्री सी. सुब्रह्मण्यम, आईसीएआर के नवनियुक्त अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन और केंद्रीय कृषि सचिव बी शिवरामन की मंडली ने हरित क्रांति की नींव डाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ अनाज उगाही की व्यवस्था शुरू की। शिवरामन को खास तौर पर इसी काम के लिए नियुक्त किया गया था।

शास्त्री और सुब्रह्मण्यम ने इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी राजनीतिक तथा बजटीय समर्थन दिया। हालांकि, वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी और वित्तीय मामलों में काफी रूढ़िवादी मोरारजी देसाई सरीखे नेता इसके विरोध में थे, जिन्हें डर था कि इससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। स्वामीनाथन ने कृषि अनुसंधान एवं विस्तार व्यवस्था में सुधार करके हरित क्रांति के लिए तकनीकी आधार तैयार किया। शिवरामन ने एमएसपी लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और कृषि मूल्य आयोग (एपीसी, जो अब सीएसीपी है) जैसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कानून बनवाने में बड़ा योगदान दिया। नई सहस्राब्दी वालों को यकीन नहीं होगा मगर यह हकीकत है कि 1960 के दशक के मध्य में हमारी खाद्य स्थिति आयात पर निर्भर बताई जाती थी। हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) अमेरिका के पब्लिक लॉ 480 (पीएल 480) कानून के तहत अमेरिका से आयात किए जाने वाले अनाज पर निर्भर थी। पीएल 480 राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की पहल से बना कानून था। केनेडी का कहना था कि भोजन ताकत है, भोजन शांति है, भोजन आजादी है, भोजन दुनियाभर के उन लोगों की ओर बढ़ा सहायता का हमारा हाथ है, जिनका सद्भाव और दोस्ती हम चाहते हैं। यह वह दौर था जब प्रधानमंत्री शास्त्री ने हरेक भारतीय से आह्वान किया था कि वह देश की खाद्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नवंबर 1965 से सप्ताह में एक शाम उपवास रखे। उस समय भारत की 48 करोड़ आबादी के लिए 9.5 करोड़ टन अनाज की जरूरत थी और उसे 1.2 करोड़ टन अनाज आयात करना पड़ता था।

● **कुमार विनोद**

कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति, इन्दौर, जिला इन्दौर

लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर, दूरभाष क्रमांक 0731-2411223, 2412902

Fax No.:-0731-2412040 & E-mail ID :- apmcindore@gmail.com

-: कृषकों से अपील :-

1. किसान भाई अपनी विक्रित कृषि उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त करें, यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी लिखित सूचना अगले दिन तक मण्डी कार्यालय में अवश्य देवें अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि संबंधित कृषक को भुगतान प्राप्त हो गया है तथा इसके बाद की जाने वाली शिकायत को आपसी लेन-देन माना जावेगा।
2. किसान भाई शासन के नियमानुसार राशि रू. 2 लाख रूपये तक का नगद भुगतान प्राप्त करें तथा शेष राशि RTGS/NEFT से प्राप्त कर सकते हैं। तथा चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त न करें।
3. धोखाधड़ी से बचने हेतु किसान भाई अपनी कृषि उपज को मण्डी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही खुली नीलाम अथवा सौदा पत्रक एप के माध्यम से ही विक्रय करें तथा मण्डी प्रांगण के बाहर किसी भी स्थिति में सीधे विक्रय न करें।
4. किसान भाई मण्डी प्रांगण में कृषक भोजन, कृषक विपणन पुरस्कार, विश्राम गृह तथा शासन की अन्य सुविधाओं का लाभ उठायें।
5. किसान भाई अपने एंड्राइड मोबाईल में गूगल प्लेस्टोर से ई-मण्डी एप इंस्टाल करें।
6. कृषक भाई इस एप में कृषक पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करें। इस हेतु अपना न्यूनतम आवश्यक विवरण स्वयं भरें।
7. किसान लॉगिन में जाकर मण्डी इन्दौर का चयन कर अपनी फसल विवरण दर्ज कर प्रवेश पर्ची स्वयं अपने मोबाईल में ही प्राप्त करें।

सचिव
मण्डी, इन्दौर

अपर कलेक्टर/भारसाधक अधिकारी
मण्डी इन्दौर

मुफ्त रेवड़ी पर सब साइलेंट

गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया... चुनावी माहौल के समय यह व्यंग्य राजनीतिक दलों के लिए खूब चर्चा में रहता है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है तो यहां भी रेवड़ी का मौसम बन रहा है। जो योजनाएं पूर्व में दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी इह रेवड़ी के नाम से ही जनता के बीच लेकर उतरी है। फ्रीबीज पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। पिछले एक साल में केंद्र यह नहीं बता पाई है कि असल में फ्रीबीज है क्या? इधर दिल्ली में मुफ्त वादों की झड़ी लग गई है। वादे करने में सभी पार्टियां आगे चल रही हैं।

फ्री बीज यानी राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाएं (रेवड़ी) मुहैया कराने की कोई कानूनी परिभाषा अभी नहीं है। शायद इसे परिभाषित करना भी जटिल है, इसलिए केंद्र सरकार एक साल से इसका जवाब ढूंढ रही है। दिल्ली की राजनीति से शुरू हुई यह कवायद किसी वायरस की तरह अन्य राज्यों में फैलने लगी है। हकीकत ये है कि देश की राजधानी की प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि बेरोजगारी में सबसे कम दर वाले राज्यों में दिल्ली शुमार है। फिर क्यों जनता को मुफ्त की रेवड़ी की जरूरत है? अर्थशास्त्रियों, कानूनविदों की मानें तो फ्रीबीज के राजनीतिक फायदे का आंकलन दलों ने भी किया। यही वजह है कि दिल्ली के बाद मप्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में चुनाव के दौरान इसका उपयोग किया गया।

दरअसल आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो भारत में वोटर तीन स्तरों का है- उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग या गरीब। इनमें सब कैटेगरी भी है, लेकिन महंगाई, टैक्स, बेरोजगारी की जद्दोजहद और सुविधाओं को जुटाने की कवायद सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को झेलनी पड़ती है। इसमें भी तीन स्तर हैं- उच्च मध्यम वर्ग, सामान्य मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, फ्रीबीज का सीधा फायदा इन्हें भी है। हाशिए पर रहने वालों को निशाने पर रखकर राजनीति का दौर फ्रीबीज के आने पर पुराना हो गया। इसके गलत और सही होने का फैसला या परिभाषित करने का हल सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले से निकल आएगा, लेकिन आंकड़ों की हकीकत ये सवाल उठाती है कि देश की राजधानी में रहने वाली जनता सक्षम है तो उसे फ्रीबीज की क्या जरूरत है। कई विद्वान बढ़ती टैक्स और महंगाई की दरों के चलते इसे जायज करार देते हैं, जबकि एक धड़ा इसके बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणापत्र में राजनीतिक दल सरकार बनने पर सुविधाएं मुहैया कराने का ब्यौरा दे सकती है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि फ्रीबीज की कानूनी परिभाषा तय होना जरूरी है। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर सवाल किए हुए एक साल से ज्यादा समय हो चुका है। देखते हैं केंद्र इस पर अदालत को क्या सुझाती है, लेकिन इस हकीकत को कोई नहीं नकार सकता कि साल 2023-24 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,61,910 रुपए सामने आई थी, जो देश में गोवा और सिक्किम के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय 1,84,205 रुपए से दोगुनी से अधिक है।

यही नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली हैंडबुक पर गौर किया जाए तो राष्ट्रीय राजधानी की प्रति व्यक्ति आय में 7.4 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी का अनुमान भी है। जबकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएल-एफएस) द्वारा गत वर्ष सितंबर में जारी एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर में भी दिल्ली अन्य राज्यों से काफी निचले पायदान पर है। बेरोजगारी दर की टॉप-5 पोजिशन में जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों फ्रीबीज के बयाज समग्र विकास पर गौर करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह तभी संभव है जब मुफ्त की योजनाओं की एक परिधि तय हो और परिधि तय करना सत्ता में मौजूद किसी भी सरकार के लिए आ बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध हो सकती है, क्योंकि चुनाव में जनता के सामने हर पांच साल में जाना ही है। वहीं भाजपा भी अपने संकल्प पत्र में वादों की भरमार कर दी है। वह सत्ता में आएगी तो मुफ्त बिजली, पानी जैसी सुविधाएं दिल्लीवासियों को मिलती रहेंगी। इस चुनावी मैदान की एक और अहम पार्टी

हो रही हैं लोकलुभावन घोषणाएं

केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे उज्वला हो या उजाला। इसमें वितरण की व्यवस्था अच्छी है। इसलिए इन योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई दिया है। मनरेगा योजना कांग्रेस के समय आई थी, इसमें वितरण प्रणाली बेहतरीन है। योजनाओं के वितरण के लिए एक बेहतर प्रणाली बनाने की जरूरत है। राजधानी में बिजली और पानी की मुफ्त सेवा सर्वाधिक चर्चा में है। इसमें भी ऐसे लोग लाभ ले रहे हैं, जो उसका खर्च आराम से वहन कर सकते हैं। उनको इसकी जरूरत नहीं है। बसों में महिलाओं का सफर एकदम मुफ्त है। इसमें भी कैटेगरी बनानी होगी। सरकारी अधिकारी हैं या अच्छे वेतन पर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त बस सेवा की जरूरत नहीं है। इसके लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाने चाहिए और वास्तविक जरूरतमंद लोगों को दिए जाने चाहिए। इससे बजट का भी संतुलन बना रहेगा। अगर सरकार इसमें कुछ कर्मचारियों को जोड़ना चाहती है तो सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। क्योंकि उन्हें इसकी असल में जरूरत होती है। इसमें भी वर्गीकरण करने की जरूरत है। इनका डिजिटलीकरण भी होना चाहिए। जन धन खातों से इसको जोड़ा सा जा सकता है। बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय छात्रों को स्किल करने की जरूरत है। ताकि वह जल्द रोजगार पा सकें।

घोषणाओं से गड़बड़ाएगा बुनियादी सिद्धांत

राजधानी में विकास कार्यों को गति देनी है और उसके लिए बजट चाहिए तो योजनाओं की वितरण प्रणाली बदलनी ही होगी। प्रॉपर्टी एक्ट, एक्साइज नीति में सुधार की जरूरत है। दिल्ली में लाखों रुपए दुकान और घर के किराया देने का कारोबार है। इसमें कैश आदान-प्रदान पर रोक लगनी चाहिए, ताकि सरकार के पास टैक्स आ सके। जितनी व्यवस्था पारदर्शी होगी, सभी लोगों को उसका उतना ही फायदा होगा। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अगर सामाजिक न्याय का बुनियादी सिद्धांत गड़बड़ाएगा तो उससे समस्याएं ही खड़ी होंगी। कोई योजना खराब नहीं है, लेकिन इनके वितरण के तरीके पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर योजनाएं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं, तो इनसे अंत्योदय का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, सभी के लिए यह बात सामान्य रूप से लागू होती है। फ्री सुविधाओं को बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ही अनिवार्य किया जाना चाहिए। वरना करदाताओं का पैसा कभी लोगों के कल्याण के काम नहीं आ पाएगा।

कांग्रेस भी मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य बीमा को लेकर दावा करने लगी है।

मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों में चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी की होड़ सी मची है। जहां एक ओर रेवड़ियों के जरिये राजनीति साधने पर देशभर में बुद्धिजीवी और राजनीतिक जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं और इस प्रवृत्ति को लोकतंत्र व देश के लिए हानिकारक बता रहे हैं, वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इसे सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए आप के इस कदम को उचित ठहरा रहे हैं। यहां आशंका इस बात की है कि सत्ता पाने की कोशिश में राजनीतिक दल एक राह पर ही दिख रहे हैं, तो सरकारी खजाने का क्या होगा? यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में सरकारी खजाने का विकास योजनाओं में इस्तेमाल करने के बजाय रेवड़ियां उपलब्ध कराने में प्रयोग किया जाना उचित है?

क्या रेवड़ियों के कारण जैसे कई अन्य राज्य आर्थिक संकट झेल रहे हैं तो क्या दिल्ली को समय रहते रेवड़ियों से तौबा नहीं कर लेना चाहिए? क्या मिठास के लिए प्रसिद्ध रेवड़ी राजनीति की दुकान में आने के बाद विकास के लिए कड़वी हो रही है? आप नेता व पूर्व उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि एक दशक में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आप सरकार ने शासन का एक नया मॉडल पेश किया है। लेकिन दिल्ली मॉडल क्या है? क्या यह सिर्फ मुफ्त रेवड़ी देने के बारे में है या राष्ट्र निर्माण के लिए कोई बड़ा विजन है। ये सवाल जरूर सभी दिल्ली वालों को परेशान करता है। दिल्ली मॉडल ने पहली बार स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को हाशिये से हटाकर भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। यह मानव पूंजी विकास में निवेश और सभी नागरिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण को प्राथमिकता देता है, जबकि सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करता है। दशकों से विभिन्न राजनीतिक दल विकसित भारत बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देने के दावे करते रहे हैं, फिर भी उनमें से किसी ने भी सत्ता में रहते हुए ऐसा करने की इच्छा नहीं दिखाई।

भाजपा की केंद्र और 20 राज्यों में सरकारें हैं। उनके पास असीमित संसाधन हैं। क्या वे एक भी राज्य में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बदलने का दावा कर सकते हैं? इसी तरह, कांग्रेस ने आजादी के बाद से सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने में विफल रही है। दिल्ली में केवल आप सरकार ही है जिसने भारतीय इतिहास में पहली बार अपने वार्षिक बजट का लगभग 40 प्रतिशत शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है। इसमें लगभग 25 प्रतिशत शिक्षा के लिए और 15 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए है। अन्य सभी भारतीय राज्यों के लिए यह औसत 18-20 प्रतिशत है। नतीजतन, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा है। इसी तरह, 550 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक और 40 अस्पताल किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रदान करते हैं, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो। साथ ही, आप सरकार दिल्ली के आम आदमी, मध्यम और निम्न वर्ग को मुफ्त रेवड़ी देने पर गर्व करती है। ताकि वे सम्मान की जिंदगी जी सकें और महंगाई से राहत पा सकें। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बस सेवा सभी मिलाकर, ये रेवड़ियां दिल्ली के बजट का केवल 7 प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन आम आदमी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारी नजर में सुशासन का मतलब ही यह है कि आम जनता को वह सारी सुख सुविधाएं मिलें जिससे उनका जीवन संपन्न हो और समाज का कल्याण हो। और अगर कोई भी सरकार या राजनीतिक पार्टी कहती है कि आम आदमी को भी मुफ्त में सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, उन पर हर साल ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगना चाहिए या सारे पैसे से बड़े पेंशन को मुफ्त में ऋण या टैक्स में कटौती मिलनी चाहिए, तो फिर वो जनता को मूर्ख समझने की गलती कर रहा है।

सरकार की रेवड़ियों से एक आम आदमी का जो पैसा बचता है, वह उसका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या जरूरत का सामान खरीदता है। इससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है और दिल्ली का बजट फायदे में रहता है। वहीं दूसरी ओर प्रो. संजीव कुमार जो राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं ने बताया कि देश में राजनीतिक पार्टियों की ओर से फ्री सुविधाएं देना या चुनाव से पूर्व उनकी घोषणा नया चलन नहीं है। हां, अब इनका दायरा बढ़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां बिजली, राशन, पानी और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर सर्वाधिक चर्चा में हैं।

● **विपिन कंधारी**

वजूद की जंग

जाहिर है अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वह पहले आप से अपना वोटबैंक वापस ले। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उनका वजूद कांग्रेस की कीमत पर ही है। भाजपा का अपना ठोस वोटबैंक और प्रतिबद्ध समर्थन आधार है। इसलिए अब उन्हें कांग्रेस भी अपना बड़ा दुश्मन नजर आने लगी है। यही कारण है कि उनके निशाने पर कांग्रेस भी है।

कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, जैसा उसने 2013 में किया था। कांग्रेस का आक्रामक रुख 2015 के विधानसभा चुनावों में भी रहा, लेकिन आप की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के बुलंद इतिहास और राजनीति, दोनों को एक साथ बहा ले गई। आप की आंधी में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा। इसके बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उसी आम आदमी पार्टी का साथ दिया, जिसका पूरा वजूद ही उसी के विरोध पर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की अजेय बढ़त पर ब्रेक लगाने के मकसद से 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर आईएनडीआईए के नाम से विपक्षी दलों का जो मोर्चा बना, उसमें तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति को छोड़कर अधिकांश विपक्षी दल शामिल हुए। उनकी समन्वित ताकत ने भाजपा को कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन उसे इतना कमजोर नहीं कर पाई कि भाजपा सत्ता से चूक जाए। इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताते हुए सबसे पहले उनके नेतृत्व पर ममता बनर्जी की ओर से सवाल उठाया गया। उसके बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आईएनडीआईए को लोकसभा चुनावों के लिए बनाया गया था, लिहाजा इसे भंग कर देना चाहिए।

फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव के लिए आईएनडीआईए नहीं है। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में अलग-थलग करने की कोशिश की। यह सच है कि केजरीवाल के साथ से कांग्रेस को फायदे के बजाय नुकसान ही होता रहा है। केजरीवाल की पार्टी अगर आज पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज है तो वह भाजपा की कीमत पर नहीं है। दोनों ही राज्यों में उसने कांग्रेस की न सिर्फ जगह छीन ली है, बल्कि उसका वोटबैंक भी हथिया लिया। गोवा में भी बेशक आम आदमी पार्टी को कम वोट मिले हों, लेकिन वह भी उसी के वोटबैंक का हिस्सा हैं। गुजरात में भी आप को मिले वोट कांग्रेस के वोटबैंक का ही हिस्सा हैं। 2008 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस अगले ही विधानसभा चुनाव यानी 2013 में 24.6 प्रतिशत वोट पाकर तीसरे स्थान पर खिसक गई।

फिर महज दो साल बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोटबैंक 9.7 प्रतिशत पर पहुंच गया और 2020 के चुनावों में उसका जैसे वजूद ही मिट गया। उसे महज 4.26 प्रतिशत वोट मिले। इस बीच आम आदमी पार्टी 54 प्रतिशत से ज्यादा वोट पाकर अजेय दिखने लगी। अव्वल तो कांग्रेस को उसी वक्त सचेत होना चाहिए था। कांग्रेस की राजनीतिक दुश्मन नंबर वन आप को होना चाहिए था, मगर वह उसके साथ ही गलबहियां करने लगी थी। लगता है कांग्रेस समझ गई कि उसका वजूद केजरीवाल के रहते बच नहीं सकता, इसीलिए दिल्ली के चुनावों में वह आप के खिलाफ आक्रामक दिख रही है। जिस शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं, सबसे पहले दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने उसे उजागर किया था। माकन कुछ दिनों पहले केजरीवाल के खिलाफ एक और तथ्य सामने लाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना कोई कारण बताए

एक-दूसरे का बिगाड़ रहे खेल

2023 में जब मप्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी तो उसे सपा के साथ अन्य सहयोगी दलों ने खूब खरी-खोटी सुनाई थी। तब इन दलों ने इसकी अनदेखी करना बेहतर समझा था कि सपा ने 69 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। हालांकि सपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन उसने कम से कम चार सीटों पर कांग्रेस को हराने का काम किया था। कांग्रेस पर यह तोहमत मढ़ी जाती है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में उसने आप के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और यदि वह ऐसा नहीं करती तो शायद परिणाम कुछ और होते। संभव है ऐसा ही होता, लेकिन आखिर कांग्रेस ही सदैव झुकने के लिए क्यों तैयार रहे? यदि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव आप के साथ मिलकर लड़ती तो नतीजा कुछ भी होता, केजरीवाल को कांग्रेस की उपस्थिति वाले एक और राज्य में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिलता। यदि कांग्रेस समाप्तप्राय नहीं होना चाहती तो उसे गठबंधन का सारा बोझ खुद उठाने से बचना होगा, अन्यथा उसे आईएनडीआईए का नेतृत्व करने के भी लाले पड़ेंगे। ध्यान रहे कि उसके नेतृत्व को चुनौती देने का उपक्रम शुरू हो चुका है। आईएनडीआईए की एकजुटता की कितनी भी बातें की जाएं, यह एक अस्वाभाविक गठबंधन है।

रद्द कर दी गई। कहा जा रहा है कि इसके लिए केजरीवाल ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को फोन किया और कांग्रेस को रोकने के लिए गुहार लगाई। आपसी राजनीतिक सहयोग और दबाव की वजह से राजनीतिक दलों को कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। कांग्रेस चूंकि तमिलनाडु की सत्ता में भागीदार है, लिहाजा उसे भले ही चुप रहना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए चुप रहेगी।

राहुल गांधी ने दिल्ली की चुनावी रैली में इसकी शुरुआत कर भी दी है। राहुल ने कहा कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और केजरीवाल आए, तब वह क्या कहते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने, दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन क्या हो रहा है। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि बाहर निकलना मुश्किल है। महंगाई बढ़ रही है। केजरीवाल ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार मिटा दिया? जैसे प्रचार मीडिया में मोदी जी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, वैसी ही रणनीति केजरीवाल जी की भी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। राहुल ने ऐसा कहकर एक तरह से केजरीवाल के मर्म पर चोट की है। उनका वादा पारंपरिक राजनीति के इतर स्वच्छ राजनीति करने, भ्रष्टाचार मिटाने और दिल्ली को चमकाने का था। राहुल ने उनके तीनों ही वादों पर सवाल उठा दिया है। इस हमले से केजरीवाल कितना तिलमिलाए हैं, वह उनके जवाबी हमले से पता चलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल की लड़ाई कांग्रेस बचाने की लड़ाई है और उनकी यानी केजरीवाल की लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। जाहिर है अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वह पहले आप से अपना वोट बैंक वापस ले। केजरीवाल भी जानते हैं कि उनका वजूद कांग्रेस की कीमत पर ही है। भाजपा का अपना ठोस वोटबैंक और प्रतिबद्ध समर्थन आधार है। इसलिए अब उन्हें कांग्रेस भी अपना बड़ा दुश्मन नजर आने लगी है। यही कारण है कि उनके निशाने पर कांग्रेस भी है। इस जंग में कांग्रेस अगर अपना पारंपरिक समर्थन आधार हासिल करती है तो यकीनन दिल्ली विधानसभा के लिए केजरीवाल की राह कठिन होगी।

राहुल गांधी ने दिल्ली की अपनी पहली रैली में भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी पर जैसा जोरदार हमला बोला, उससे उन लोगों की आशंका और बढ़ गई होगी, जो इससे चिंतित हैं कि विपक्षी मोर्चे आईएनडीआईए की दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, लेकिन राहुल ने आप को निशाने पर लेकर बिल्कुल सही किया। यदि कांग्रेस को दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करनी है तो उसे यह प्रदर्शित करना ही होगा कि वह इसके लिए हरसंभव जतन करेगी। निसंदेह दिल्ली में कांग्रेस के पूरे दमखम से लड़ने से आईएनडीआईए की एकजुटता प्रभावित होगी, लेकिन गठबंधन की एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल उसकी ही नहीं है। किसी भी गठबंधन में एकता तभी कायम रह सकती है, जब उसके सभी घटक एक-दूसरे के हित की चिंता करें। आईएनडीआईए में ऐसा नहीं है। इस गठबंधन के घटक पहले दिन से यह कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनावों में केवल उन्हीं सीटों तक सीमित रहे, जहां उसका ठीक-ठाक प्रभाव है। इसी कारण पिछले लोकसभा चुनाव के समय उनकी ओर से यह पहल की गई थी कि कांग्रेस गठबंधन धर्म के नाम पर कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े। ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। केरल में भी वाम मोर्चा ने कांग्रेस प्रत्याशियों और यहां तक कि राहुल के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतार दिए।

पंजाब में आप ने कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं समझी। पंजाब कांग्रेस के नेता भी इसके पक्ष में नहीं थे। अब यदि दिल्ली में भी आप ने कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं समझी और इसके जवाब में कांग्रेस ने उसके खिलाफ मोर्चा खोलना बेहतर समझा तो इसमें गलत क्या है? दिल्ली में कांग्रेस वही कर रही है, जो किसी दल को वहां करना चाहिए, जहां वह कभी प्रमुख दल था। इसका कोई औचित्य नहीं कि गठबंधन की एकजुटता के नाम पर कांग्रेस तो अपनी जमीन पर सहयोगी दलों को विस्तार करने दे, लेकिन जब उसकी बारी आए तो यही दल यह सलाह दें कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं। यदि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों की इस सलाह को मानेगी तो वह तो खत्म ही हो जाएगी। कांग्रेस इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि यदि राष्ट्रीय दल होने के बावजूद उसकी स्थिति क्षेत्रीय दल जैसी हो गई है तो इसका कारण यही है कि उसके कथित सहयोगी दलों ने उसकी राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसमें तनिक भी ढील देने को तैयार नहीं। आईएनडीआईए के सभी घटक कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके ही आगे बढ़े हैं। कांग्रेस ने समय-समय पर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बदले में अपनी राजनीतिक जमीन खो दी, ताकि गठबंधन धर्म का निर्वाह होता रहे। गठबंधन धर्म का एकपक्षीय पालन कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ा है। उसके सहयोगी दल उससे सहयोग लेने को तो तैयार हैं, लेकिन देने को राजी नहीं।

● **इन्द्र कुमार**

कसौटी पर विपक्षी एकता

चुनावी घोषणा के साथ ही दिल्ली में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अपना मजबूत किला बचाने में जुटी है। दशकों से दिल्ली की सत्ता से बाहर भाजपा वापसी के पुरजोर प्रयास में लगी है। 1998 से 2013 तक लगातार तीन बार सत्ता में रही कांग्रेस यहां अपने वजूद को साबित करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखना चाहती। दिल्ली पर आप की पकड़ का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पिछले दो चुनावों में जहां भाजपा दहाई अंकों में नहीं पहुंच पाई, वहीं कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुल सका। हालांकि इस बार परिदृश्य कुछ बदला हुआ है। आप पहली बार कुछ दबाव में और रक्षात्मक दिख रही है। दूसरी ओर, भाजपा और कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को वापस हासिल करने में जुटी हैं। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों यही साबित करने में लगी हैं कि आप का मुकाबला मुख्य रूप से उन्हीं के साथ है। कुछ सीटों पर बिछी चुनावी बिसात से ही मुकाबले की तपिश का अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित, तो भाजपा ने प्रवेश वर्मा को उतारा है। दोनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे होने के साथ ही संसद में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

छिपने का नया ठिकाना ढूंढ रहे नक्सली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद फोर्स नक्सलियों को उनके गढ़ में ही घेरकर मार रही है। सालभर के अंदर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के टॉप नक्सली लीडर्स बस्तर में फोर्स की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में अब तक सीसीएम, एससीएम, डीकेएसजेडसी कैडर के नक्सली मारे जा चुके हैं। इन पर 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम घोषित था। जॉइंट ऑपरेशन के साथ घेरने की नई रणनीति जिलों के साथ ही अब 2 राज्यों के बॉर्डर पर भी अपनाई जा रही है। बस्तर में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसे में बड़े नक्सली लीडर्स छिपने के लिए अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि, पामेड़ एरिया में एक्टिव माओवादी अबूझमाड़ में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर चले गए हैं, जबकि अबूझमाड़ के कुछ बड़े नक्सली लीडर्स गरियाबंद और ओडिशा में अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। बस्तर में पिछले 13 महीनों में फोर्स ने करीब 240 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया है। इनमें बड़े कैडर्स के नक्सली हैं। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 का लगभग सफाया हो गया है। हिड़मा और देवा की टीम भी कमजोर हुई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी की मानें तो बस्तर से काफी हद तक नक्सली बैकफुट पर हैं। नक्सलियों के कोर इलाके तक पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। तेलंगाना, ओडिशा के बड़े कैडर्स भी मुठभेड़ में मारे गए हैं जो पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। साथ ही अंदरूनी और नक्सलियों के आधार वाले इलाकों में सुरक्षाबलों के नए-नए कैंप भी स्थापित किए गए हैं, जिससे नक्सली बैकफुट पर हैं। 20-21 जनवरी को गरियाबंद जिले के जंगल में मुठभेड़ हुई। यहां 27 नक्सलियों के मारे गए। ये इलाका छत्तीसगढ़ और ओडिशा का बॉर्डर है। 16 जनवरी को दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इन 3 जिलों की फोर्स ने पुजारी कांकेर इलाके में 18 नक्सलियों को घेरकर मारा। 3 जिलों के साथ ये इलाका तेलंगाना बॉर्डर से भी लगा हुआ है। इसी तरह 4 अक्टूबर को सबसे बड़ा एनकाउंटर नेंदुर-थुलथुली गांव में हुआ। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की पुलिस ने 38 माओवादियों को मार गिराया था। 16 अप्रैल 2024 को कांकेर और नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर छोटे बेठिया थाना इलाके में 29 माओवादियों को मार गिराया गया।

● रायपुर से टीपी सिंह

अपराध-मुक्त नहीं हो पा रही मायानगरी...

मायानगरी मुंबई दुनिया के हरेक इंसान को अपनी चमक-दमक और काम-धंधे के लिए अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहां की ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें, सपनों जैसी हॉलीवुड की दौलत-शोहरत वाली दुनिया और सदाबहार मौसम को कौन इंज्वाय नहीं करना चाहता। पर जैसे इस एक दुनिया के भीतर कई दुनिया छुपी हुई हैं, वैसे ही मुंबई की इस दुनिया के भीतर और भी कई दुनियां छुपी हुई हैं, जहां चकाचौंध के बीच अपराध और गुंडागर्दी का काला साया भी है।

नववर्ष 2025 की पहली तारीख की सुबह तक इस मायानगरी के बाशिंदों ने खूब जश्न मनाया। पर गए साल की 31 दिसंबर और नए साल की 1 जनवरी की मिलीजुली जश्न की रंगीन रात में मुंबई में न जाने कितने ही अपराध हुए होंगे, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है। पुलिस के पास भी नहीं। यहां पबों, बारों, बाइयों के कोठों में तो हर रात खुलेआम अपराध होते हैं; पर सड़कों-फुटपाथों, गली-कूचों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल जैसी आम बस्तियों से लेकर बड़ी-बड़ी हवेलियों में भी कहीं-कहीं अपराध होते हैं। मुंबई की कई अपराधों की डरावनी घटनाएं अंदर तक झकझोर देती हैं, तो कई घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में आम-सी लगती हैं। पर अपराध तो अपराध है। जो अपराध की तलवार से जख्मी होता है, वो ही इसका दर्द समझ सकता है। अभी चंद दिनों पहले 5 जनवरी को बॉलीवुड की पुरानी मशहूर अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के मुंबई-खार में बने फ्लैट में हुई चोरी में लगभग एक हीरे का नेकलेस, 35,000 रुपए और कुछ अमेरिकी डॉलर के चोरी होने की घटना सामने आई। इस चोरी के अपराध में तो अगले ही दिन 6 जनवरी को मुंबई पुलिस ने समीर अंसारी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, जो अभिनेत्री के फ्लैट की पेंटिंग बीते एक हफ्ते से कर रहा था। फ्लैट में अभिनेत्री पूनम ढिल्लो का बेटा और उसका परिवार रहता है। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने सरकंडा इलाके से दो नाबालिग अपराधियों समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों पर बीते साल चार जगह हुई चोरियों में लिप्त होने का आरोप है। मुंबई पुलिस हर रोज अपराधियों को पकड़ती है; पर मुंबई में अपराध कम नहीं होते।

● बिन्दु माथुर

शेयर मार्केट में प्रॉफिट के बहाने 10 हजार करोड़ रुपए की ठगी

राजस्थान के ठगों ने शेयर मार्केट में प्रॉफिट दिलाने के नाम पर 10 हजार करोड़ रुपए का स्कैम किया है। करीब आठ साल से मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को फंसाने का काम चल रहा था। सबसे ज्यादा ठगी महाराष्ट्र-कर्नाटक में की गई है। ठगी के लिए ऐप श्रीगंगानगर जिला के युवकों ने बनाई थी। मामले में श्रीगंगानगर पुलिस ने अंबिका एन्क्लेव सेकंड निवासी लाजपत आर्य व उसके बेटे दीपक आर्य नायक को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 85 लाख की एक लग्जरी कार, 10 लाख नकद, 6 मोबाइल फोन और 3 सीपीयू जब्त किए हैं। आरोपियों ने श्रीगंगानगर के साथ जयपुर में भी करोड़ों रुपए के बंगले व दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। गैंग के 4 आरोपी फरार हैं। इनमें से एक लाजपत आर्य का बेटा अजय आर्य भी है।

श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों ने कैपमोर एफएक्स नाम से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रखी थी। आरोपी लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के तरीके सिखाते थे। इसके लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के शहरों में सेमीनार कर ग्राहकों को आकर्षित करते। 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग देते और इसके बदले 10 से 15 हजार रजिस्ट्रेशन फीस लेते। फिर ऐप पर निवेश करवाते।

आरोपी सॉफ्टवेयर पर पहले छोटे निवेश के खाते खोलते। उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपए का खाता खोल निवेश करवाते। फिर ग्राहक को 1500 रुपए रिटर्न कर 500 रुपए का मुनाफा देते और मोटे निवेश के लिए तैयार करते। फिर इनको ही और ग्राहक लाने पर कमीशन का लालच देते थे। कटप्पा बाबू चौहान की ओर से दर्ज मुकदमे में आरोपियों का एक मोबाइल नंबर बताया गया है। इस नंबर को भारत सरकार के प्रतिबिंब ऐप पर चेक किया। पता चला कि इस नंबर पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में 5 साइबर फ्रॉड की शिकायतें हैं। पहली शिकायत की छानबीन की तो 75 बैंक खाते सामने आए जिनमें करोड़ों रुपए रकम गई थी।

फ्रॉड के मामले में कर्नाटक निवासी कटप्पा बाबू चौहान के परिवाद पर सदर थाने में आरोपियों पर 4.50 करोड़ रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया। जब सीओ सिटी ट्रेनी आईपीएस बी आदित्य ने जांच की तो यह स्कैम बहुत बड़ा निकला। इस केस से जुड़े दूसरे आरोपियों के दुबई भागने की जानकारी है। इनमें दीपक का भाई अजय आर्य, श्रीगंगानगर निवासी सौरभ चावला, उसकी पत्नी सलोनी चावला, पंजाब के अबोहर के गांव वरियामखेड़ा निवासी बलजीत सिंह, कालियां निवासी कर्मजीत सिंह भी हैं। दावा किया जा रहा है ये पूरा स्कैम 10 हजार करोड़ से ज्यादा का है। एसपी गौरव यादव ने बताया कि इस गिरोह में प्रत्येक सदस्य का पता लगाने को दो एफआईआर दर्ज की हैं। एक पुरानी आबादी में जिसकी एसएचओ ज्योति और दूसरी सदर थाने में जिसकी जांच एसएचओ सुभाष जांच कर रहे हैं। गिरोह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति की जानकारी लेकर कोर्ट में इस्तगासा पेश किए जाएंगे। कोर्ट के आदेश से सभी को सीज करके नीलाम किया जाएगा। इस राशि को पीड़ितों को वापस लौटाकर राहत देंगे।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

अर्थव्यवस्था को बल देगा महाकुंभ

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का केवल धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही विशेष महत्व नहीं है। यह अर्थव्यवस्था को भी एक नई उड़ान देने वाला भी है। इस महाकुंभ में विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। पारंपरिक परंपराओं के अस्तित्व से अनुकूलन करता महाकुंभ समय के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ता दिख रहा है। यूनेस्को द्वारा 2017 में कुंभ मेले को मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद से यह आयोजन विश्व के लोगों के लिए और आकर्षण का केंद्र बन गया है। कुंभ उनके लिए सदैव शोध एवं जिज्ञासा का विषय रहता है कि कैसे बिना निमंत्रण के ही इतने अधिक लोग एक साथ एक जगह एकत्रित हो जाते हैं?

महाकुंभ में डिजिटल तकनीक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर है। यहां करीब 500 पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं गंगा और कुंभ की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए हर घर से एक थैला, एक थाली द्वारा हरित कुंभ में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। महाकुंभ में आधुनिक तकनीक का प्रयोग केवल भीड़ को सुचारू रूप से प्रबंधित करने और सुरक्षा आदि के लिए ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि 11 भाषाओं में एआई संचालित चैटबाट कुंभ सहायक महाकुंभ की समस्त आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करा रहा है।

महाकुंभ को भव्य एवं सुगम बनाने पर सरकार द्वारा लगभग 7000 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इस निवेश से न सिर्फ तीर्थाटन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इसके गुणक प्रभाव से उप्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज की देश के विभिन्न हिस्सों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही भारतीय रेलवे ने 3,000 विशेष ट्रेनों को चलाया है। प्रयागराज में गंगा पर छह लेन का ब्रिज, चार लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। हल्दिया-वाराणसी जलमार्ग को प्रयागराज तक विस्तार दिया गया है। सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए विभिन्न विकास योजनाओं पर व्यय के साथ बड़े-बड़े उद्योगपति भी अपनी-अपनी वस्तुओं की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर रहे हैं।

प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाले इस समागम में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वित्तीय लेनदेन 2.5 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। 2019 के अर्धकुंभ में 1.2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लेनदेन हुआ था। महाकुंभ की एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि डिजिटल लेनदेन पर बहुत अधिक जोर रहेगा। इस डिजिटल लेनदेन से गैर-संगठित क्षेत्र के लोगों की ऋण क्षमता बढ़ने से बैंकिंग क्षेत्र की व्यवस्था भी मजबूत होगी। होटल, रेस्तरां, परिवहन सेवाएं और टूर प्रदाताओं के साथ-साथ क्षेत्रीय हस्तशिल्प, कला और व्यंजनों के लिए बाजार से जुड़े लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

इस आयोजन से स्ट्रीट वेंडर, शिल्पकार और दुकानदार आदि 45 दिनों में ही आठ महीने से अधिक की आय आसानी से अर्जित कर लेंगे। सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के कुंभ में विभिन्न क्षेत्रों में छह लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला था। इस बार यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। उप्र पर्यटन विभाग के अनुसार महाकुंभ की तैयारियों में लगभग 45,000 परिवारों को रोजगार मिल चुका है।

महाकुंभ में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन से भी राज्य और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, दोनों के राजस्व में वृद्धि होगी। महाकुंभ के लिए टूर ऑपरेटरों द्वारा अनेक प्रकार के आकर्षक टूर पैकेज की पेशकश की जा रही है। प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्री केवल महाकुंभ तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आदि अन्य स्थलों पर घरेलू एवं विदेशी मेहमानों के आने से सरकार को लगभग 200 करोड़ से अधिक आय सृजित होने की संभावना है।

कुंभ मेले का सर्वाधिक आकर्षण स्थानीय उत्पादों के स्टाल होते हैं। कुंभ एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा जा सकता है। इसके लिए बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से स्थानीय उद्योगों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

महाकुंभ में लोगों द्वारा गरीबों एवं वंचितों को अन्न एवं वस्त्र के दान का भी विशेष महत्व होता है। श्रद्धालुओं द्वारा संतों को भी दान दिया जाता है। भंडारे जैसी गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति या समाज ही नहीं, बल्कि पूरा देश ही उठ खड़ा होता है। इस सामाजिक चेतना को भले ही आर्थिक मानकों पर न मापा जा सके, पर ये गतिविधियां भी आर्थिक मापदंड का आधार मजबूत करती है। महाकुंभ से देश की जीडीपी में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होने के साथ ही अन्य दूरगामी आर्थिक प्रभाव होंगे, जो उप्र की आर्थिकी को एक ट्रिलियन डॉलर वाले लक्ष्य के और निकट लाएंगे। महाकुंभ में आर्थिक प्रभावों से अधिक सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम् की मूल भावना के और अधिक निकट लाएगा।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

पीके की पॉलिटिक्स

बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर बिहार विधानसभा उपचुनावों में उतरे प्रशांत किशोर (पीके) अपनी जन सुराज पार्टी की करारी हार के बाद युवाओं का कंधा तलाश रहे हैं। बीपीएससी में कथित पेपर लीक-धांधली में उनकी छलांग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उनकी पार्टी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में ख्यात प्रशांत किशोर हर सूरत में विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।

पिछले साल चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी खाता तो नहीं खोल पाई, मगर तीन सीटों बेलागंज, इमामगंज और तरारी में उसके उम्मीदवार तीसरे पायदान पर रहे। इमामगंज का मुकाबला दिलचस्प रहा। वहां राजद उम्मीदवार करीब छह हजार वोटों से हार गया जबकि जन सुराज के उम्मीदवार ने 37 हजार से अधिक वोट हासिल किए। यह वाकई सियासी संदेश देता है। वैसे भी, पीके देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की लहर वाले 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में प्रशांत किशोर अपनी चुनावी रणनीति की कामयाबी का झंडा गाड़ चुके हैं।

आगामी विधानसभा चुनाव में बीपीएससी पेपर लीक मामले ने पीके को युवाओं पर डोरे डालने का एक मौका दे दिया है। पीके जब छात्रों का साथ देने आंदोलन में उतरे तो कांग्रेस और राजद का भी समर्थन मांगा। पटना के गांधी मैदान में गांधीजी की मूर्ति के सामने आमरण अनशन पर बैठे। युवाओं की 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति बनाई, गिरफ्तार हुए। अदालत के सशर्त जमानत लेने से इनकार के बाद शाम तक उन्हें बिना शर्त रिहा करने का आदेश हासिल हो गया। इसके भी अपने सियासी संकेत हैं। उसके पहले जन सुराज पार्टी के गठन की घोषणा करने के पूर्व भी पीके ने पूरे बिहार का दौरा कर पंचायत स्तर तक बैठकें कर लोगों का मन मिजाज टटोला था। जाहिर है, इससे पीके के इरादे और उनकी भावी योजनाओं को समझा जा सकता है।

बीपीएससी मामले में प्रशांत किशोर का आरोप है कि एक-डेढ़ करोड़ रुपए की दर से नौकरियों को बेचा गया है और यह एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। जन सुराज पार्टी ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए 4.83 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था जिसमें 3.25 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर अनियमितता को लेकर परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की आवाज बुलंद की तो बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र सहित 912 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराई, हालांकि आयोग ने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग ठुकरा दी। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई और नीतीश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी पेपर लीक को खारिज कर चुके हैं। आयोग ने प्रशांत किशोर को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भी भेजा है। पेपर लीक बिहार के लिए नया नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआइजी के अनुसार 2012 से अब तक 10 पेपर लीक के मामलों में ईओयू जांच कर रहा है। करीब साढ़े पांच सौ लोगों को इन मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है।

● **विनोद बक्सरी**

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि मंडियों का महत्वपूर्ण योगदान

मप्र में सरकार खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए किसानों को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सरकार की मुहिम को साकार करने में कृषि मंडियों का महत्वपूर्ण योगदान है। 50 वर्षों में मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से किसानों को उनकी कृषि उपज का सही मूल्य दिलाने की दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है।

मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कृषि विपणन के कार्य में नवीनतम तकनीक ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली 24×7 को विकसित कर कृषि उपजों के परिवहन को आसान कर प्रदेश के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को स्वयं ई-अनुज्ञा बनाने की सुविधा प्रदान की है, वहीं एमपी फार्मगेट ऐप के माध्यम से प्रदेश के किसानों को अपनी उपज खेत, खलिहान व घर से उनके तय मूल्य पर विक्रय करने का विकल्प प्रदान कर किसानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास में भागीदार बनाने का सराहनीय प्रयास किया है।

मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने भारत वर्ष में कृषि विपणन सुधारों को अंगीकृत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है तथा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नवाचारों को नेतृत्व प्रदान किया है। कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने हेतु समय-समय पर कृषि विपणन प्रणाली में सुधार किए गए और उपयोगी सुविधाएं, व्यवस्थाएं व अवसंरचनाएं लगातार उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव सफल प्रयत्न किए।

कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किए गए कार्यों और उसकी अनुषांगिक इकाई कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विभिन्न प्रकार से किए जा रहे कार्यक्रमों और प्रयासों की सर्वत्र सराहना हो रही है। कृषि उत्पादन के विपणन में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति रही है। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रावधान वर्ष 1973 में मंडी अधिनियम में किया गया है। वर्ष 1973 से सतत रूप से प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के विकास के लिए मंडी बोर्ड सतत प्रयत्नशील है। मप्र सरकार उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक मंडी स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इस फैसले के तहत प्रमुख 11 कृषि उपज मंडियों में उद्यानिकी फसलों के विक्रय के लिए अलग परिसर बनाए जाएंगे।

– **फीचर**

मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सुविधाएं

- हाईटेक मंडी
- ऑनलाइन ट्रेडिंग लाइसेंस
- ई-मंडी
- ई-अनुज्ञा प्रणाली
- फार्मगेट एप
- इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे
- कृषकों को रियायती दर पर भोजन
- कृषि विपणन पुरस्कार योजना
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

पाक-बांग्लादेश गठजोड़

भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार किस तरह पाकिस्तान से संबंध सुधारने के साथ उसे जरूरत से ज्यादा भाव दे रही है। भारत को यह देखना होगा कि कहीं ये दोनों देश मिलकर उसके खिलाफ कोई ताना-बाना तो नहीं बुन रहे हैं? भारत के लिए यही उचित है कि वह पाक-बांग्लादेश के संभावित गठजोड़ से सावधान रहे। जम्मू के अखनूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताते हुए जिस तरह उससे गुलाम कश्मीर से आतंकी ढांचे को समाप्त करने के लिए कहा, उससे यह साफ है कि वहां अब भी आतंकियों को पाला-पोसा जा रहा है। इसे रक्षा मंत्री ने यह कहकर पुष्ट भी किया कि भारत के पास इसके प्रमाण हैं कि सीमा पार आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के साथ लॉन्च पैड भी कायम हैं। हालांकि पाकिस्तान को इसके पहले भी समय-समय पर चेतावनियां दी गई हैं, लेकिन वह अपने कब्जे वाले भारतीय भू-भाग से आतंकी ढांचे को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं। इस आतंकी ढांचे के कायम रहने का मतलब है सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों का खतरा बने रहना।

पाकिस्तान से लगती सीमा पर तमाम चौकसी के बाद भी सीमा पार से जिस तरह जब-तब आतंकियों की घुसपैठ होती रहती है, वह गंभीर चिंता की बात है। जब पाकिस्तान से लगती सीमा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, तब यह शुभ संकेत नहीं कि बांग्लादेश से सटी सीमा भी भारत के लिए चिंता का कारण बन रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां की सत्ता पर काबिज अंतरिम सरकार की ओर से न केवल भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं, बल्कि सीमा पर बाड़ लगाने के काम में बाधा भी पहुंचाई जा रही है और वह भी तब, जब इसके लिए एक समझौता हो चुका है। इसी समझौते के चलते ही सीमा पर बाड़ लगाने का करीब 80 प्रतिशत काम हो चुका है।

अब बांग्लादेश बाड़बंदी पर आपत्ति जता रहा है और इसी सिलसिले में गत दिवस उसने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। इसके जवाब में भारत ने भी ऐसा ही किया, लेकिन लगता नहीं कि बांग्लादेश सीमा पर भारत के समक्ष जानबूझकर समस्या पैदा करने से बाज आने वाला है। बांग्लादेश बाड़ लगाने के समझौते का सम्मान करने के बजाय उसकी समीक्षा करने की बात कर रहा है। वह उन स्थानों पर कंटीले तारों वाली बाड़ लगाने का खास तौर पर विरोध कर रहा है, जहां से बड़े पैमाने पर घुसपैठ और तस्करी होती है। इस संदर्भ में वह वैसे ही कुतर्क पेश कर रहा है, जैसे सीमा सुरक्षा के भारत के प्रयत्नों पर पाकिस्तान करता रहता है। हैरानी नहीं कि यह बांग्लादेश से पाकिस्तान की हालिया नजदीकी का असर हो। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार किस तरह पाकिस्तान से संबंध सुधारने के साथ उसे जरूरत से ज्यादा भाव दे रही है। भारत को यह देखना होगा कि कहीं ये दोनों देश मिलकर उसके खिलाफ कोई ताना-बाना तो नहीं बुन रहे हैं? भारत के लिए यही उचित है कि वह पाक-बांग्लादेश के संभावित गठजोड़ से सावधान रहे। यह वाकई अजब मंजर है। जिस भारत ने विश्वपटल पर बांग्लादेश के उदय के लिए अपने 1600 सैनिकों की कुर्बानी दी। जिस भारत ने अरबों रुपए खर्च कर इस देश को चलने के काबिल बनाया। उसी बांग्लादेश के उदय के उपलक्ष्य में मनाए गए विजय दिवस पर इस बार फिजाएं भारत विरोधी नारों से गुंजायमान थीं। इसी बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों की याद में सात साल से बनाए जा रहे वॉर मेमोरियल का काम भी रोक दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ निर्मम हिंसा, उनके पूजास्थलों के साथ तोड़फोड़ और तिरंगे के अपमान की खबरें तो पहले ही लगातार आ रही हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से चिंतित करने वाली खबर ये भी कि 53 साल पहले करारी हार के बाद बांग्लादेश (तब के पूर्वी पाकिस्तान) से रुखसत होने वाली पाकिस्तानी आर्मी की फिर बांग्लादेश में एंट्री होने जा रही है। पाक आर्मी के मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए यहां आएगी। शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद आज बांग्लादेश इतिहास के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है, जहां उसके सामने अपने ही अस्तित्व को लेकर गंभीर संकट पैदा हो सकता है।

बांग्लादेश में भारत विरोध का जुनून इस कदर छाया है कि इस प्रक्रिया में कार्यवाहक सरकार के समर्थक अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। वहां हिंदुओं के उपासना स्थलों के साथ तोड़फोड़ के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हिंदुओं से जान बचाने के लिए अपनी पहचान छिपाने तक के लिए कहा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि ऐसे समय में, कोई एक व्यक्ति उम्मीद की लौ जगाता है। आशा की किरण और प्रतिकार का प्रतीक बन जाता है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

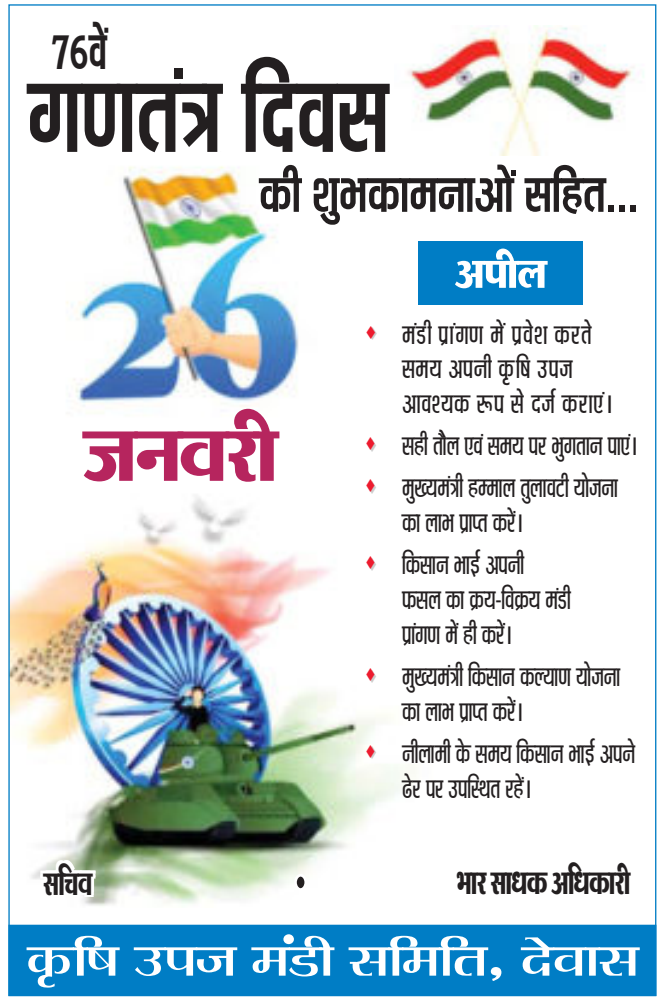

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का असर

भारत सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों में लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले गिरोह सक्रिय हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप का वीजा और वहां नौकरी दिलाने का फर्जी दावा करने वालों ने बाकायदा अपनी दुकानें खोल रखी हैं। ये ठगी की दुकानें हैं लेकिन राज्य सरकारें उनके खिलाफ वांछित कार्रवाई नहीं करतीं।

भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार रहने की बात कहकर वही किया, जो उन्हें करना चाहिए था। यदि अमेरिका अपने यहां अवैध रूप से आए लोगों को वापस करने का फैसला करता है तो भारत को अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन केवल इतने से ही बात नहीं बनने वाली। जहां अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि भारतीय नागरिक उसके यहां न तो अवैध रूप से प्रवेश करने पाएं और न ही उत्पीड़न की झूठी शिकायतों के आधार पर शरण पाने पाएं, वहीं भारत को यह देखना होगा कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं, उन पर लगाम लगे। इसलिए लगे, क्योंकि चोरी-छिपे वहां जाने वाले देश की बदनामी कराते हैं और उन भारतीयों की छवि भी खराब करते हैं, जो वैध तरीके से वहां गए हैं।

भारत सरकार इससे अपरिचित नहीं हो सकती कि अमेरिका जाने की ललक में अवैध तरीके अपनाने वाले लोग ठगी का शिकार होते हैं, कुछ भारत में और कुछ अमेरिका के पड़ोसी देशों में। कई मामले ऐसे आए हैं, जिनमें अमेरिका या यूरोप जाने की कोशिश में लोगों ने अपनी सारी जमा-पूंजी गंवा दी और फिर भी वहां नहीं पहुंच पाए। कुछ तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि वे डंकी रूट कहे जाने वाले बेहद खतरनाक रास्तों से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। भारत सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि में लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले गिरोह सक्रिय हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप का वीजा और वहां नौकरी दिलाने का फर्जी दावा करने वालों ने बाकायदा अपनी दुकानें खोल रखी हैं। ये ठगी की दुकानें हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनके खिलाफ वांछित कार्रवाई नहीं करतीं।

भारत सरकार को ऐसे राज्यों को आवश्यक निर्देश देने चाहिए। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे लोग वैध और सुरक्षित तरीके से विदेश जा सकें। यदि सरकारी एजेंसियां इसमें सहायक बन जाएं तो विदेश में नौकरी का लालच देकर ठगी करने वाले स्वत: हतोत्साहित होंगे। भारत को इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा कि ट्रंप प्रशासन की नई नागरिकता नीति से कहीं वे भारतीय दंपती संकट का सामना न करने पाएं, जो अमेरिका गए तो वैध तरीके से हैं, लेकिन उनके पास वहां की नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं है। इनमें अधिकांश एच-1बी वीजा धारक हैं। ट्रंप ने घोषणा की है कि 20 फरवरी के बाद ऐसे दंपतियों की संतानों को नागरिकता देने की सुविधा खत्म कर दी जाएगी। भारत को अमेरिका को यह बताना होगा कि इस नीति से वही घाटे में रहेगा। इस पर हैरानी नहीं कि खुद अमेरिका में ट्रंप की नई नागरिकता नीति का विरोध हो रहा है।

● कुमार विनोद

उड़ान भरना चाहती हैं लड़कियां...

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्नातक पाठ्यक्रमों में वर्ष 2019 में जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करने वाली महिलाओं की संख्या 5,356 थी। वर्ष 2020 में यह संख्या 6,707; वर्ष 2021 में 6,452; वर्ष 2022 में 6,516 और वर्ष 2023 में 7,509 पहुंच गई। अब वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 7,964 को छू गया। आंकड़ों से पता चलता है कि आईआईटी जैसे क्षेत्र में लड़कियों का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अहम पहचान बनाने वाले आईआईटी संस्थानों में लड़कियों की संख्या बहुत कम, औसतन आठ फीसदी तक ही रहती थी। लेकिन अब यह आंकड़ा 20 फीसदी तक पहुंच गया है।

देश में इस समय 23 आईआईटी संस्थान हैं। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और यहां लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम होना बराबरी की भूमिका निभाने के लिहाज से एक गंभीर मुद्दा बना रहा है। वैसे यहां लैंगिक समावेशी वाला पहलू भी अहम है। लेकिन सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए 2018 में इन संस्थानों में लड़कियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त कोटे की शुरुआत की। इस अतिरिक्त कोटे के तहत इन संस्थानों के स्नातक पाठ्यकमों में तय सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि लड़कियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें जोड़ दी गईं। अतिरिक्त सीटों वाली योजना का असर 2018 के बाद साफ नजर आता है। आंकड़े इसके गवाह हैं। इसका असर अन्य जगहों पर दिखाई देता है। मसलन क्लासरूम बड़े हो गए हैं। नए महिला शौचालयों का निर्माण, छात्रावास आदि। दिल्ली आईआईटी ने महिला वॉशरूमों में सेनेटरी नैपकिन मशीनें लगवाई हैं। रुड़की आईआईटी ने 13 छात्रावास में से चार लड़कियों के लिए आवंटित किए हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 6 करोड़ रुपए कैमरों पर खर्च किए हैं। दिल्ली व बॉम्बे आईआईटी की महिला फुटबॉल टीमें हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन सुरक्षा व अन्य लैंगिक संवेदनशील विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी समय-समय पर किया जाता है। इससे आशा जगती है कि आने वाले वक्त में तकनीकी संस्थानों में लड़कियों की संख्या और बढ़ेगी।

तकनीक, डिजिटल व एआई के युग में अधिक से अधिक लड़कियों को ऐसी शिक्षा की दरकार है। यहां इस बिंदु पर भी गौर करना चाहिए कि लड़कियों की संख्या में इजाफे के पीछे सरकार की 20 प्रतिशत अतिरिक्त कोटे वाली योजना ने तो अहम भूमिका निभाई ही है; लेकिन इसमें ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता, आईआईटी संस्थानों में बढ़ोतरी व संस्थानों द्वारा जारी अतिरिक्त प्रयासों का भी अपना महत्व है। पहले कई मर्तबा माता-पिता आईआईटी में चयन होने के बावजूद घर से दूरी के कारण अपनी लड़कियों को वहां नहीं भेजते थे। लेकिन अब यह बाधा कुछ हद तक कम हो गई है। बॉम्बे आईआईटी ने 2020 में जेईई एंडवास्ड परीक्षा पास करने वाली लड़कियों व उनके अभिभावकों के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी लड़कियां बॉम्बे आईआईटी का चयन क्यों करें। हालांकि लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो यह नारा पूरे देश में इतना गूंजा कि रास्ते में चलने वाली गाड़ियों पर लिखा जाने वाला स्लोगन बन गया। लेकिन क्या आज वास्तव में देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की मंशा में हम सफल हो सके हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के देश पर पिछले 10 साल से ज्यादा के शासनकाल में कोई भी सरकार इस नारे को साकार नहीं कर सकी है, खुद मोदी सरकार भी नहीं। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस सरकारी योजना का लाभ क्या निम्न व मध्यम वर्ग की लड़कियों के लिए उठाना बहुत आसान है। जवाब नहीं होगा। वजह-प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बाजार में जो कोचिंग संस्थाएं उपलब्ध हैं, उनकी फीस का पैकेज बहुत ही अधिक है। यही नहीं उसके बाद अगर लड़की को दाखिला मिल भी जाता है, तो संस्थानों में फीस भी बहुत अधिक है।

● ज्योत्सना

कलियुग के हैरान कर देने वाले रहस्य

कलियुग की आयु करीब पांच लाख वर्षों की बताई गई है। कलियुग का आरंभ कई हजार वर्षों पहले ही हो चुका है लेकिन, क्या आप जानते हैं कलियुग का आने वाला समय और भी भयावह होने वाला है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने घोर कलियुग से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

कलियुग के बारे में कई वेदों और पुराणों में वर्णन किया गया है। कलियुग को लेकर भविष्यपुराण से लेकर विष्णुपुराण तक सभी जगह जानकारी दी गई है। लेकिन, क्या आप जानते हैं रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कलियुग का ऐसा वर्णन किया है, जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस तरह से कलियुग का वर्णन किया है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। कलियुग जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा पाप, घमंड, दुर्राचार जन्म लेगा। आइए जानते हैं रामचरितमानस के अनुसार, कलियुग का आने वाला समय कैसा होगा। क्यों गृहस्थ लोगों को धन की कमी होगी। धन के लिए लोग क्या करेंगे। जानें रामचरित मानस से। रामचरित मानस में, तुलसीदास जी ने बताया है कि कलियुग जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा लोग वही रास्ता अपनाने लगेंगे जो उन्हें पसंद आएगा। चाहे वह फिर सही हो या गलत। जो लोग अपनी तारीफ खुद करेंगे और जो लोग धर्म की बातों को अपने हिसाब से बताएंगे। वह खुद को पंड़ित कहेंगे। अहंकारी और दंभी लोग भी अपने आप को संत कहने लगेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में आगे बताया है कि उन्होंने कलियुग का ऐसा स्वरूप देखा है कि कलियुग में ऐसे लोग ज्ञानी कहलाएंगे जो पराई स्त्री से आसक्त रहेंगे, जो दूसरों के साथ कपट करेंगे। जिसका स्वभाव चतुर होगा। वही ज्ञानी माना जाएगा। कलियुग में स्त्रियों के साथ बहुत गलत होगा। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकालने के लिए तत्पर रहेंगे और पतिव्रता को छोड़कर अपने घर में किसी अन्य को ला रखेंगे। कलियुग में पुत्र तब तक अपने माता-पिता को मानेगा जब तक की उसकी शादी नहीं हो जाती है। कलियुग में पुत्र को अपने घर से ज्यादा अपना ससुराल प्यारा होगा।

रामचरित मानस के अनुसार, कलियुग में आने वाले समय में स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे हो जाएंगे की वह थोड़े से लाभ के लिए ही किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़े से लाभ के चक्कर में स्त्री और पुरुष ब्राह्मण और गुरु तक की हत्या से नहीं हिचकेंगे। कलियुग में ऐसे साधु संन्यासी होंगे जो स्वयं को महान बताने के लिए बड़ी-बड़ी जटाएं रखेंगे। जिनके बड़े-बड़े नख होंगे। वेद मार्ग को त्यागकर खुद को बड़ा तपस्वी बताएंगे। तुलसीदास जी के अनुसार, कलियुग में उसी का उपकार होगा और उसे ही सम्मान मिलेगा जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाला होगा। साथ ही जो जितना झूठ बोलेगा वह उतना बड़ा वक्ता बनेगा। जो दूसरों का अहित करेगा वह ही सम्मान के योग्य माना जाएगा।

कलियुग जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे लोग धन की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। धन कमाने के लिए लोग कोई भी मार्ग अपनाएंगे चाहे वह सही हो या गलत। कोई किसी से रिश्ते-नाते नहीं निभाएगा। कलियुग में उसी को गुणवान बताया जाएगा जो झूठ बोलेगा। हंसी दिल्लगी करेगा। रामचरितमानस के अनुसार, कलियुग में संन्यासी और तपस्वी भी पैसों के पीछे भागेंगे। वह अपने घरों को खूब धन खर्च करके सजाएंगे। जबकि गृहस्थ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें धन कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।

● ओम

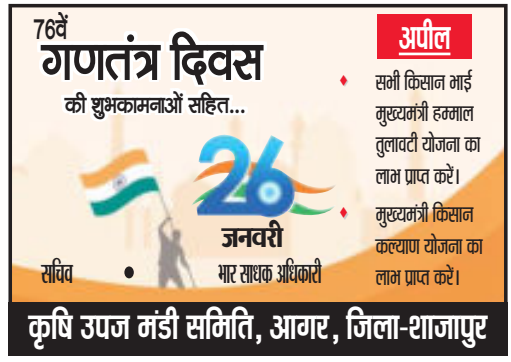

टेढ़ी खीर होना

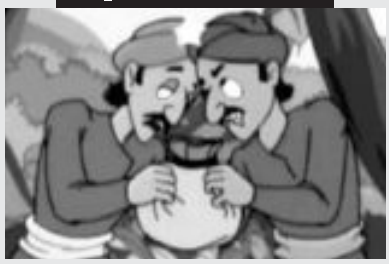

टेढ़ी खीर होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है। टेढ़ी खीर होना, इस मुहावरे का प्रयोग हम अक्सर अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत मुश्किल कार्य होना अर्थात् जब कोई कार्य करने में बहुत कठिनाई आ रही हो तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।

टेढ़ी खीर होना मुहावरे से जुड़ी कहानी कुछ इस प्रकार है- बहुत समय पहले की बात है दो दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त लंगड़ा था और दूसरा दोस्त अंधा था। दोनों दोस्त बहुत गरीब थे। दोनों मित्र प्रतिदिन शाम के समय मिला करते थे और एक-दूसरे के साथ सुख-दुख को साझा किया करते थे। एक बार लंगड़े दोस्त के घर में खीर बनी। लंगड़े व्यक्ति को खीर बहुत अच्छी लगी और शाम को जब वह अपने अंधे मित्र से मिला तो उससे बोला- भाई आज मैंने खीर खाई है, खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी खाकर मुझे ऐसा लगा मानो स्वर्ग की अनुभूति हो गई हो।

अंधे व्यक्ति ने पहले कभी खीर नहीं खाई थी, ना ही खीर के बारे में सुना था। लंगड़े व्यक्ति की बात सुनकर अंधे व्यक्ति के मन में भी खीर को जानने की इच्छा हुई। अंधे व्यक्ति ने लंगड़े से पूछा- भाई यह खीर क्या होती है। लंगड़े व्यक्ति ने उत्तर में अंधे से ही पूछा- क्या तुमने कभी खीर नहीं खाई है?

अंधे व्यक्ति ने बतलाया कि उसने पहले कभी खीर नहीं खाई है ना ही खीर के बारे में सुना है। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर लंगड़ा व्यक्ति बोला- भाई खीर सफेद होती है, मीठी होती है, मुलायम होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है।

लंगड़े की बात सुनकर अंधा फिर पूछता है- यह सफेद रंग कैसा होता है? लंगड़े ने बतलाया कि दूध सफेद होता है दांत भी सफेद रंग के होते हैं। अंधे को यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह लगातार लंगड़े से प्रश्न किए जा रहा था। नेत्रहीन व्यक्ति को समझाना अब लंगड़े व्यक्ति के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी थी। वह सोच रहा था कि इसे मैं कैसे समझाऊं, तभी उसे एक सफेद बगुला दिखाई दिया। लंगड़ा उस बगुले को पकड़कर अंधे व्यक्ति के पास ले आया और उसके हाथों में रखते हुए बोला- इस बगुले की तरह खीर भी सफेद और मुलायम होती है।

अंधे व्यक्ति ने अपने पास रखे हुए बगुले पर हाथ फेरा उसे बगुला बहुत ही नरम महसूस हुआ, वह कभी बगुले के ऊपर हाथ फेरता कभी उसके दांये-बांये छूकर देखता था। उसे बगल टेढ़ा-मेढ़ा समझ में आ रहा था तभी अंधा व्यक्ति मुस्कुरा कर बोला- अच्छा तो तुम्हारी खीर इस तरह टेढ़ी-मेढ़ी होती है। लंगड़ा व्यक्ति अंधे को संतुष्ट कर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला हां खीर टेढ़ी होती है तभी से किसी मुश्किल कार्य करने के लिए टेड़ी खीर होना कहावत प्रचलित हो गई है।

- अनाम

कितनी भारी शाम

कितना चौड़ा पाट नदी का
कितनी भारी शाम
कितने खोए-खोए से हम
कितना तट निष्काम
कितनी बहकी बहकी-सी
दूरागत वंशी टेर
कितनी टूटी-टूटी-सी
नभ पर विहंगों की फेर

कितनी सहमी सहमी-सी
क्षिति की सुरमई पिपासा
कितनी सिमटी-सिमटी सी
जल पर तट तरु अभिलाषा

कितनी चुप-चुप गई रोशनी
छिप-छिप आई रात
कितनी सिहर-सिहर कर
अधरों से फूटी दो बात
चार नयन मुस्काए
खोए भीगे फिर पथराए
कितनी बड़ी विवशता
जीवन की कितनी कह पाए।

- सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

दिग्गजों पर चला बीसीसीआई का हंटर

हाल के वर्षों में जिस तरह खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट को छोड़कर टी-20 का रुख कर रहे हैं उससे इसकी लोकप्रियता को नुकसान हो रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पूर्व सचिव जय शाह ने घोषणा की थी कि जो खिलाड़ी प्रत्येक सत्र में कम से कम सात टेस्ट मैच खेलते हैं उनकी मैच फीस 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 45 लाख रुपए करने का ऐलान किया था। यह राशि रिटेनर फीस के इतर होगी जो खिलाड़ी को सालाना केंद्रीय अनुबंध के अंतर्गत मिलती है। बीसीसीआई ने यह कदम तब उठाया था जब एक ओर जहां टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता में भारी कमी आंकी गई थी, वहीं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे कुछ खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। इन खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने के बजाय अपनी आईपीएल टीमों के साथ प्रशिक्षण जारी रखा था। जिसके बाद बीसीसीआई ने सख्त रुख अपनाकर टेस्ट खिलाड़ियों को यह सौगात दी थी। लेकिन अब बीसीसीआई ने उन दिग्गज खिलाड़ियों पर भी हंटर चलाया है जिनका हालिया प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और जिनको घरेलू मुकाबले में न खेलने को लेकर छूट दी गई थी।

बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी हो उसे रणजी ट्रॉफी में खेलना ही होगा। अगर खिलाड़ी इसका पालन नहीं करते हैं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। खासकर ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और ऋषभ पंत के खराब प्रदर्शन को लेकर काफी आलोचना के बाद क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया है। रोहित शर्मा की बात करें तो वे ऑस्ट्रेलिया ही नहीं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। सीरीज में चार टेस्ट मैचों में 3, 9, 10, 3, 6 रन बनाए थे।

सिडनी में हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रणजी में खिलाड़ियों के खेलने पर जोर देते हुए कहा कि मैं हमेशा चाहता हूं कि हर कोई घरेलू क्रिकेट खेले। घरेलू क्रिकेट को भी हमें उतना ही महत्व देना चाहिए। अगर आप घरेलू क्रिकेट को महत्व नहीं देते, तो आपको टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह के खिलाड़ी की जरूरत है, कभी नहीं मिलेंगे। हर खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट खेलने चाहिए। यह न केवल खिलाड़ियों को अपने खेल को सुधारने में मदद करता है, बल्कि टीम के लिए मजबूत विकल्प भी तैयार करता है। अगर घरेलू क्रिकेट को महत्व नहीं दिया गया तो हमारी टीम को वह खिलाड़ी नहीं मिलेंगे जो कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन कर सकें। इसी का परिणाम है कि कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बाद अब ऋषभ पंत ने भी खुद को रणजी ट्रॉफी के लिए उपलब्ध बताया है। जहां तक बात है रोहित शर्मा की तो उन्होंने मुंबई टीम प्रबंधन को इस बात की जानकारी दी है कि वह वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले रणजी ट्रॉफी के प्रैक्टिस सेशन में शामिल होंगे। मुंबई टीम अपने अगले रणजी ट्रॉफी लीग राउंड के लिए सेंटर-विकेट प्रैक्टिस सेशन का उपयोग करेगी। जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई की टीम को अपने घर पर खेलना है।

हालांकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की मानें तो रोहित मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में शामिल होंगे लेकिन यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि वह जम्मू-कश्मीर के खिलाफ अगला रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे या नहीं। लेकिन उनके इस फैसले ने घरेलू टूर्नामेंट में उतरने के संकेत दिए हैं। रोहित शर्मा के घरेलू क्रिकेट खेलने की बात करें तो उन्होंने मुंबई के लिए आखिरी बार 2015 में उप्र के खिलाफ रणजी मुकाबला खेला था। रोहित ने भारतीय टीम के लिए टेस्ट में साल 2013 में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 67 टेस्ट मुकाबलों में कुल 4 हजार 301 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं।

● आशीष नेमा

आमिर खान की डाई हार्ट फैन हैं ये टॉप एक्ट्रेस... विनोद खन्ना पर थीं फिदा

जितेंद्र की पत्नी बनकर मचा दिया था तहलका

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस में शुमार मौसमी चटर्जी ने महज 15 साल की उम्र में शादी रचा ली थी। उस दौर की वह पहली एक्ट्रेस रहीं जो शादी के बाद लीड रोल में नजर आती थीं। मौसमी का मानना था कि विनोद खन्ना से हैंडसम एक्टर उस वक्त कोई था ही नहीं, जबकि अब आमिर खान उनके फेवरेट हीरो हैं।

टैलेंटेड एक्ट्रेस में शुमार मौसमी चटर्जी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। अपने दौर में उनकी जितेंद्र संग जोड़ी काफी हिट थी। टीन एज में ही उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद वह एक्टिंग की दुनिया में अपनी धाक जमाने में कामयाब रही थीं। अपने दौर में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं। मौसमी चटर्जी ने महज 10 साल की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। फिल्म बालिका बधू से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। ये एक बंगाली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों फिल्मों में काम किया था। मौसमी की शादी मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत राव के बेटे जयंत मुखर्जी से हुई थी। 17 साल की उम्र में तो वह मां बन चुकी थीं।

यूं तो मौसमी चटर्जी देवानंद की दीवानी थीं, लेकिन कपिल शर्मा के शो में उनसे सवाल किया गया कि उस दौर में सबसे हैंडसम एक्टर कौन हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा- विनोद खन्ना, उनके जैसा हैंडसम उस दौर में कोई नहीं था।

जितेंद्र संग काफी पसंद की गई जोड़ी

एक इंटरव्यू में मौसमी से पूछा गया कि अब के स्टार्स में से उनका फेवरेट कौन हैं। उन्होंने कहा- यूं तो सभी अपनी जगह सही हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आमिर खान का काम बहुत पसंद आया। वह जो रोल करते हैं सभी अच्छे लगते हैं। अपनी एक्टिंग के अलावा मौसमी चटर्जी अपने चुलबुले स्वभाव को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। वह जहां भी होती हैं खूब मस्ती करती हैं। कपिल के शो में उन्होंने कपिल शर्मा तक की बोलती बंद कर दी थी। एक फिल्म में तो उन्होंने सनी देओल की ही क्लास लगा दी थी। बता दें कि साल 1980 में आई फिल्म मांग भरो सजना में तो वह जितेंद्र संग नजर आई थीं। इस फिल्म में उनकी जोड़ी जितेंद्र संग काफी पसंद की गई थी। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म में रेखा भी नजर आई थीं। मौसमी ने फिल्म में जितेंद्र की पत्नी की भूमिका निभाई थी।

छोटे कद वाले बड़े साहित्यकार

वह साहित्यकार हैं। साहित्यकार होने के नाते उन्हें स्वयं को विशिष्ट समझने का अधिकार प्राप्त है। वह आम जनता पर लिखने का दावा करते हैं, लेकिन विशिष्ट होने के नाते उनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है।

स्वयं को विशिष्ट समझने के कारण उनका लेखन भी विशिष्ट लोग ही समझ पाते हैं। वह बड़े साहित्यकार तो हैं ही, उनका डील-डौल भी बड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका कद बहुत छोटा है। वह स्वयं भी यह नहीं समझ पाए हैं कि डील-डौल बड़ा होने के बावजूद उनका कद छोटा क्यों है।

वह चाहते हैं कि वह जितने बड़े साहित्यकार हैं, उनका कद भी उतना ही बड़ा हो जाए, लेकिन वह कद बढ़ाने की जितनी कोशिश करते हैं, उनका कद उतना ही छोटा होता जाता है। हारकर उन्होंने अपना कद बढ़ाने की कोशिश छोड़ दी है।

अब उनका सारा ध्यान रचना का कद बढ़ाने पर है। इस समय उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनकी रचना उनके कद जितनी छोटी न हो जाए। रचना का कद बढ़ाने के लिए वह दिन-रात एक किए हुए हैं।

अति उत्साह में एक दिन उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर चिपका दिए कि वह अंतिम समय तक रचना का कद बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। तब जाकर शहर की साहित्यिक जमात को पता चला कि रचना का भी कोई कद होता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समीक्षकों को उनकी यह मेहनत दिखाई ही नहीं देती है।

साहित्यकार जी ने यह मान लिया है कि वह विशिष्ट और बड़े साहित्यकार हैं, इसलिए उनकी रचना तो स्तरीय होगी ही। जब प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ऐसा विश्वास साथ हो तो रचना के स्तरीय न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

आजकल विश्वास का बड़ा टोटा है। लाख कोशिश करो, लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं होता। साहित्यकार बनते ही विश्वास अपने आप हमारे साथ हो लेता है। इस अटूट विश्वास के कारण ही उन्हें यह पक्का भरोसा हो गया है कि वह जो लिखते हैं, हमेशा स्तरीय ही होता है।

फलस्वरूप इस बात पर माथापच्ची करने से तो छुट्टी मिल जाती है कि रचना स्तरीय है या नहीं? इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि रचना के स्तर पर कभी बात ही नहीं होती है। लिहाजा सुबह-शाम रचना करने का हौंसला दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करता रहता है।

साहित्यकार जी ने अपने हौंसले के आधार पर कई किताबें लिख मारी हैं। छपते ही वह मित्रों को डाक से किताब भेजनी शुरू कर देते हैं। जब यह काम खत्म हो जाता है तो स्थानीय स्तर पर मित्रों को अपनी किताब बांटने निकल पड़ते हैं।

किताब बांटकर जब वह घर आते हैं तो उन्हें असीम संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्टि की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि रात को नींद भी नहीं आ पाती है। दूसरे दिन सुबह उठते ही वह मित्रों को फोन कर किताब पर प्रतिक्रिया मांगनी शुरू कर देते हैं।

जब कुछ मित्र उनका फोन नहीं उठाते हैं तो उनका पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वह ऐसे लोगों को साहित्य का दुश्मन घोषित कर देते हैं। कुछ ऐसे भले जीव भी होते हैं, जो सारी रात घोड़े बेचकर सोते हैं और जब उनसे किताब पर प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो बड़े ही गर्व से बताते हैं कि उन्होंने सारी रात जागकर किताब पढ़ी है।

ऐसी अद्वितीय किताब उन्होंने आज तक नहीं पढ़ी है। यह सुनकर बड़े वाले साहित्यकार और बड़े हो जाते हैं। हालांकि कई दिनों तक खुशी से उछलने के बावजूद उनका कद बड़ा नहीं होता है।

साहित्यकार जी जब अपनी किताब पर विभिन्न नामों से स्वयं समीक्षा लिखकर पत्रिकाओं में छपवाने की जी-तोड़ कोशिश करते हैं तो उनके सामने राजनीति के घाघ खिलाड़ी भी फीके लगने लगते हैं।

एक दिन साहित्य के एक नासमझ पाठक ने जब उनकी किताब पढ़कर कहा कि मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि आपकी रचना क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने पाठक को पकड़कर वहीं बैठा लिया और उसे रचना का मर्म समझाने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पाठक नींद के आगोश में समा गया।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

HAPPY Republic Day

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com